हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 2008

खण्ड – 1, अंक – 6

अधिकृत विवरण

विषयसूची

शुक्रवार, 14 मार्च, 2008

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नो के लिखित उत्तर	(6)27
घोषणा–	(6)36

विधायको की विधान सभा से सदस्यता रद्द करने बारे	(6)36
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(6)36
अतिविशिष्ट व्यक्ति का अभिनन्दन	(6)55
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(6)55
नियम 22(2) के अधीन प्रस्ताव	(6)60
वर्ष 2007–06 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना	(6)61
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(6)61
वर्ष 2007–06 के लिए अनुपूरक अनुमानो की मांगों (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान	(6)61
अतिविशिष्ट व्यक्ति का अभिनन्दन	(6)66
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(6)66
बैठक का समय बढाना	(6)78
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(6)79

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार 14 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सवाल–जवाब होंगे।

Status of Fly-over at Karnal

***911. Smt. Sumita Singh:** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the present status of fly-over from Mall Road to Ram Nagar Basti Karnal togetherwith the time by which the said fly-over is likely to be completed ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, the work on road over Bridge on Karnal Kachhwa road from Mall Road to Ram Nagar Basti, Karnal is in progress and physically 75% work stands completed.

श्रीमती सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि क्या वे बतायेगे कि जो ये पलाई ओवर बन रहा है जब यह सैक्शन हुआ था उस समय इसके साथ और कितने पलाई ओवर सैक्शन हुए थे। क्या वे सभी पलाई ओवर भी कम्पलीट हो गये हैं या वे अभी भी

इनकम्पलीट है। इसके अतिरिक्त इन पलाई ओवर के साथ जो साईड लेन्ज हैं क्या उनको भी चौड़ा किया जायेगा। इसके साथ ही जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब मे लिखा है कि The work is likely to be completed by 30-6-2008. तो क्या इसमे अभी भी आपको कोई डाऊट है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, सदन मे कल भी इस प्रकार की एक बात आई थी कि पिछली जो श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी उसने इस ब्रिज को सन 2002 मे अप्रूव किया था और उसका शिलान्यास पत्थर भी रखा जा चुका था लेकिन उसके बाद मे न तो इस पुल के कस्ट्रक्शन के लिए एक भी ईट लगाई और न ही इसकी लागत के बारे मे बजट मे कोई प्रावधान ही किया गया। सत्ता मे आने के बाद इस सरकार द्वारा 23—8— 2005 को इस पुल के निर्माण का कार्य अलॉट किया गया। इस पुल का कुछ पोर्शन रेलवे डिपार्टमैंट द्वारा भी बनाया जाना था और वहां स्थित मील रोड पर रहने वाले जो लोग थे वे भी इसकी अलाईनमेट को चेंज करवाना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमत्री महोदय से भी मुलाकात की थी। इन कारणो से इसके निर्माण मे थोडा सा विलम्ब हो गया क्योकि जो चीज एक बार अप्रूव हो जाती है उसको दोबारा चेज करने मे कुछ समय तो लगता ही है। इसके अतिरिक्त दूसरी समस्या यह रही कि जो उस वक्त कट्रैक्टर था वह ठीक ढग से काम नहीं कर रहा था इसलिए हमने उसके काम को 29— 11 — 2007 को टर्मिनेट कर

दिया था। लेकिन जब उसने दोबारा रिप्रेजैंटेशन दी तो हमने यह निर्णय लिया कि अगर यह कोर्ट में चला गया तो मामला ओर लम्बा हो जायेगा और इस पुल के निर्माण का कार्य ओर डिले हो जायेगा क्योकि लिटिगेशन मे मामला काफी लम्बा हो जाता है, इन सब बातो को ध्यान मे रखकर हमने उसी कट्रैक्टर को काम कम्पलीट करने की परमीशन दे दी और साथ ही 25 लाख रुपये की बैक गारन्टी उससे ले ली गई और कट्रैक्टर को कहा गया कि अगर वह 30 जून, 2006 तक अपना कार्य पूरा नहीं करेगा तो उसकी सिक्योरिटी फोरफीट कर दी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप अब उसने अपना काम पूरे जोर–शोर से शुरू कर दिया है। जो आपने लाइकली वाली बात कही है उसके बारे मे मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो रेलवे डिपार्टमैट का काम है उस रार 1. 47 करोड की लागत आयेगी। वह काम भी तेजी से चल रहा है और यह काम 30 अप्रैल तक कम्पलीट होने की संभावना है। सबसे पहले रेलवे का काम पूरा होना जरूरी है क्योंकि जब तक वे अपने गार्डर वगैरह नहीं डालेंगे तब तक इस पुल का काम आगे नहीं चल पायेगा। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्या ने जो साईड लेन को चौड़ा करने के बारे में पूछा हे उसके बारे मे मै आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूगा कि साईड लेन को भी चौड़ा करने पर हम विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यन से माननीय सदस्या को आश्वासन देना चाहूंगा कि ऐज पर टारगेट हमने जो समय सीमा निर्धारित की है उस टारगेट तक हम इसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 931

(इस समय माननीय सदस्य श्री नरेश यादव सदन मे उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Repair of Dabwali-Sangria Road

***808. Dr. Sita Ram:** Will the **P.W.D. (B&R)** Minister be pleased to state the date on which the Dabwali-Sangria road was recarpeted (repaired) last time togetherwith the time by which the said road will be repaired as it is in very bad condition at present ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Dabwali-Sangria road was last time recarpeted in three phases.

(i) Km. 0.00 to 2.15 (Four laning in city portion) during Feb., 2007.

(ii) Km. 2.15 to 28.00 during September, 2005.

(iii) Km. 28.00 to 31.52 during April, 2006.

The condition of part of the road at Sr. No. (i) and (iii) is satisfactory and agency has been directed to repair part of the road at Sr No. (ii).

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जो ने जौ जवाब दिया है उसमें उनके द्वारा दिए गये जवाब के पार्ट 2 और 3 का कार्य संतोषजनक नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः पार्ट 2 और 3 की नहीं मै पार्ट 1 और 3 की बात कर रहा हूँ।

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि पार्ट 2 और 3 का कार्य सतोषजनक नहीं है क्योकि मै अक्सर उस एरिया की तरफ जाता रहता हूँ यह सडक बिलकुल टूटी हुई है और इसके टूटने का भी कारण है क्योकि राजस्थान के अन्दर जयपुर हाईवे चार लेन का बन रहा है वह रतनगढ से होता हुआ हनुमानगढ़–रावतपुर तक जाता है उसकी वजह से राजस्थान से ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। रोड के ऊपर अतिरिक्त लोड होने के कारण यह सडक जल्दी टूट जाती हे। अगर इसकी रिपेयर भी करवाई जायेगी तो यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसलिये मंत्री जी नैशनल हाईवे की तर्ज पर इसकी रिकार्पेटिंग करवाने का क्या कोई प्रावधान करेगे ताकि यह लम्बे समय तक चल सके? क्या मंत्री जी इरा बारे मे विचार करेगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार अपने चहेतों को सडकों के ठेके देती थी। मुझे लगता है कि जिसको ठेका दिया गया वद कोई इनका ही चहेता होग।। इस सड़क का फेस– 1 का टेण्डर दिनांक 22 – 11 –04 को 213.36 लाख रुपये मे हुआ था और पहले पोर्शन की 4 लेनिंग फरवरी, श्का मे कम्पलीट हो गई थी लेकिन ड्रेनेज का काम अब तक चल रहा है। डिफोरैस्टेशन और बिजली कै पोल हटाने मे कुछ दिक्कत हुई है। अध्यक्ष महोदय,

इसमे सबसे बडी बात जो निकली वह यह है कि इन्होंने जो सीरियल न० 2 की बात कही है उसकी 196.72 लाख रुपये की लागत है, उसका टैण्डर किये बगैर इनहांस्मैंट करके और उसी ठेकेदार को यह काम दे दिया। अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजे दर्शाती हैं कि किस प्रकार की अनियमितताएं पहले होती रही है। यह काम इन्होंने मैसर्ज गर्ग कंस्ट्रकशन कपनी से करवाया हे और इसके एक्स. ई. एन. बस्ती राम है उसको अर्थ वर्क की वजह से सस्पैंड कर दिया गया है। वह पिछले 3 साल से सस्पैंड चल रहा है। उसने कई घोटाले किये हैं। जहां तक फेस– 2 की बात है उसकी प्रीवियस रिकार्पेटिग सितम्बर, 2005 में कम्पलीट की गई और 2007 तक इस सड़क की कंडीशन ठीक रही। किसी सड़क की रिकार्पेटिंग के लिये यह कंडीशन होती है कि वह सड़क कम से कम 3 साल तक चलनी चाहिए। इसकी थिकनैस की जहा तक बात है, वह 20 मिलीमीटर है। उस पर कार्य ठीक नहीं किया गया। उसके बारे में मैं ने आदेश दिए हैं कि 10 दिन के अन्दर–अन्दर इसकी इन्क्वायरी करके मुझे दी जाये। मैंने यह भी कहा है कि कोई भी दोषी हो, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे कट्रैक्टर हो अगर कोई सरकारी खजाने का दुरूपयोग करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। मैने अपने अधिकारियो से विशेष तौर पर कहा है कि वे दस दिन के अन्दर–अन्दर रिपोर्ट दे कि क्या कारण था कि यह सडक दोबारा से टूट गई?

डा० सीता रामः स्पीकर सर, जैसे कि माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है। बारिश होने के बाद नॉर्मली सडकों की रिपेयर की जाती है लेकिन बारिश के बाद रिपेयर न होने की वजह से तथा हैवी ट्रैफिक होने के वजह से ये सडक बार–बार टूटी। अध्यक्ष महोदय, वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो क्या मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि नैशनल हाईवे के जो रूल्स होते हैं उसका क्राईटीरिया लेकर इस रोड को उसी पैटर्न पर बनाने की कोशिश करेगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव अध्यक्ष महोदय. यह बात ठीक है कि इस रोड पर हैवी ट्रैफिक चलता है। जैसे इन्होने कहा है कि इस रोड की फोरलेनिग राजस्थान बॉर्डर तक हो गई है। हम सी. आर. एफ. स्कीम के तहत जल्दी ही इस रोड की स्ट्रैग्थनिंग और रिपेयरिंग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूगा कि जी सरकार अपने लोगो का फेवरिटिजा करती है वह वास्तव मे लोगों की भलाई का काम नहीं करती। पहले ऐसे लोगो को काम के टैण्डरज अलॉट होते रहे हैं जो इनके चहेते होते थे। सर, ऐसा ही एव? ठेकेदार करतार सिंह भी है जिसने पिछली सरकार के वक्त मे कई कान्ट्रैक्ट ले रखे थे। ऐसे लोग जान–बूझ कर कामो को डिले करते है और सरकार की नीति के खिलाफ काम करते हैं ताकि सरकार की छवि खराब हो। अध्यक्ष महोदय, हमारी मोजूदा सरकार के आने के बाद हम ई, टैडरिग द्वारा कान्ट्रैक्ट देते है और कान्ट्रैक्ट देने मे सरकार की तरफ से कोई

इन्टरफियरैंस नहीं की जाती और पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने इस सडक के बारे बताया है कि इस सड़क की स्ट्रैंथनिंग का काम जल्दी ही सी.आर एफ, स्कीम के तहत करवाएंगे।

ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि लाडवा दु मुस्तफाबाद रोड मे बहुत ज्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि इस रोड की मुरम्मत करवाने का कोई प्रावधान सरकार ने रखा है? इस सडक की रिपेयर का काम होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेगे कि क्या इस रोड को चौड़ा करने का भी कोई विचार है, यदि हा तो इसको कब तक किया जाएगा?

कैप्टन अजय सिह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह कहना चाहूगा कि इसके लिए ये सैप्रेट नोटिस दे तो इनको इसके बारे मे बता दिया जाएगा। स्पीकर साहब, हमारी कण्डीशन है कि कम से कम दो साल के बाद सड़क की मुरम्मत होती है और तीन साल के बाद उसकी रि–कारपैटिग का काम करवाया जाता है। हम इस रोड को दिखवा लेंगे और अगर इस रोड की कण्डीशन खराब है तो इसकी रिपेयर करवा देगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से डी० सीता राम जी को यह बताना चाहूगा कि इनके हल्के मे प्राईम मिनिस्टर सडक योजना के तहत चोरम खेडा से लेकर चुकरिया रोड और सकता

खेडा से मुरल्ला खेडा की दो सडके हैं जो 13 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से बनेगी और इन पर काम चल रहा हे। प्रधान मन्त्रो रोड योजना के तहत इस रोड को 12 कुट से बढ़ा कर 16 फुट चौड़ा किया जाना है जिसके लिए 13 करोड़ 14 लाख रुपये लगेगे। इनके ऐरिया मे सिरसा अन्हे रानिया डबवाली रोड है at the cost of करोड़ रुपये इसकी स्ट्रैंग्थनिंग एण्ड वाईडनिंग का काम किया है। यह रोड 61 किलोमीटर है और 15 करोड रुपये की लागत से इसका काम पूरा किया गया है। स्पीकर सर, हमारी सरकार की यह प्रॉयोरिटी रही हे कि बिना किसी भेदभाव के काम किया जाए। चाहे विपक्ष का कोई भी साथी का हल्का हो चाहे रूलिंग पार्टी के किसी सदस्य का हल्का हो उसमे हम नाबार्ड के तहत या प्रधान मन्त्री सड़क योजना के तहत सडको की मुरम्मत भी करते है और हर प्रकार से ठीक ढग से काम करते है।

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा मे आते हुए मुझे भी लगभग आठ साल हो गये है। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार होते हुए भी मैने मांग उठाई थी कि हजामपुर जमालपुर तोशाम सुद्धिवास वाली जो सडक है उसकी हालत इतनी खस्ता है कि वहा पशु भी नहीं चल सकते हैं। इस रोड के बनवाने के बारे मे आज तक मुझे आश्वासन ही मिलते रहे है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन सड़को के काम को टाईम बाउड

करके बनवाया जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के वक्त मे तो इस रोड से तारकोल के ड्रम भी उठवा लिये गये थे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले जिस काण्ट्रैक्टर का नाम बताया है इस सडक का काण्ट्रैक्ट भी करतार सिह के पास है जो पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान उसको अलाट किया गया था। चार किलो मीटर तक उसने इसका काम किया उसमे इतनी अनियमितताएं पाई गई कि इस का काम रुक गया। जल्दी ही नोटिस दे कर दो महीने मे इसका काम शुरू करवा दिया जाएगा। (विघन)

श्री अध्यक्षः क्या इस सडक की रिटैंडरिंग करवाएंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसके लिए क्या प्रक्रिया तय करनी पड़ेगी लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे इसकी रिटैडरिग करनी पडे या इसका काम उसी काण्ट्रैक्टर से करवाएं लेकिन इस सडक का काम दो महीने मे शुरू करवा देगे।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल करना चाहता हू कि हमारे मेवात एरिया के जो रोडज हैं उनकी हालत बहुत ही जर्जर है। अगर मैं उन सडको के नाम बताऊगा तो बहुत सी सडके हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, एक सडक तावडू से भागीपुर की है जिसकी लम्बाई 7 किलोमीटर की है। अगर उस सडक पर कोई भी आदमी गाडी से जाना चाहे तो

उस 7 किलोमीटर को पार करने मे आधा घटा लग जाता है। इसके साथ ही एक और सडक तावडू से मढार रोड है

श्री अध्यक्षः साईदा खान जी, क्या आपने कभी इस बारे मे पहले कोई सवाल दिया है?

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, बहुत सै माननीय सदस्यों ने अपने–अपने हल्के की सड़को के बारे मे सवाल हैं। अगर मैंने पूछ लिया तो इसमें क्या दिक्कत है? मैने जो सवाल पूछा है उसका मंत्री जी जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष इसमे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप इतने रिस्पोसिबल बनते है और इतनी सीरियसनैस दिखाते है तो मै यह पूछ रहा हूं कि आपने हस बारे मे कभी कोई सवाल पूछा है या गवर्नर एड्रैस मे हस बारे में चर्चा की है? यह प्रश्न स्पैसिफिक डबवाली–सगरिया रोड के बारे में है।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, सभी अपने–अपने प्रश्न पूछ रहे हैं अगर साहिदा खान ने सवाल पूछ लिया तो क्या कोई गुनाह कर दिया है?

श्री अध्यक्षः आपका यह सैप्रेट प्रश्न है। आप इस बारे मे अलग से लिखकर दे दे। मंत्री जी आपको इसका जवाब दे देगे।

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि इन्होने सिरसा जिला मे ज्यादा पैसा

खर्च किया हे। में आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पन्नीवाला मोटा से आसाखेडा तक एक सडक जाती है आज उसका स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है। क्या मत्री जी उस सडक को नए सिरे से बनवाने या उसकी रिपेयर करवाने रू। कष्ट करेगे। अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के लिये पैसा मंजूर हो गया था लेकिन इन्होंने वह पैसा बाद मे पता नहीं क्यो वापिस मंगवा लिया?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से पूछना चाहूंगा कि कहीं यह सडक वही तो नहीं है जो चौटाला जी के फार्म हाऊस को जाती है।

डा० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के लिए पैसा मजूर दो गया था लेकिन इन्होने वह पैसा पता नहीं क्यो बाद मे वापिस मंगवा लिया। क्या मंत्री जी उस सडक को नए सिरे से बनवाने या रिपेयर करने के बारे मे कोई विचार करेगे?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस सडक का जिक्र किया है इसके लिए माननीय सदस्य सैप्रेट नोटिस दे दें। मै इसको एग्जामिन करवा लूंगा और एग्जामिनेशन के बाद ही हाऊस मे इस बारे मे कुछ कहा जा सक ता हर।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मत्री जी ने अपने जवाब मे दो बाते कहीं हैं। मैं महसूस करता हूं कि जो सडको की कारपेटिग होती है वह 3 वर्ष तक चलनी चाहिए। इसके साथ ही

जो सड़कों के काम चहेतो को दिए गए है और वे काम ठीकै ढंग से नहीं रहे हैं इस बारे में मंत्री जी से आग्रह करते हुए पूछना चाहता हूं कि जो सड़क हरियाणा में रिपेयर हुई है ये सड़कें हरियाणा मे सभी जगहों पर रिपयेर हुई होंगी। इस हिसाब से उन सडको की रिपेयर और मैंटीनैंस कम से कम 1 वर्ष तक तो चलनी चाहिए। इसके साथ ही यहा पर चहेती की बात चल रही थी और उन चहेतो को एक–एक जिले मे सड़को के ठेके दे दिए गए थे लेकिन आज उन ठेक्को को दिए हुए 2–3 साल हो गये हैं ओर उन सडको के काम कम्पलीट नहीं हुए है। क्या इस बारे मे मंत्री जी जांच करवाएगे कि वे काम अभी तक पूरे क्यो नहीं हुए हैं? अध्यक्ष महोदय, इस वजह से जनता मे सरकार की छवि खराब हो रही है। मंत्री जी क्या आप इस बारे मे उन ठेकेदारो के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करेगे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय इस सरकार ने निर्णय लिया है कि जिस भी ठेकेदार को जिस सडक का हम काम देगे, उस सड़क को एक साल तक मेनटेन करने का काम उसी ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। जहा तक माननीय साथी जी ने चहेतो वाली बात कही है तो इस विषय मे मैं इनको कहना चाहूंगा कि हमारे लिए कोई भी चहेता नहीं है न ही पी. डब्ल्यू. डी. (बी. एण्ड आर.) मे ऐसी कोई बात होती है और जो भी व्यक्ति ऐसा होगा चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे स्पैसिफिक कम्प्लैंट लिखकर दे दे। हम उस ठेकेदार के

खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ओर अगर किसी अधिकारी ने इस तरह के लोगो को शह दी है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। अध्यक्ष– महोदय, मेवात के अदर एन सी. आर. के तहत भी हमने 588 करोड़ रुपये मजूर करवाए हैं। इसमे हमने इनकी दो मेजर सडके मजूर करवायी है। स्पीकर सर, इस सरकार के समय मे चाहे तावडू का एरिया हो या कोई दूसरा एरिया हो, सबका हमने ध्यान रखा है विशेष रूप से मेवात के एरिया का तो हमने बहुत ध्यान रखा है। चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत सड़क बनाने की बात हो या चाहे नाबार्ड के तहत सडक बनाने की बात हो, अगले दो वर्षो मे इनकी सडको मे सुधार आएगा।

आई. जी. शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके मे भी एक ऐसी सड़क बन रही है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के मुताबिक रोहतक और जींद जो नेशनल हाई वे हैं, वहय से वह गोहाना और जींद रोड को पार करते हुए पिल्लखेडा जा रही है। मेरे एारेया मे लगभग 6 किलोमीटर तक यह रोड मार्केटिग बोर्ड ने बनायी हुई है लेकिन स्पैसिफिकेशन दोनो की अलग–अलग है इसलिए एक पैच बीच मे बहुत ज्यादा भद्दा लगता है। नन्दगढ गांव से लेकर भैरोखेडा तक यह 6 किलोमीटर का टुकडा है जो अलग ही दिखाई देता है जबकि वहा बाकी रोड दूसरी तरह की यानी अच्छी दिखाई देती है। मै आपके माध्यम से मत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या सरकार के पास ऐसी योजना है कि यह जा 6 किलोमीटर सड़क का टुकड़ा भी वहा पर जो बाकी सड़क है

उसके मुताबिक ही अच्छा बन जाए यानी एक ही तरह की सड़क वहां पर बन जाए ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, अगर वह मेजर स्टेट हार्ड वे है तब तो हम इसको बनाने के बारे मे विचार कर सकते है! लेकिन यह स्टेट हाई वे नहीं है इसलिए मार्केटिंग बोर्ड ही इस सड़क की रिपेयर करवा सकता है। मै समझता हू कि अगर यह बात माननीय सदस्य कृषि मंत्री जी के सामने रखें और यदि वे उसी तरह पर इस सडक के टुकड़े को भी बना दे जिस तर्ज पर हमने वहां पर रोड बनायी हैं तो मेरे ख्याल से यह बेहतर रहेगा।

कृषि मंत्री (सरदार एच .एस. चट्ठा): स्पीकर साहब, यह मुझे लिखकर दे दें कि कौन सी सडक है और कहां पर बननी है, मैं विचार कर लूंगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मै आपके माध्यम से पी. डब्ल्यू.डी., हरियाणा सरकार ओंर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूं' कि कलायत जैसे पिछडे क्षेत्र मे इस समय सडको का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कलायत रेलवे रोड एक ऐसी मेन सड़क है जो डेढ दो साल से अधूरी पड़ी हुई है। यह केवल डेढ किलोमीटर का हो टुकडा है जिसमे डिवाइडर बनाया गया था और फिर तोड़ दिया गया था। उसके बीच मे पोल्ज भी खडे है। मैने कई बार मंत्री जी से इसकी लिखित तौर पर शिकायत भी की है और

अधिकारियो को भी मे इसकी शिकायत कर चुकी हूँ। क्या माननीय मंत्री जी बंताएगे कि उन अधिकारियो या ठेकेदार के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जाएगा?

केप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय सदस्या की शिकायत आयी थी। इन्होने कहा था कि वहां का जो एस. डी. ओ. है वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है इसके बाद मैंने तुरन्त अपने सैक्रेटरी साहब और ई. आई. सी. साहब दोनो को निर्देश दिया था कि जल्दी इस मामले मे कार्यवाही की जाए और जल्दी शुरू की जाए। अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो सरकार जरूर कार्यवाही करेगी।।

श्री फूलचन्द मुलानाः स्पीकर साहब, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और उसके थोडे दिनो बाद मे बरसात आ जाएगी। मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या बरसात से पहले–पहले देहात की सारी सडको की रिपेयर करवा देगे?

कैप्टन अजय सिह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको इतना आश्वासन दे सकता हू कि हम पूरी कोशिश करेगे कि मैक्सिमम स्टेट की जितनी भी रिपेयर के लायक सड़के है वह अगले दो वर्षो मे बजट के प्रावधान को देखते हुये रिपेयर करेगे।

श्री अरजन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल भी सडको के मुताल्लिक ही है। मै मंत्री जी को सडको के बारे मे जानकारी

देने देह लिए धन्यवाद करना चांहूगा। पहले तो लोगो को यह पता ही नहीं चलता था कि सडक कितने दिन के लिए बेनी है और कब टूट जायेगी। लोग तो यह सोचते हैं कि सरकार का ही सडक बनाने का काम है और सरकार का ही सडक तोड़ने का काम है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के मे चार– पाच सड़कें ऐसी बनी हैं जो 6 महीने बाद ही टूट गयी है। ठेकेदारों को भी इसकी जानकारी है कि तीन साल की अवधि में ये सडकें ठीक करवानी पड़ेंगी। –इनमे एक सडक मार्किटिग बोर्ड की है जोकि जयधरी बेगमपुर से देवधर रोड है यह सड़क डेढ साल मे तैयार हुई –एगर छह महीने मे दूट भी गई। इसके बारे मे आप जाकर इन्क्वायरी करवा ले। इस सडक का कहीं नामो– निशान तक नहीं मिलेगा। दूसरी सड़क दादूपुर से बूडिया है इस सडक पर तो बनने के बाद कोई दक्ष, बस या लारी आदि चढ़ी ही नहीं है और ये उससे पहले ही टूट गई है। वहा अब पेड खड़े हुए है।

श्री अध्यक्षः इन सारी सडको के नाम लिख कर आप चड्ढा साहब के पास भिजवा दे या श्री शादी लाल बत्रा साहब जो कि मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, के पास भिजवा दे।

श्री अरजन सिंहः ठीक है, सर।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हू कि सोहना रोड को आठ लेन कर दिया गया

है। इसके साथ ही यह बताना चाहता हू कि जो एक खडी दिक्कत आ रही है वह यह है कि गुडगांव–फरीदाबाद रोड का घाटा गत पड़ता है वहां बहुत वढाई है और उस पर जो ओवरलोडेड ट्रक और गाडिया आती है, वे चढ़ नहीं पाती हैं, रुक जाती है जिसकी वजह से वहां रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोज ट्रैफिक जाम हो जाता है। मै मुख्यमत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए। इसके अलावा सोहना रोड पर भी एक घाटी की चढाई है। वहां भी सेम पोजीशन है और गाडियां चढ़ नहीं पाती है। उस रोड पर भी साथ दिन जाम लगा रहता है। वह रोड एन. एच. – 71 –बी बन गई है तो अब उसका काम न तो हाइवे अथोरिटी करती है न बी. एण्ड आर. करता है। बी. एण्ड आर. वालो से कहो तो वे कहते है कि हाइवे अथौरिटी को यह काम दे दिया गया है लेकिन जब हाइवे अथोरिटी वालो से कहते है तो वे यह कहने है कि पलवल रोड का काग शुरू हो गया है दूसरी तरफ रिवाडी से काम शुरू हो गया है। इसलिए अभी हम यह काम नहीं कर सकते है। अध्यक्ष महोदय तावडू व सोहना पोर्शन के काम को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। रोड की हालत जर्जर हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि जब तक हाइवे अथोरिटी वाले रोड बनाने के लिए नहीं आते तब तक बी.एण्ड आर. टेकओवर करे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सोहना सड़क का

ऐस्टीमेट तैयार हो युका है। इसका एन.एच. ए. .आई. से केस टेकअप कर रहे है और उम्मीद है कि जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। क्योकि यह रोड एन.एच. ए. आई. के अंडर आ गई हे तो बी. एण्ड आर. डिपार्टमैंट के भू इसकी रिपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम इसको एन. एच. ए. आई. द्वारा जल्दी ही रिपेयर कराएगे। दूसरे इन्होने जो घाटा गाव की सडक की बात कही है उसको दिखवा लेते है जो भी हो सकेगा, उसको करेगे।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः अध्यक्ष महोदय, एन.एच. 71 बी बन गया है और फरीदाबाद से पलवल की तरफ रोड बन रही है क्योकि वहां से कर्ण सिह दलाल साहब विधायक हैं। दूसरी तरफ से रिवाड़ी की शुरू हो गई है क्योकि आप बैठे हैं। लेकिन सोहना और तावडू के पोर्शन का अभी टेण्डर भी नहीं हुआ है। पोर्शन दोनो तरफ से बनने शुरू हो गए हैं लेकिन ये पोर्शन जो कि के.एम.पी. को टच कर रहा है। इस पोर्शन का हो नही आया छै। थर्ड फेज मे इस काम को करने की बात कही जा रही है उसमे तो तीन साल का समय लग जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया है कि इसको एन. एच.ए. आई. से टेकअप कर जल्द ही काम शुरू करा देगे।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः क्या इसकी रिपेयर कराते क्योकि इसकी रिपेयर न होने की स्थिति मे कोई आदमी तावडू नही जा सकता है, रोड की यह हालत हो गई हें।

केप्टन अजय सिंह यादवः जो माइनर पैचिज वगैरह है उनको तो ठीक करा देगे लेकिन जो मेजर स्ट्रैग्थनिग आदि हैं या रोड की चौडाई बढाने की बात होगी उसके लिए तो जब एन एच ए. आई से पैसा अलोकेट हो पाएगा और वहा से पैसे की सैक्शन मिल जाएगी, तभी उस काम को करा सकेंगे। जहां तक आपकी हस रोड का सवाल है, इसका मोटरबल जरूर बना देगे।

डा० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के मे जीतू वाला फाटक से दिनोप नाई पास को जो रोड जातो है उसका जीतू वाला फाटक से शाम बाग तक का आधा भगि पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा बना हूआ है उस भाग को तो काफी अच्छा कर दिया गया है लेकिन उसका उससे आगे का आपा हिस्सा पहले कभी मार्किटिग बोर्ड ने बनाया था, उसकी हालत बहुत जर्जर है। मैं रिक्वेस्ट करता हू कि उस हिस्से को के बी. एण्ड आर ले ले, बह एक किलोमीटर से भी कम टूकडा है। पहले ही आग बी एण्ड आर. के पास है, आधा ले लेने से सारा बी. एण्ड आर. के पास हो जाएगा तो उससे उसकी मेटीनेस भी ठीक हो जाएगी। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र चौधरीः अध्यक्ष महोदय एक ही सवाल पर चर्चा होते होते आधे घण्टे का समय बीत गया है।

श्री अध्यक्षः यह पब्लिक इम्पोर्टेस का सवाल हे। सरकार की सारी की सारी वर्किग ऐफीशिएसी सड़को पर ही निर्भर करती है। आप क्वेशचन पूछना चाहे तो आप भी पूछे। आधा घण्टा इसी क्वेशचन पर नहीं हुआ है बल्कि आधे घण्टे मे यह चौथा सवाल है।

10.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादवः सर, इसको हम ऐग्जामिन करवा लेगे कि जो मार्किटिग बोर्ड की सडक है उसके बारे मे पॉलिसी यह है कि जिस डिपार्टमैंट की सड़क जो बनाता है वही विभाग उसको रिपेयर करता है। आप इस बारे में कृषि मंत्री जी को या चेयरमैन मार्किटिंग बोर्ड को अप्रोच करे और उसको रिपेयर करवा ले। जहां तक रिपेयर पंचायती राज से करवाने के बारे मे सवाल है, 110 सडके हमने पहले इसमें रिपेयर करवाई भी हैं क्योकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्वर उपलब्ध नहीं दै। मार्केटिंग बोर्ड के पास काफी बजट है इसलिए इन सड़को को मार्केटिंग बोर्ड द्वारा रिपेयर करवाया जा सकता हे।

श्री रामफल चिडाना अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांवो रिडाना से घडवाल की एक सड़क है जो 500 गज का टुकड़ा अधूरा पड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना

चाहता हू कि क्या मंत्री जी इस काम की जाँच करवायेगे कि इन सड़को का काम शुरू क्यो नहीं हुआ। क्या उस सड़क को बनाने का सरकार का विचार है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन सड़कों का जिक्र किया है, उनको हम जरूर ठीक करवायेगे।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्राः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि डाक्टर भारद्वाज जी ने कहा कि इन सड़कों का काम पी. डब्ल्यू. डी. को दे दिया जाये तो हालात सुधर सकते हैं। मेरे हल्के के गांव मिताथल बाई–पास हरिजन बस्ती के पास से रोड निकलता है और जताई गांव की सड़कें बनने का काम दो साल से मंजूर हुआ पड़ा हे लेकिन उनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जब विभाग के अधिकारियो से पूछते है तो यह जवाब आता है कि ठेकेदार किसी और जगह काम में लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इन सड़कों की रिपेयर के काम को एक्सपेडाईट करवा दें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हम अधिकारियो को निर्देश देगे कि वे वहां जाकर इस बारे मे जाँच करे। जो भी इस मामले मे दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे और इन सड़को की रिपेयर का काम जल्दी करवायेगे।

Deaths Due to Electrocution

***818. Sh. Radhey Shyam Sharma, M.L.A.:** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a number of persons and cattle have died from electrocution due to the iron poles of electricity in Narnaul constituency;

(b) if so, the details thereof togetherwith the time by which these iron poles are likely to be replaced with cemented poles; and

(c) the time by which the Power sub-stations constructed in village Dholera, Tehsil Narnaul will be commissioned ?

Interim Reply

Sub: **Starred Assembly Question No. 818-deaths due to Electrocution in Narnaul Constituency .**

A Starred Assembly Question No. 818 asked by Shri Radhey Shyam Sharma, MLA regarding deaths due to electrocution has been listed for 14-3-2008. Some additional information has been requisitioned to deal with the possible supplementaries. This information from the field offices will not be possible upto 14-3-2008.

It is therefore, requested that extension of time for the said question be granted and may please be listed on or after 19th March, 2008.

Power Minister,

Hon'ble Speaker, Haryana

Vidhan Sabha.

Annual Plan and Non-Plan Budget

***836. Shri Shamsher Singh Surjewala:** Will the Finance Minister be pleased to state the Annual Plan and Non-Plan Budget of Haryana during the last five years ?

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir,

During the last five years the Annual Plan and Non-Plan Budget of Haryana was as under:--

(Rs. in crore)

Year	Plan Expenditure	Non Plan Expenditure	Total Expenditure
2002-03 (Actual)	2063.90	8170.46	10234.36
2003-04 (Actual)	2368.98	10563.18	12932.16
2004-05 (Actual)	2705.16	9806.93	12512.09
2005-06 (Actual)	3706.97	10721.90	14428.87

2006-07 (Actual)	4975.42	13999.05	18974.47
2007-08 (BE)	5998.76	13753.10	19751.86

श्री एस.एस. सुरजेवालाः स्पीकर सर, मैं सरकार को और माननीय वित्त मंत्री महोदय को मुबारिकवाद देना चाहूगा कि इन्होने बहुत बढ़िया बजट इस सरकार को दिया है। यह सरकार बनने से पहले तीन सालो वर्ष 2003 से 2005 का बजट देखे तो ऐनुअल प्लान एक्सपैंडीचर में मुश्किल से 330 करोड़ रुपये बढे हें। इस सरकार के आने के बाद इसमे करीब 1००० करोड रुपये का जम्प हुआ है। डिवैल्पमैंट के जितने भी वर्क्स हैं उनके लिए प्लान ऐक्सपैंडीचर होता हे। नॉन–प्लान एक्सपैंडीचर जो है उसमें कर्मचारियो और अधिकारियों की तनखाहे और दूसरे खर्चे हे। दोनो मे तकरीबन–तकरीबन 3 गुना फर्क है और उससे पहले जो पिछली सरकार थी उसमे यह फर्क 4–4 गुणा होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूगा कि क्या वे इस गैप को कम करेगे क्योकि यह अच्छी इकोनिमी और स्टेट की तरक्की और हैल्थ का प्रमाण है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो 12वां फाइनास कमीशन था उसने खर्चे को सीमित रखने के लिए बजट को इफैक्टिव बजट बनाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए थे। जब हमारी सरकार आई तो उसी साल हमने विधान सभा द्वारा ऐक्ट

पास कराकर उन मापदण्डो को अपना लक्ष्य बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑनरेबल सुरजेवाला जी को यह बताना चाहूंगा कि जो बात ये कह रहे है वे सीमाओ मे अगर खर्चे रहे तो डिवैल्पमैट पर ज्यादा खर्चा हो सकता है हमने उसके लिए जो कदम उठाए थे उसमे 2004–05 मे जब हम सरकार में आए तो उस समय रिवैन्यू रिसीट्स मे हमारी स्टेट घाटे मे थी, 2005 – 06 मे वह घाटा पूरा करके हम 1213 करोड़ रुपये सरप्लस में हो गए, 2006–07 मे वे रिवैन्यू रिसीट 1213 करोड़ से बढकर 1590 करोड़ सरप्लस मे हो गए और इस साल बजट एस्टीमेटस के मुताबिक अब तक 1149 करोड़ के रिवैन्यू रिसीट थे लेकिन मैं समझता हूं कि जब ऐक्चुअल फिग्गर्ज आएंगें तो 31 मार्च के बाद ये जो 1149 करोड़ की सरप्लस है यह 1500 या 1600 करोड़ तक बढने की उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिवैन्यू रिसीट्स की बात है तो उसमें जो मापदंड थे, उससे हम आगे ही हैं और शायद देश मे कुछ एक ऐसे राज्य हों जो हरियाणा की तरह रिवैन्यू रिसीट में सरप्लस हो। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय घाटा जो है, वह 3 प्रतिशत से नीचे होना चाहिए। ऐसे आर. बी. एम. के मापदंड थे। जब हमारी सरकार आई तो 2003–04 मे यह वित्तीय घाटा 3.6 प्रतिशत था, जो स्टेट जीडीपी. है उसको मानकर इसमे लिया जाता है। वर्ष 2005 –06 में यह वित्तीय घाटा 3.6 से 0.3 प्रतिशत पर आ गया और उसके बाद वर्ष 2006–07 मे यह और नीचे आया और वर्ष 2007–08 में the fiscal deficit is expected to be around zero जोकि 3 प्रतिशत भी अगर रहे तो भी हम फिस्कल मैनजमैंट मे

ऐफीशिथेंट हैं लेकिन यह जीरो परसैंट तक आने की सम्भावना है। अध्यक्ष महोदय, इन्होने तनखाहों और पैंशन की बात की, मापदंड के अनुसार एक समय ऐसा था जब हरियाणा मे टोटल बजट में से 60 प्रतिशत बजट तनख्याहो और पैंशन के लिए जाता था और ये फिगर्ज 1999–2000 के हैं। उसके बाद 2004–05 में यह घटकर 40.00 परसैट रह गया था और जबसे हमने कार्य भार सम्भाला है यह वर्ष 2005–06 में 40.90 परसैंट से घटकर 34. 35 परसैंट आ गया है। वर्ष 2००6–०? मे 33. 32 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2007–08 मे 32.57 प्रतिशत मे हो गया। अध्यक्ष महोदय, यह बजट एस्टीमेट्स के मुताबिक है इसमें फिग्गर वैरी करेगे और नीचे०पर भी होंगे। इसके साथ–साथ जो स्टेट के डैब्ट हैं जिनकी आज से 4–5 साल पहले 26–27 हजार करोड़ रुपये की लायबिल्टीज थी जिनके हमे सालाना 400 करोड रुपये ब्याज के देने पडते थे। As per debt norms जो हमारी देनदारी थी, उसमे स्टेट गारटीज भी थी। ये एक समय 28% of the State GDP थीं। 2001 – 02 मे ये लगभग 38.88 प्रतिशत थी, 2002 –03 में 29.40 प्रतिशत थी लेकिन अब हम उनको नीचे लेकर आये है। 2006–07 मे ये 25.77 प्रतिशत थी और इस साल 2007–06 में अब तक के आकडो के मुताबिक 23.35 प्रतिशत रह गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो कर्जे लिए हुए हैं उनकी बजट देनदारी 40 प्रतिशत से घटकर 23.35 प्रतिशत रह गई है।

श्री एस.एस. सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, परफौरमैस के बारे में वित्तमंत्री जी ने विस्तार से बताया है इसलिए मैं उनको मुबारबाद देता हू लेकिन मंत्री जी ने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया। फाईनैस कमीशन क्या कहता है इससे मेरे सवाल का कोई सरोकार नहीं है। मेरा सवाल यह है कि हरियाणा जैसे छोटे स्टेट मे जहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवो मे रहती हे। जीडीपी. मे तो फरीदाबाद और गुड़गाव जैसे बडे–बडे शहर कवर होते है। लेकिन जो 70 प्रतिशत लोग गांवो मे रहते हैं न तो उनके लिए अच्छी शिक्षा का प्रावधान है, न चिकित्सा का इतंजाम हे। गांवों में रहने वाले लोगो के लिए शिक्षा और चिकित्सा का बहुत बुरा हाल है। क्या सरकार इस बारे मे इन्नोवेटिव तरीके से सोचेगी ? सरकार अपने खर्चे कम कर सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार पर कई विभाग बोझ बने हुए हैं जिनको सरकार अबोलिश कर सकती है। इसके अलावा एक और कदम सरकार उठा सकती है वह यह है कि जो कारे अधिकारियो और मंत्रियो की सरकार ने दे रखी है उनकी बजाय सभी अधिकारी ओर मंत्री अपनी कारे इस्तेमाल करे और ट्रैवल का जो खर्चा आये वह सरकार से ले लें, इससे गाड़िया का दुरुपयोग कम होगा तथा काफी पैसा बचाया जा सकता है। इसी तरह से जो सरकारी टैलीफोन अधिकारियो और मंत्रियों के यहा लगे हुए हैं उनकी जगह मी वे अपने टैलीफोन इस्तेमाल करें और जो बिल आये उसका खर्चा सरकार से ले लें। यह बहुत बडा गैप है जो

कम किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि वित्तमंत्री जी इस बारे में कोई ठोस कदम उठायेंगे।

श्री अध्यक्षः सुरजेवाला जी, आपके सवाल का जवाब आ गया है। नॉन–प्लान एक्सपैंडीचर को खत्म करने के लिये क्या–क्या कदम उठाये जा रहे हैं इस बारे मे मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। जहां तक बजट एलोकेशन की बात हे, यह हैल्थ में, एजुकेशन मे और पी.डब्ल्यू.डी. में हुआ हे। यह तो सरकार की पौलिसी

श्री कर्ण सिंह दलाल अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वित्त विभाग कोई बजट कलैण्डर तैयार करता है और यदि हां तो उस बजट कलैण्डर के मापदण्ड क्या हैं? अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आपके मार्फत दूसरा सवाल वित्तमंत्री जी से मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो नॉन–प्लान और प्लान बजट सालना बनाया जाता है इसको पंच–वर्षीय या दस वर्षीय बनाने पर भी मंत्री जी विचार करेगे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, हम बजट में विभिन्न विभागो के लिए बजट का प्रावधान करते है उसका सबरने बड़ा आधार हमारी पार्टी का घोषणा पत्र होता है। जिस समय हमने लोगो से वोट लिये थे, उस समय हमने लोगो से वायदे किए थे। यही कारण है कि बजट बनाते समय हम अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को ही आधार मानते हैं। यह भी सही है कि आज हरियाणा

को अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो हमारे दूसरे सैक्टर हैं जो समाज के गरीब लोग हैं उनको एक किस्म से इतना बड़ा सहारा दिया जाये जिससे कि वे भी आर्थिक दौड़ मे जमाने के साथ शामिल हो सके। इन सारी चीजों को ध्यान मे रखते हुये हमने ऐसा किया है। जहां तक श्री सुरजेवाला जी द्वारा दिये गये सुझाव का सम्बन्ध है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि जो मन्त्री, विभागाध्यक्ष और सैक्रेटरीज है उनकी अपनी कार होनी चाहिए और उसके लिये वे सरकार से अलाऊंस क्लेम कर ले इन सारी बातों को ध्यान मे रख कर ही हमारी सरकार ने माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल की अध्यक्षता मे ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की स्थापना की है। ये जो सुझाव देगे, सरकार उन पर गौर करेगी।

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सरकार को बजट मे बढौतरी करने के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि यह जो प्लान के बजाय नॉन–प्लान एक्सपैंडीचर बह गया है क्या इसमें जो सरकार द्वारा पैंशन बढाई गई है और दूसरे वर्गो को जो कुछ भी लाभ दिया गया है क्या यह सब भी इस नॉन–प्लान मे शामिल किया गया है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हू कि हमारी नई वार्षिक योजना मे 6650 करोड़ का प्रावधान है और जब वर्ष 2005 में हमारी सरकार का गठन हुआ, उस्से पहले हरियाणा का नॉन–प्लान

एक्सपैंडीचर सिर्फ 2200 करोड़ था और जिसमे से हमारे ये साथी 2000 करोड रुपये ही खर्च पाये थे। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय आपको यह जानकर भी बड़ी खुशी होगी कि आज तक जब से हरियाणा बना, जो चौथी पचवर्षीय योजना थी वह 1979 में इट्रोड्यूस हुई थी और वर्ष 2007 तक यानि चौथी पचवर्षीय योजना से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक इन सात पंचवर्षीय योजनाओ मे हरियाणा बनने के बाद से कुल 31,006 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ था और अब अकेले जो हमारी 11 वीं पंचवर्षीय योजना है उसमे 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हे। यानि हरियाणा के अन्दर जो 40 साल मे खर्च किया गया, उतना अगले 5 सालों मे खर्च किया जायेगा।

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होने अपने जवाब मे कहा है कि जो हमारी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है, सरकार द्वारा उसके मुताबिक ही अपनी प्राथमिकताये तय की जाती है। हालांकि कुशल आर्थिक प्रबंधन के लिए यह बात तो जरूरी है कि पैसे को योजनागत तरीके से खर्च किया जाये। इन्होंने गैर–योजनागत तरीके के बारे मे बताया है कि हमने रेवेन्यू रिसीट्स में बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है लेकिन अपने चुनावी घोषणा–पत्र मे इन्होने साफ दर्शाया था कि हम वैट को पूरी तरह से समाप्त करेगे। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रेवेन्यू रिसीट्स में वैट का अहम रोल है

इसके अलावा क्या इन्होने कोई अतिरिक्त साधन भी जुटाये हैं जिन से रिवेन्यू रिसीट्स बढी हो और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढावा दिया गया हो।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्यो श्री फूल चन्द मुलाना जी और श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी को बताना चाहूंगा कि जो प्लान बजट है उसमे पिछले 3 साल मे 300 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और जो नॉन–प्लान एक्सपैडीचर है उसमे 200 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई हे। अगर इसको आप कम्पेयर करे तो 100 प्रतिशत प्लान एकरपैडीचर बढा है और उसके कम्पैरेटिवली हम उसको नीचे लेकर आये है और दूसरी बात इन्होने यह कही है कि वैट का हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र मे विरोध किया था। इस बारे मे मैं बताना चाहूगा कि जो पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र था उसका मैं कनवीनर था चौधरी कुल चन्ध मुलाना और श्री सुरेजावाला जी भी उसमे सदस्य थे, उसमे हमने साफ लिखा था कि we opposed the VAT in isolation. If VAT is to be introduced, it should be introduced uniformly in the entire country. यह हमारा विरोध था न कि वैट का विरोध। आज सिर्फ वैट की ही बात नहीं हे जब हमारी सरकार आई तो स्टॉम्प ड्यूटी से उस समय 560 करोड़ रुपये मिलते थे और आज हमे इससे कितना मिल रहा है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस बार हमे इससे 2200 करोड़ रुपये मिलेगे, जो कि 400 प्रतिशत से भी ज्यादा हैं।

Residential Sector of HUDA in Julana

***935 Sh. Sher Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop residential sector of HUDA in Julana, District Jind; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

Shri Randeep Singh Surjewala (Power Minister):

(a) No sir,

(b) Not applicable please.

आई. जी. शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सन 2000– 2005 के बीच मे जो सरकार थी उन्होंने जुलाना मे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम पर लोगो से 2000,3000 और 5000 रुपये तीन कैटेगरी में एडवास में लिए थे। मैं जानना चाहूगा कि वह पैसा किसी संस्था द्वारा लिया गया है, या किसी विभाग द्वारा लिया गया है। क्या मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे और अगर हुडा का सैक्टर जुलाना में नहीं बनता है तो क्या लोगो का वह पैसा वापिस किया जायेगा 9

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जुलाना में कोई पैसा जमा नहीं करवाया है। अगर किसी ऐजेन्सी

ने पैसा लिया है तो माननीय सदस्य लिख कर भिजवा दे, हम यह सुनिश्चित करेगे कि उस पर कार्यवाही होगी और वह सारा पैसा वापिस दिया जायेगा।

श्री भूपेन्द्र चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पटौदी मे भी पैसा लिया गया है और पिछली सरकार मे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भौडा कला मे पत्थर रख कर आये थे। अब तक न तो पैसा वापिस किया गया है और न ही हुडा का सैक्टर काटा गया है। क्या मंत्री जी इसके बारे मे भी बतायेगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मौजूदा मुख्य मत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने यह निर्णय लिया है कि पटोदी के अन्दर हम भविष्य मे हुडा का सेक्टर जरूर काटेगे। हालांकि जिस पैसे की माननीय सदस्य चर्चा कर रहे है उस पैसे के बारे मे अभी इस समय मेरे द्वारा जवाब दिया जाना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास जो जानकारी हे उसमे इस पैसे की कहीं कोई रिफलैक्शन नजर नहीं आती। फिर भी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे मुझे इस बारे मे लिख कर भिजवा दे। हम यह सुनिश्चित करेगे कि वह पैसा वापिस हो और पटौदी के अन्दर हुडा का नया सैक्टर भी काटा जायेगा। पिछली सरकार ने तो फिजी तक का पैसा नहीं छोड़ा, चौधरी महेन्द्र चौधरी भी चौटाला साहब को ढूंढते फिर रहे है।

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि करनाल मे हुडा के पुराने सैक्टर जो लो लाईग हैं वहाँ पर सड़को पर पानी भर जाता हे जिसके फलस्वरूप सडके जल्दी टूट जाती हें। क्या मंत्री जी ऐसा प्रावधान करेंगे कि जिस प्रकार नगरपालिका वाले कक्रीट की सडकें बनाते है उसी प्रकार की सड़के वहां पर बनवाई जायें?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह पृथक प्रश्न है लेकिन माननीय सदस्या ने कहा है तो मै उनसे अनुरोध करूगा कि वे लिख कर भिजवा दें कि कंक्रीट की सडके बनवाई जायें। केस दू केस हम देख कर जरूर कार्यवाही करेगे।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि योजना मे 400 परसैट से भी ज्यादा वृद्धि हुई हे।

श्री अध्यक्ष: जौनापुरिया जी, यह बात संबंधित प्रश्न रवे संबंध नहीं रखती। आप सिर्फ सबंधित प्रश्न पर ही कोई पूरक प्रश्न पूछ सकते है।

Major Nirpender Singh Sangwan: Mr. Speaker Sir, in order to help serving and retired soldiers, Hon' ble Chief Minister had graciously announced defence colony in Dadri last year. The HUDA authorities had made a survey for this defence Sector quite some time back but nothing has happened thereafter. Sir, you will agree and appreciate that when the retired soldiers come back, they need a place to stay

but Dadri has no plot available for them to settle down. Therefore, it leads to unauthorized colonies coming up. May I request the Minister to tell us when this will be done ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमैंट्री मेन सवाल से ताल्लुक नहीं रखती है इसलिए मैं माननीय साथी से यह निवेदन करूगा कि वे लिख कर भिजवा दे। स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहूता हूं कि दादरी के अन्दर सैक्टर–8 और सैक्टर 9 के लिये 154.50 एकड जमीन का अधिग्रहण किया गया है जिसके लिए लैण्ड ऐक्विजीशन एक्ट की धारा 6 के तहत 20 फरवरी, 2003 को नोटिस हो गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जल्दी ही वहां पर दो सैक्टर डिवैल्प करेगा। स्पीकर साहब, इनका प्रश्न वायटिडली इस बात के लिए था कि हमारे फौज के जो रिटायर्ड अधिकारी है या पैरा–मिलिट्री फोर्सिज के अधिकारी हैं क्या डिफैंस के उन लोगो के लिए सरकार प्लाट काटेगी? अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि हमारे वे सिपाही जिन्होने देश की सीमाओं पर सेवा की है उनके लिए दादरी में हुड्डा सैक्टर काटेगा। इस समय दादरी के बारे मे जानकारी मेरे पास रेडीली अवेलेबल नहीं है, माननीय सदस्य को इसके बारे मे उत्तर भिजवा दिया जाएगा। श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे हल्के मे हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान उपलव्य करवाए जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष: नरेश जी, जो सवाल चल रहा हे वह हाउसिंग बोर्ड से सम्बन्धित नहीं है। जो सवाल चल रहा है वह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है, इसलिए आप बैठे।

Land aquired by Improvement Trust Dadri

***938. Major Nirpender Singh Sangwan:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) the exact acreage of land acquired by the Improvement Trust at Dadri; togetherwith its legal position at present; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a commercial complex and Stadium on the land referred to in (a) above ?

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhry):

(a) Yes, Sir, 46.51 acres of land has been acquired by the Improvement Trust, Charkhi Dadri and there is no Court case pending about this; and

(b) No, Sir, there is no proposal under consideration of the Government to construct a commercial complex on this land. However, proposal to construct a stadium on a part of the land is under consideration.

Major Nirpender Singh Sangwan: Sir, I would like to know can a commercial complex be cut out on a part of this land because you will appreciate that Municipal Committee at

Dadri have no means of revenue. Besides it, we cannot even pay our Salary bills or the electricity bills of the Municipality Committee. So, a commercial complex should be cut out there so that we can have some revenue in our Municipal Committee and we can pay the bills of the Municipal Committee.

Shri A.C. Chaudhary: Basically, the land was acquired for housing purposes but I thank the hon'ble Member to have attracted the attention of this August House regarding funding of Municipality Committee. I assure that in case the rules permit, **I** get it changed the use of land so that some commercial complex comes up.

Appointment of Guest Teacher

***855. Shri Randhir Singh:** Will the Education Minister be pleased to state the rules for appointing the guest teachers in the Education Department and whether these rules have been followed while making the said appointments; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): श्रीमान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

1 हरियाणा के सरकारी विद्यालयों मे अतिथि अध्यापको की भर्ती के लिये हिदायते दिनांक 29– 11 – 2005 जारी की गई थी, जिनकी एक प्रति अनुबन्द 'क' पर उपलब्ध है।

2 पहली हिदायतों को निवर्तित करते हुये पत्र दिनांक 16– 12 – 2005 के अन्तर्गत नई हिदायते की गई, जिनकी एक प्रति अनुबन्ध ' ख ' पर उपलब्द है।

3. दिनांक 27–9–2006 को और भी हिदायते जारी की गई, जिनकी एक प्रति अनुबन्ध 'ग ' पर उपलब्ध है। समय–समय पर जारी की गई उपरोक्त हिदायतो का विभाग द्वारा अनुसरण किया गया है।

अनुबन्ध ' क'

आदेश क्रमांक 15/59– 2005 तम (3)

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव

हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग

चण्डीगढ़।

सेवा मे

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।

विष्यः अध्यापकों के रिक्त पदों को अतिथि शिक्षक के आधार पर भरने बारे।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि अध्यापकों की कमी के कारण विद्यार्थियो की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2005 – 06 में अध्यापको के रिक्त पद अतिथि शिक्षक आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। अध्यापकों के संस्वीकृत पदो पर दिसम्बर 2005 से मार्च 2006 के मध्य तक

अतिथि शिक्षक आधार पर अध्यापको की नियुक्तिया की जायेगी। अतिथि शिक्षक आधार पर नियुक्तियां करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशो की पालना की जायेगी।

मानदण्डः

1 सम्बन्धित विद्यालय के प्राचार्य/मुख्याध्यापक को अध्यापको के सस्वीकृत पदो तथा छात्रों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये शिक्षको की कमी का निर्धारण करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्राध्यापको/मारटरों/ सी. एण्ड वी. अध्यापकों के लिये निर्धारित पीरियड की न्यूनतम सख्या क्रमशः 30,36 तथा 39 पीरियड प्रति सप्ताह है। यदि किसी विद्यालय में किसी विषय का पद रिक्त है अथवा पीरियड की मांग उक्त नार्म के अनुसार पूर्ण कार्यभार से अधिक है तो अतिथि शिक्षक का प्रबन्ध किया जायेगा।

3. ऐसी पेशकश प्रथमतः उन सेवानिवृत्त अध्यापको को की जायेगी जिन्होने राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त किये हो। यदि ऐसे सेवानिवृत अध्यापक उपलब्ध न हो तो संस्थान का मुखिया

नियमित अध्यापकों पर लागू निर्धारित अर्हताए रखने वाले अन्य व्यक्तियो को अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्त करेगा। इस प्रयोजनार्थ अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की शक्तियां प्राचार्य/मुख्याध्यापक को प्रत्यायोजित की जाती हे।

4. आवेदक द्वारा सीधी भर्ती के लिये पद हेतु सेवा नियमों मे निर्धारित सभी अर्हताएं पूर्ण की जानी चाहिएं। यह पेशकश निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं से बेहतर अर्हता रखने वाले उम्मीदवारो को की जायेगी।

प्रकिया

1 संस्थान का मुखिया रिक्तियों तथा कार्यभार के आधार पर अतिथि शिक्षकों के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति करेगा।

2. प्राचार्य/मुख्याध्यापक मांग का निर्धारण करने के पश्चात् मांग संस्थान के मुख्य द्वार पर लगाये गये सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा, तथापि नियुक्ति के लिये विस्तृत निबन्धनो का वर्णन करते हुये केन्द्रीकृत विज्ञापन/समाचार निदेशालय द्वारा जारी किया जायेगा।

3. आवेदको द्वारा विधिवत रूप से टाइप किये गये आवेदन पत्र एक विशिष्ट अवधि अर्थात् केवल नियुक्ति की तिथि से 31–3–2006 तक अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्ति की पेशकश करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

4. प्राचार्य/मुख्याध्यापक प्राप्त हुये आवेदन पत्रो पर कार्यवाही करेगा। यदि प्राचार्य/मुख्याध्यापक को प्राप्त आवेदन पत्र शैक्षिणक सत्र में रिक्तियों से अधिक हों तो वह शेक्षिणक मैरिट के आधार पर बनाई गई वरिष्ठता सूची के अनुसार उच्चतर शैक्षिणक मैरिट वाले आवेदको को प्राथमिकता देगा।

5 जैसे ही विद्यालय मे नियमित कर्मचारी (सीधी भर्ती द्वारा नियमित रूप से अथवा पदोन्नति के पश्चात) तैनात किया जाए सस्थान का मुखिया सम्बन्धित वर्ग के पद पर अतिथि अध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करेगा।

पारिश्रमिक

अतिथि शिक्षकों के रूप मे नियुक्त किये गये अध्यापको को निम्नलिखित विवरण अनुसार पारिश्रमिक/ मानदेय दिया जायेगा।

क्रमांक	वर्ग	अतिथि शिक्षकों हेतू प्रति पीरियड मानदेय
1	हिन्दी/सस्कृत/पंजाबी अध्यापक	50 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)
2.	पी. टी.आई. /	45 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम

	अध्यापक	तीन पीरियड प्रति दिन)
3.	मास्टर	55 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)
4.	विद्यालय प्राध्यापक	80 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)

अतिथि शिक्षको के रूप मे नियुक्त किये गए व्यक्तियों को वेतन विद्यालय मे उपलब्ध रिक्त पदो के समक्ष आहरित किया जायेगा।

दिनांक 29– 11 – 2005

आर. एस. गुजराल,

वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

शिक्षा विभाग, चण्डीगढ।

पृष्ठाकन क्रमांक 15/59– 2005 तम (3) दिनांक चण्डीगढ़ 29– 11 – 2005

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है . –

1 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

2. वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़।

3. उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।

4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।

5. निजी सचिव, आयुका एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।

6. राज्य मे स्थित सभी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक संस्थानो के मुखिया।

(हस्ता०–)

उप– सचिव शिक्षा

कुते वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

शिक्षा विभाग, चण्डीगढ।

अनुबन्ध 'ख'

आदेश क्रमांक 15/59– 2005 तम (3)

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव

हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग

चण्डीगढ़।

सेवा मे

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।

विषय अध्यापकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त करने बारे।

राज्य सरकार के आदेश क्रंमाक 15/59–2005 तम (3) दिनांक 29– 11 –2005 के अधिक्रमण मे। आपको निर्देश दिया जाता है कि अतिथि शिक्षको के रूप मे नियुक्तिया करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना की जाए: –

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्राचार्य/मुख्याध्यापक आहरण एवं वितरण अधिकारी (मुख्याध्यापक अथवा प्राचार्य का पद रिक्त होने तथा प्रारम्भिक विद्यालय के मामले में) को अध्यापको के संस्वीकृत पदों तथा छात्रो की संख्या को ध्यान मे रखते हुये शिक्षको की कमी का निर्धारण करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्राध्यापको/मास्टरो /सी.एण्ड वी. अध्यापकों के लिये निर्धारित पीरियड की न्यूनतम संख्या क्रमश: 30, 36 तथा 39 पीरियड प्रति सप्ताह है। यदि किसी विद्यालय में किसी विषय का पद रिक्त है अथवा पीरियड की आवश्यकता उक्त नार्म के अनुसार

पूर्ण कार्यभार से अधिक है तो अतिथि शिक्षक का प्रबन्ध किया जायेगा।

3. ऐसी पेशकश प्रथमतः उन सेवानिवृत्त अध्यापकों को की जायेगी जिन्होने राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त किये हो। यदि ऐसे सेवानिवृत्त अध्यापक उपलव्य न हों तो संस्थान का मुख्या नियमित अध्यापको पर लागू निर्धारित अर्हताएं रखने वाले अन्य व्यक्तियो को अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्त करेगा। इस प्रयोजनार्थ अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्ति करने की शक्तियां प्राचार्या मुख्याध्यापक/आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती है।

4. आवेदक द्वारा सीधी भर्ती के लिये पद हेतु सेवा नियमो मे निर्धारित सभी अर्हताए पूर्ण की जानी चाहिएं। यह पेशकश निर्धारित अर्हताओ (अन्तिम वर्ष परीक्षा तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा में प्राप्त अंको की प्रतिशतता का औसत) मे प्राप्त अकों के आधार पर की जायेगी। उच्चतर अर्हताओ को कोई अधिमान नहीं दिया जायेगा।

प्रक्रिया

1 संस्थान का मुखिया रिक्तियो तथा कार्यभार के आधार पर अतिथि शिक्षको के रूप में अध्यापकों की नियुक्तियां करेगा।

2. प्राचार्य/मुख्याध्यापक/ आहरण एवं वितरण अधिकारी मांग का निर्धारण करने के पश्चात् मांग सस्थान के

मुख्य द्वार पर लगाये गये सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा, जिन विद्यालयो मे प्राचार्य अथवा मुख्याध्यापक का पद रिक्त हो उनके मामले मे आहरण एव वितरण अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी माग का निर्धारण करेगा तथा माग प्रदर्शित करेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक विद्यालयो में अध्यापकों की मांग का निर्धारण भी करेगा।

3 आवेदकों द्वारा एक विशिष्ट अवधि अर्थात् केवल नियुक्ति की तिथि से 31 –3– 2006 तक अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्ति की पेशकश करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने चाहियें।

4. प्राचार्य/मुख्याध्यापक/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रो पर कार्यवाही करेगा। यदि प्राचार्य/मुख्याध्यापक/आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र शक्षिणक सत्र मे उपलब्ध रिक्तियो से अधिक हो तो वह उच्चतर शैक्षणिक मैरिट वाले आवेदको को प्राथमिकता देगा। किसी विशिष्ट विद्यालय मे अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्ति के लिये प्रथम अधिमान उसी गांव/कस्वे के निवासी उम्मीदवार को दिया जाना चाहिये। ऐसे उम्मीदवारो की मेरिट सूची तैयार की जानी चाहिए। यदि उसी गांव/कस्वे के निवासी अपेक्षित उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो उस खण्ड के निवासी उम्मीदवारो की मेरिट सूची तैयार की जाए। अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्ति के लिये द्वितीय प्राथमिकता सम्बन्धित खण्ड के निवासी उम्मीदवारो

को दी जानी चाहिए। तृतीय प्राथमिकता सम्बन्धित जिले के निवासी उम्मीदवारों को दी जानी चाहिए।

5 जैसे ही विद्यालय मे नियमित कर्मचारी (सीधी भर्ती द्वारा नियमित रूप से नियुक्ति अथवा पदोन्नति के पश्चात) अथवा समायोजन अथवा स्थानांतरण तैनात किया जाए। संस्थान का मुखिया सम्बन्धित वर्ग के पद पर अतिथि अध्यापक के रूप मे नियुक्त किये गये व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करेगा। यह नियुक्ति नहीं है बल्कि निर्धारित दरो पर पीरियड पर आधारित जॉब कार्य की पेशकश है। यह पेशकश जिन विद्यालयो मे नियमित अध्यापक उपलब्द नहीं हैं, उनमे विद्यार्थियो की पढाई हेतु व्यवस्था करने के लिये है।

पारिश्रमिक

अतिथि शिक्षको के रूप मे नियुक्ति किये गये अध्यापको को निम्नलिखित विवरण अनुसार पारिश्रमिक' मानदेय दिया जायेगा।

क्रमांक	वर्ग	अतिथि शिक्षकों हेतू प्रति पीरियड मानदेय
1.	हिन्दी / सस्कृत / पंजाबी अध्यापक	50 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)

2.	जे.बी.टी. अध्यापक/ ड्राईग अध्यापक	225 रुपये प्रतिदिन/ 45 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)
3	अध्यापक	55 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)
4	विद्यालय प्राध्यापक	60 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)

1 अतिथि शिक्षको के रूप में नियुक्त किये गए व्यक्तियों को अदायगी विद्यालय मे रिक्त पदो के लिये स्वीकृत बजट से की जायेगी।

2. यदि रिक्त पद न हो और किसी व्यक्ति की नियुक्ति अतिरिक्त कार्य भार के कारण की जाये तो अदायगी प्रतिकारक अनुशिक्षण के लिये स्वीकृत बजट से की जायेगी।

3. यह वित्त विभाग की सहमति की शर्त पर किया जायेगा।

अन्य दिशा निर्देश

1 निम्नलिखित वर्गो के पदों पर किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जायेगीः – –

(व)) पी.टी.आई.

(ख) डी.पी.ई.

(ग) मिडिल स्तर तक के विद्यालयो में ड्राईग अध्यापक

(घ) भीतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र के प्राध्यापक (क्योंकि इन विषयो के प्राध्यापक पहले से ही सरप्लस है।

2. अतिथि शिक्षको की नियुक्तियां मैरिट के आधार पर की जानी चाहिए।

हइ।एह? छा)त एा?।००58

तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिये। सभी योग्य उम्मीदवारो से 20–12–2005 को विद्यालय के कार्य समय के समाप्त होने तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाये। कार्य भार तथा रिक्ति के अनुसार मांग के आधार पर 21–12–2005 से अध्यापकों की नियुक्तियां की जानी चाहिये।

3 अदायगी के ढंग सहित सभी निबन्धन एवं शर्ते सस्थान के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध मे पारदर्शिता अपनाई जाये। अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त अध्यापक द्वारा पढ़ाये गये पीरियड का विवरण रजिस्टर मे दर्ज किया जाए।

4. ऐसे अध्यापको की नियुक्तियां उनको आबंटित किये जाने वाले पीरियड तथा किसी विशिष्ट विषय के समाविष्ट किये

जाने वाले पाठ्यक्रम का वर्णन करते हुये विशिष्ट अवधि के लिये इकरारनामे के आधार पर की जानी चाहिये।

5. अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्त अध्यापक निर्धारित निबन्धनो एवं शर्तों के अनुसार मास के अन्त मे अपना मासिक बिल प्रस्तुत करेगा।

दिनांक 29—11—2005

आर.एस. गुजराल,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

शिक्षा विभाग, चण्डीगढ।

पृष्ठाकन क्रमांक 15/59—2005 तम (3) दिनांक चण्डीगढ 16—12—2005

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ——

1 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

2. वित्तायुक्त एव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़।

3. उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़।

4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ।

5. निजी सचिव, आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।

6. राज्य मे स्थित सभी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक संस्थानो के मुखिया।

7 राज्य के सभी खंड शिक्षा अधिकारी।

(हस्ता०/–)

उप–सचिव शिक्षा

कुते वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, चण्डीगढ।

अनुबन्ध 'ग '

आदेश क्रमांक 15/59–2005 तम (3)

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव

हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़।

सेवा में

1 राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी

2. राज्य में सभी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एव जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी

3. राज्य के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी

विषय अध्यापकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त करने बारे।

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के यादी क्रमांक 15/59–2005 तम (3) दिनांक 29–11 –2005, 16–12–2005 तथा 26–05–2006 के संदर्भ मे।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि अध्यापको की कमी के कारण विद्यार्थियो की पढाई पर प्रतिकुल प्रभाव न पड़े सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2006–07 मे अध्यायको के रिक्त पद अतिथि शिक्षक आधार पर भरने का निर्णय लिया है। अध्यापको के संस्वीकृत पदो पर अतिथि शिक्षक आधार पर नियुक्तियां सम्बन्धित संस्थान के मुखिया /खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी। अतिथि शिक्षको के रूप में अध्यापको के पदों पर नियुक्तियां करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशो की पालना की जाये –

1 सम्बन्धित विद्यालय के प्राचार्य/मुख्याध्यापक/ आहरण एवं वितरण अधिकारी (मुख्याध्यापक अथवा प्राचार्य का पद रिक्त होने तथा प्रारम्भिक विद्यालय के मामले मे) को अध्यापकों के संस्वीकृत पदो तथा छात्रो की संख्या को ध्यान में रखते हुये शिक्षको की कमी का निर्धारण करने के लिये प्राधिकृत किया जाता

2 प्राध्यापको / मास्टरों / सी.एण्ड वी. अध्यापकों के लिये निर्धारित पीरियड की न्यूनतम संख्या क्रमशः 30,36 तथा 39 पीरियड प्रति सप्ताह है। यदि किसी विद्यालय मे किसी विषय का पद रिक्त है अथवा पीरियड की आवश्यकता उक्त नार्म के अनुसार पूर्ण कार्यभार से अधिक है तो अतिथि शिक्षक का प्रबन्ध किया जायेगा।

3. ऐसी पेशकश प्रथमतः उन सेवानिवृत्त अध्यापको को की जायेगी जिन्होने राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त किये हों अथवा विषय के ज्ञान के बारे में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। यदि ऐसे सेवानिवृत्त अध्यापक उपलब्द न हों तो सस्थान का मुखिया नियमित अध्यापको पर लागू निर्धारित अर्हताएं रखने वाले अन्य व्यक्तियो को अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्त करेगा। इस प्रयोजनार्थ अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की शक्तिया प्राचार्य / मुख्याध्यापक / आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती हैं।

4 आवेदक द्वारा सीधी भर्ती के लिये पद हेतु सेवा नियमो मे निर्धारित सभी अर्हताए पूर्ण की जानी चाहिएं। यह पेशकश केवल उन उम्मीदवारो को की जायेगी जो पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताओ से बेहतर अर्हताए रखते हो।

प्रक्रिया

1 संस्थान का मुखिया रिक्तियो तथा कार्यभार के आधार पर अतिथि शिक्षको के रूप मे अध्यापकों की नियुक्तियां करेगा।

2 प्राचार्य/मुख्याध्यापक/ आहरण एवं वितरण अधिकारी मांग का निर्धारण करने के पश्चात् मांग संस्थान के मुख्य द्वार पर लगाये गये सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। जिन विद्यालयों मे प्राचार्य अथवा मुख्याध्यापक का पद रिक्त हो उनके मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी मांग का निर्धारण करेगा तथा माग प्रदर्शित करेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक विद्यालयो मे अध्यापको की माग का निर्धारण भी करेगा।

3 आवेदको द्वारा माग के अनुसार अथवा नियमित कर्मचारी की नियुक्ति तक एक विशिष्ट अवधि के लिये अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुकि की पेशकश करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने चाहिये। 4. प्राचार्य/मुख्याध्यापक/आहरण एवं वितरण अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करेगा। यदि प्राचार्य/मुख्याध्यापक/आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र शेक्षिणक सत्र मे उपलब्ध रिक्तियो से अधिक हो तो वह उच्चतर शेक्षणिक मैरिट वाले आवेदको को प्राथमिकता देगा। किसी विशिष्ट विद्यालय मे अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्ति के लिये प्रथम अधिमान उसी गांव/कस्वे के निवासी उम्मीदवार को दिया जाना चाहिये। ऐसे उम्मीदवारो की मैरिट सूची तैयार की जानी चाहिए। यदि उसी गांव /कस्बे के निवासी अपेक्षित

उम्मीदवार उपलव्य न हो तो उस खण्ड के निवासी उम्मीदवारो की मैरिट सूची तैयार की जाए। अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्ति के लिये द्वितीय प्राथमिकता सम्बन्धित खण्ड के निवासी उम्मीदवारो को दी जानी चाहिए। तृतीय प्राथमिकता सम्बन्धित जिले के निवासी उम्मीदवारो को दी जानी चाहिए।

5. जैसे ही विद्यालय मे नियमित कर्मचारी (सीधी भर्ती द्वारा नियमित रूप से नियुक्ति अथवा पदोन्नति के पश्चात् समायोजन अथवा स्थानातरण) तैनात किया जाए संस्थान का मुखिया सम्बन्धित वर्ग के पद पर अतिथि अध्यापक के रूप मे नियुक्त किये गये व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करेगा। यह नियुक्ति नहीं हे बल्कि निर्धारित दरो पर पीरियड पर आधारित जॉब कार्य की पेशकश है। यह पेशकश जिन विद्यालयों में नियमित अध्यापक उपलब्द नहीं हैं, उनमें .विद्यार्थियों की पढाई हेतु व्यवस्था करने के लिये हे।

पारिश्रमिकः

अतिथि शिक्षको के रूप मे नियुक्ति किये गये अध्यापको को निम्नलिखित विवरण अनुसार पारिश्रमिक' मानदेय दिया जायेगा।

क्रमांक	वर्ग	अतिथि शिक्षकों हेतू प्रति पीरियड मानदेय

1	हिन्दी / सिस्कृत / पंजाबी अध्यापक	50 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतन तीन पीरियड प्रति दिन)
2.	जेबीटी, अध्यापक ड्राईंग अध्यापक	225 रुपये प्रतिदिन / 45 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)
3.	मास्टर	55 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)
4.	विद्यालय प्राध्यापक	60 रुपये प्रति पीरियड (न्यूनतम तीन पीरियड प्रति दिन)

1. अतिथि शिक्षको के रूप मे नियुक्त किये गए व्यक्तियो को अदायगी विद्यालय में रिक्त पदो के लिये स्वीकृत बजट से की जायेगी।

2. यदि रिक्त पद न हो ओर किसी व्यक्ति की नियुक्ति अतिरिक्त कार्य भार के कारण की जाये तो अदायगी प्रतिकारण अनुशिक्षण के लिये स्वीकृत बजट से की जायेगी।

3. यह वित्त विभाग की सहमति की शर्त पर किया जायेगा।

अन्य दिशा निर्देश

1 निम्नलिखित वर्गो के पदो पर किसी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जायेगी –

(क) पीटीआई.

(ख) डी, पी. ई.

(ग) मिडिल स्तर तक के विद्यालयों मे ड्राईग अध्यापक।

2. पूर्व मे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र के प्राध्यापको के पदों पर अतिथि शिक्षको की नियुकिाया करने पर प्रतिबन्ध था। अब संस्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षको की नियुक्तियां की जा सकती हैं।

3 अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्त अध्यापक नियुक्तिया करते समय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण नीति की पूर्ण रूप से पालना की जानी चाहिये।

4. अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां मैरिट के आधार पर की जानी चाहिए। Pick and choose तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिये।

5 अदायगी के ढंग सहित सभी निबन्धन एव शर्तें संस्थान के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध मे पारदर्शिता अपनाई जाये। अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्त

अध्यापक द्वारा पढ़ाये गये पीरियड का विवरण रजिस्टर मे दर्ज किया जाए।

6. ऐसे अध्यापको की नियुक्तियां उनको आबटित किये जाने वाले पीरियड तथा किसी विशिष्ट विषय के समाविष्ट किये जाने वाले पाठ्यक्रम का वर्णन करते हुये विशिष्ट अवधि के लिये इकरारनामे के आधार पर की जानी चाहियें।

7 अतिथि शिक्षक के रूप मे नियुक्त अध्यापक निर्धारित निबन्धनों एवं शर्तो के अनुसार मास के अन्त मे अपना मासिक बिल प्रस्तुत करेगा।

अन्य दिशा निर्देश

1 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका नं० 2743 ऑफ 2006, बलराज सिंह एव अन्य के मामले मे दिये गये निर्णय को जोकि विभाग के पत्र क्रमाक 15/56–2005 तम(3), दिनांक 26–5 –2006 द्वारा पारिचालित किया गया है, की दृढ़ता से पालना की जाये।

2. सभी सम्बन्धित संस्थाओ के मुखिया/खण्ड शिक्षा अधिकारी पिछले वर्ष के दौरान कार्य कर चुके अतिथि शिक्षको की सेवा जारी रखेगे। यह निर्णय इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 15/59– 2005 तम (3) दिनांक 26–5–2006 द्वारा पहले ही भेजा जा चुका है।

3. यदि पूर्व मे नियुक्त किये गये अतिथि शिक्षको की नियुक्तिया करने के पश्चात् रिक्तियां शेष रहती हैं तो सम्बन्धित संस्थानो के मुखिया/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अतिथि शिक्षक आधार पर नियुक्तियां करने के लिये नये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाने हैं।

4. वह व्यक्ति जो कि पूर्व मे अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किये गये थे, लेकिन अब छात्र संख्या कम होने तथा पीरियड कम हो जाने के कारण उनका समायोजन/नियुक्ति नहीं की जा सकती, उनके मामले संस्थानो के मुखिया द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को भेजे जाने थे और खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हे उन विद्यालयों मे समायोजित किया जाना था जहां उनके वर्ग की रिक्ति उपलब्ध हो।

5 यदि ऐसे व्यक्तियो को समायोजित करना खण्ड शिक्षा अधिकारियो के लिये संभव नहीं है तो वे उम्मीदवारो की पूर्ण सूची सहित मामले की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को देगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे अतिथि शिक्षको को उन विद्यालयों मे समायोजित करेगा जहां पर रिक्ति उपलब्ध हो। ऐसा उन हिदायतो के अनुसार किया जायेगा जो उन्हे पूर्व मे भेजी गई थी। यदि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है तो इन हिदायतो की पालना आगामी सात दिनों के अन्दर की जानी चाहिये।

6. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मामले मे आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जानी है तथा यदि ऐसे व्यक्तियो को समायोजित करना उसके लिये संभव नहीं है तो वह ऐसे सभी उम्मीदवारो की पूर्ण सूची सहित मामले की सूचना निदेशालय को भेजेगा। तत्पश्चात् निदेशालय ऐसे व्यक्तियों को जहां भी संभव हो, समायोजित करेगा।

7. यदि अतिथि शिक्षको के रूप में नियुक्त किये गये अध्यापको को परीक्षा ड्यूटी से सम्बन्धित कार्य सौपा जाता है तो उन्हें तदनुसार अदायगी की जायेगी। ऐसी ड्यूटी की अवधि अतिथि शिक्षक आधार पर नियुक्त अध्यापक को एकु दिन मे आबंटित पीरियड के समान समझी जाये। जिन अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त अध्यापको ने वर्ष 2005 –06 मे ड्यूटी दी थी उन्हें भी तदनुसार अदायगी की जाये।

8. यह सुझाव दिया जाता हे कि उपलव्य रिक्तियो के अनुसार नोटिस 30 सितम्बर से पूर्व लगाया जाये तथा उसके पश्चात् सात दिन का समय देते हुये स्कीनिग/नियुक्तिया आगामी सात दिनो के अन्दर की जायें। सभी रिक्तियां 15–10–2006 तक अवश्य भरी जायें तथा मामले मे किसी भी प्रकार की कोताही को गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा और सम्बन्धित संस्थान के मुखिया/खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

9. संस्थान का मुखिया अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त अध्यापक का रिकार्ड उन्हे पहले ही विभाग द्वारा भेजे गये अतिथि शिक्षक रजिस्टर मे रखेगा। इनकी प्रतियां जिला शिक्षा अधिकारियो से प्राप्त की जाये। अतिथि शिक्षको के अध्यापन के रिकार्ड के रख–रखाव के लिये अतिथि शिक्षक अध्यापन डायरी भी रखी जाये।

दिनांक 16– 9– 2006

आर.एस. गुजराल,

वित्तायुक्त एव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

शिक्षा विभाग, चण्डीगढ।

पृष्ठाकन क्रमाक 15/59– 2005 तम (3) दिनांक चण्डीगढ 27–9– 2006

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है: –

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

2 वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़।

3. उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ।

4. अतिरिक्त आयुका एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ।

5. निजी सचिव, आयुका एव महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ।

6. राज्य में स्थित सभी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक संस्थानों के मुखिया।

(हस्ता०/–)

उप–सचिव शिक्षा

कृते वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

शिक्षा विभाग, चण्डीगढ।

श्री रणधीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो गैस्ट टीचर्ज लगाए गए थे उनको रिलीव कर दिया गया है फिर भी इस साल जो गैस्ट टीचर्ज लगाए गए थे उनकी भर्ती मे कई प्रकार की अनियमितताएं बरती गई थी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि क्या माननीय मन्त्री महोदय उन अधिकारियो की इन्क्रवायरी करवाएगे जिन्होने ये अनियमितताएं की थीं?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, गैस्ट टीचर्ज लगाने के लिए सरकार की पॉलिसी के तहत बाकायदा नार्म्ज बने हुए थे और किसी भी हैडमास्टर और प्रिंसिपल ने कोई गैस्ट टीचर

लगाया तो उसमे कोई अनियमितता नहीं की गई। अगर कोई ऐसी शिकायत नोटिस में आई है तो उसके बारे मे पूरी कार्यवाही की गई है और किसी को भी किसी प्रकार की कोई रियायत नही दी गई है।

श्री उदय भान अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू कि स्कूलो में जो टीचर्ज रखे गये थे क्या उनकी भर्ती मे रिजर्वेशन की पॉलिसी का ध्यान रखा गया था और अगर पहले ध्यान नहीं रखा गया तो क्या अब आगे इसका ध्यान रखा जाएगा ?

श्री अध्यक्षः यह बात पहले आ चुकी है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, इसमे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लैवल पर कोई भर्ती नहीं की गई थी जिसमे परसैटेज के हिसाब से रिजर्वेशन में एस.सी. के लोगों को लगाया जा सकता। अगर किसी स्कूल मे एक टीचर की डिमाड थी तो एक टीचर लगा लिया गया उसमे रिजर्वेशन की परसैटेज नहीं बनती।

Mr. Speaker: Now , the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के

लिखित उत्तर

Zoning Plan for Kundli-Manesar-Paiwal Expressway

***885. Shri Karan Singh Dalai:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has planned any Zoning Plan along the KundliManesar-Palwal Expressway; and

(b) if so, the details of the Zoning Plan alongwith the agency which has prepared it and the cost incurred, thereon ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Status of Staff in Market Committee, Pataudi and Farukh Nagar

***866. Sh. Bhupinder Chaudhary:** Will the Agriculture Minister be pleased to state the staff strength of grade II to IV of market Committees, Pataudi and Farukha Nagar, District Gurgaon ?

कृषि मंत्री (सरदार एच.एस. चट्ठा): श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी गई है।

सूचना

ताराकित प्रश्न संख्या 866, मार्किट कमेटी, पटौदी तथा फरूखनगर मे द्वितीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के अमले की संख्या क्या है?

मार्किट कमेटी पटौदी तथा फरूखनगर में द्वितीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के अमले की संख्या निम्न प्रकार है: –

मार्किट कमेटी, पटौदी

द्वितीय श्रेणी 01

तृतीय श्रेणी 11

चतुर्थ श्रेणी 21

मार्किट कमेटी, फरूखनगर

द्वितीय श्रेणी 01

तृतीय श्रेणी 6

चतुर्थ श्रेणी 9

Construction of By-Pass for Bhiwani

***872. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj:** Will the **P.W.D. (B&R)** Minister be pleased to state whether the Government is aware of the fact that there is lot of increase in traffic congestion in the city of Bhiwani; if so, whether there is any proposal under consideration, of the Government to construct following by-passes to divert heavy traffic:--

1. Meham road to Rohtak road; and

2. Rohtak road to Dadri road?

सिंचाई मंत्री, (कैप्टन अजय सिंह यादव): नहीं, श्रीमान जी। अभी पूर्वोक्त बाई–पासिज को निर्मित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Supply of Elelctricity to the Agriculture Sector

***824. Dr. Sushil Indora:** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that less electricity has been supplied to the agricultural sector during the year 2006-07 than other sector like industrial and commercial in comparison to supply of electricity made in previous years; if so, the reasons thereof; and

(b) the steps taken by the Government to improve the electricity supply to the agricultural sector ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(ए) नहीं श्रीमान, वर्ष 2005–06 की तुलना मे वर्ष 2006–07 के दौरान कृषि क्षेत्र को बल्कि 744 प्रतिशत अधिक आपूर्ति दी गई हे। इसी तरह वाणिज्यिक क्षेत्रो समेत औद्योगिक तथा शहरी क्षेत्रो को क्रमशः 8.61 प्रतिशत तथा 713 प्रतिशत अधिक बिजली दी गई है। (बी) श्रीमान, कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

1 वर्ष 2007–08 के दोरान 24 नए 33 केवी. उपकेन्द्र जोड़े जा चुके है।

2. वर्ष 2007–08 के दौरान 24 वर्तमान 33 केवी. उपकेन्द्रो की क्षमता मे वृद्धि की गई है।

3. वर्ष 2007–08 के दौरान 269.11 केवी. ग्रामीण फीडसे के नलकुप भार से ग्रामीण घरेलू भार अलग कर दिया गया है।

4. वर्ष 2007–08 के दौरान 73 अधिभार वाले 11 केवी. ग्रामीण फीडसे का द्विभाजन/ त्रिभाजन कर दिया गया है।

Repair of P.H.Cs. of Siwani and Barva

***923. Shri Somvir Singh:** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of this fact that the buildings of Primary Health Centre, Siwani and Primary Health Centre, Barva are in dilapidated condition; if so, the time by which the said buildings are likely to be repaired; and

(b) whether it is a fact that the Government is not owner of the buildings/ lands as referred to in part (a) above; if so, the action taken by the Government to take over the ownership of these buildings/lands togetherwith the time by which the ownership will be taken over by the Government ?

(स्वास्थ्य मंत्री) बहन करतार देवी:

(क) श्रीमान जी, यह ठीक नहीं है कि सामान्य अस्पताल सिवानी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडवा के भवन जर्जर अवस्था में है।

(ख) सामान्य अस्पताल सिवानी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडवा के दान किए गए भवनों की मलकियत सरकार की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडवा की 55 कनाल 18 मरला भूमि व सामान्य अस्पताल सिवानी की 13 मरले भूमि स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित हो चुकी है। यद्यपि सामान्य अस्पताल सिवानी की 10 कनाल 10 मरला भूमि की मलकियत पुनर्वास विभाग की है। पुनर्वास विभाग को सामान्य अस्पताल सिवानी की भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। इस समय पुनर्वास विभाग से भूमि स्थानान्तरण बारे समय सीमा नहीं दी जा सकती।

Setting up 33K.V. Sub-stations

***932. Shri Naresh Yadav:** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up 33 K.V. substations at village Bajar and Gujarwas of Ateli constituency; if so, the time by which the work is likely to be started on the said sub-stations?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): श्रीमान जी, अटेली विधानसत्रा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव बाजड मे एक नये 33 केवी. बिजली उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष

2009–09 मे कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है। कार्य प्रारम्भ होने के 6 से 3 माह के भीतर इस उपकेन्द्र को चालू किया जा सकेगा। परन्तु गांव गूजरवास मे 33 केवी. बिजली उपकेन्द्र निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

To promote Cultivation of Cash Crops

***809. Dr. Sita Ram:** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to promote the cultivation of cash crops in the State and to provide the assistance to the farmers for this purpose; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार एच.एस. चट्ठा): नहीं श्रीमान् जी, फिर भी नकदी फसलों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमो के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस पर होने वाला खर्च भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी से वहन किया जाता है।

Information under R.T.I. Act .

***835. Sh. Shamsher Singh Surjewala:**Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date on which the R.T.I. Act came into force in the State of Haryana; and

(b) the total number of petitions seeking information filed before the State Information Commission upto 31-12-2007 since its constitution togetherwith the petitions pending and disposed off upto 31-01-2008 separately ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): श्री मान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

वक्तव्य

श्री शमशेर सिह सुरजेवाला, विधायक द्वारा सुथना का अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सूचना बारे पूछे। गये ताराकित प्रश्न क्रमांक 835 के सम्बन्ध मे भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, मुख्य मन्त्री, हरियाणा का (क) श्रीमान जी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत में, हरियाणा राज्य सहित

21 जून, 2005 को लागू हुआ है।

(ख) (1) श्रीमान जी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2003 की धारा 6(1) के तहत 31–10–2005 को आयोग के गठन से 31–12–2007 तक सूचना प्राप्त करने के लिये 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और सभी 22 आवेदन पत्रो का आयोग द्वारा 31–1–2008 से पूर्व निपटान कर दिया गया।

(2) श्रीमान जी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(2) के तहत आयोग के गठन से 31–12–2007 तक नागरिकों से 408 शिकायते प्राप्त हुई जिनमें से आयोग द्वारा 31–3–2006 तक 391 शिकायतो का निपटान कर दिया गया जबकि 31–1–2008 को 17 शिकायते लम्बित थी।

(3) श्रीमान जी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2003 की धारा 19(3) के तहत आयोग के गठन से 31–12–2007 तक नागरिको से 1195 अपील्ज प्राप्त हुई जिनमे से आयोग द्वारा 31–3–2008 तक 1041 अपील्ज का निपटान कर दिया गया जबकि 31–1–2006 को 154 अपील्ज लम्बित थी।

Works under Water Shed Scheme

***856. Shri Radhey Shyam Sharma:** Will the Agriculture Minister be pleased to state the names of those villages of Narnaul Constituency in which the works under the Watershed Scheme has been done during the period from March, 2005 to-date together with the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): श्रीमान जी, ब्यौरा सदन के पटल पर रखा है।

ब्यौरा

नारनौल विधान सभा क्षेत्र के गावो मे सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम की वाटर शैड स्कीम के अन्तर्गत मार्च, 2005 से अब तक करवाए गये कार्यो का ब्यौरा निम्न है: –

क्रम संख्या	वाटरशेड/गांव का नाम	किये गये कार्यो का क्षेत्र (हैक्टेयर	कुल खर्चा (रुपये लाखो

		मे)	मे)
1	गहेली–।।	96	4.59
2.	तलोट	89	2.61
3.	बसीरपुर–।।	431	20.17
4.	पंचनोटा–।।	34	4.43
5.	कोरियावास	85	2.41
6.	मोहनपुर	253	11.46
7.	बयाल	220	7.23
3.	गोलवा	167	11.09
9.	मेहरामपुर	272	14.76
10.	करोली– मरोली	237	7.52
11.	बुधवाल	264	12.96
12.	नगल दरगु	397	17.71
13.	मुकन्दपुरा–टेहला	471	23.56
14.	मरोली	280	11.78

15.	नयान–।।	374	18,59
16.	दताल	420	16.55
17.	डनचौली	181	11.59
18.	घानोटा	308	12.90
19.	बयाल–।।	208	11.39
20.	नियामतपुर	182	11.39
21.	छिनडालिया	76	6.00
22	मुकुंदपुरा	211	4.18
23.	शहबाजपुर	228	5.71
24.	शैदलीपुर	124	3.00
25.	रघुनाथपुरा–रसूलपुर	40	3.29
26.	हमीदपुर–खटोटी कलां	60	3.29
27.	जैनपुर–मौसमपुर–बिहारीपुर	72	3.29
28.	अमरपुरा	12	1.08
	कुल	**5792**	**264.53**

Forcible Occupation of D.H.B.V.N. Premises at Sirsa

***884. Shri Karan Singh Dalai:** Will the Power Minister be pleased to state -

(a) whether the residential area and Power House premises of DHBVN at Sirsa were forcibly occupied on 4th/5th December, 2004 by some miscreants; and

(b) if so, the action taken by the Government in this matter and the status of the possession of the premises together with the status of **the** civil and criminal cases pending in the matter along-with the names of the accused in the case ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) ही श्रीमान, द, ह. बि. वि. नि. की सिरसा में कुछ असामाजिक तत्वो ने 4 व 5 दिसम्बर, 2004 को रिहायशी एवं बिजली घर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। कब्जा किया गया कुल भूमि क्षेत्र 22 कनाल, 17 मरले है।

(ग) द. ह बि. वि .नि. द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ निम्नलिखित मुकद्दमें दर्ज करवाये गये हैं: –

1 दीवानी मुकद्दमाः –एक दीवानी मुकद्दमा मार्च, 2005 में दीवानी अदालत (वरिष्ठ डिवीजन) सिरसा के समक्ष विशेष रिलीफ एक्ट के तहत दायर किया गया था। श्री अजय पराशर, अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ सिरसा द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश 14– 6– 2005 को दिया गया जिसके द्वारा मै. वर्ल्डवाइड कैरियर को भूमि का स्थानांतरण करने से रोक दिया गया था। सुनवाई की

तिथि 18 – 7 – 2005 को तय हुई थी जो बाद मे मैं. वर्ल्डवाइड कैरियर द्वारा जवाबदावा दाखिल करने के लिये बढाकर 24– 10 – 2005 की गई। यह मुकद्दमा अब श्री अमरजीत सिंह, सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) सिरसा की अदालत मे स्थानान्तरित हो चुका है जिसमे सुनवाई की अगली तारीख 3 – 4– 2003 है।

2. मंडल आयुका हिसार के समक्ष केस न् द. ह बिविनि ने उप मण्डलअधिकारी (नागरिक) सिरसा के समक्ष नाम बदलाव की याचिका दायर की। उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) सिरसा ने 21 –4– 2006 को निगम के हक मे फैसला दिया जिसके आदेशानुसार जमीन का मलिकाना नाम व हक निगम के नाम हो गया। उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) के आदेश के खिलाफ श्री राम निवास मिडा सुपुत्र श्री लाल चन्द मिडा ने मण्डल आयुक्त हिसार के समक्ष याचिका दायर की जिसकी अगली सुनवाई की तारीख 29–4– 2009 है।

3. फौजदारी मुकद्दमाः– अभियुक्तो के खिलाफ फौजदारी मुकद्दमा श्री आर केडोगरा, सिविल जज, सिरसा की अदालत मे विचाराधीन है जिसमें पुलिस द्वारा निम्नलिखित अभियुक्तो के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है और जिसकी सुनवाई की अगली तिथि 29–3–2008 है।

1 श्री ब्रिज लाल सुपुत्र श्री रामेश्वर अग्रवाल

2. श्री गोबिन्द काडा सुपुत्र श्री मुरलीधर कांडा

3. श्री हरीश कुमार सुपुत्र श्री मदन लाल

4 श्री सुशील सुपुत्र श्री राम सरन दास

5. श्री विजय जूहीवाला इन्द्रपुरी मोहल्ला

6. श्री राम निवास सुपुत्र श्री लाल चन्द

7 श्री गोपाल काडा सुपुत्र श्री मुरलीधर

8. श्री अजय सुपुत्र श्री मंगत राम

Status of 220 K.V. Sub-station at Village Pahari

***867. Shri Bhupinder Chaudhary:** Will the Power Minister be pleased to state the status of the proposed 220 K.V. Sub-station at village Pahari in district Gurgaon ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): गांव पहाडी में 2 x 100 एम. वी. ए., 220/66/33 के. वी. की क्षमता के साथ एक 220 के. वी. उपकेन्द्र के निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Supply of Electricity to Delhi Metro Project

***849. Dr. Sushil Kumar Indora:** Will the Power Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the electricity of Haryana State is being supplied to the Metro of Delhi or for the completion of such kind of projects;

(b) if so, whether it is effecting the supply of electricity in the State; and

(c) the steps taken by the Govt. for the supply of electricity ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) नहीं श्रीमान, हरियाणा के द्वारा दिल्ली की मैट्रो को या इस प्रकार की किसी परियोजना को कोई बिजली नहीं दी जा रही है। हालांकि गुडगांव मे मैट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य हेतु निम्नलिखित अस्थायी कनैक्शन दिए गए हैं: –

(1) मैट्रो स्थानीय कार्यालय के लिए 25 किलोवाट,

(2) निर्माण कार्यो के लिए 20– 20 किलोवाट के दो कनैक्शन

(ख) प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।

(ग) 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1 2 x 300 मैगावाट यमुनानगर ताप विद्युतगृह की पहली इकाई का समक्रमण नवम्बर 2007 में किया जा चुका है तथा दूसरी इकाई का समक्रमण मार्च, 2008 को होना संभावित है। इन

दोनो यूनिटो के चालू होने के उपरान्त राज्य को लगभग 144 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली मिलेगी।

2 2x600 मैगावाट राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना, हिसार का निर्माण कार्य तेजी से बढ रहा है। इस परियोजना की पहली तथा दूसरी इकाई क्रमशः दिसम्बर, 2009 तथा मार्च, 2010 के दौरान चालू की जानी निर्धारित है।

3. कोयला आधारित 3x500 मैगावाट सुपर ताप विद्युत परियोजना झज्जर मे स्थापित की जा रही हे। इस परियोजना को हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय संघ क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. द्वारा संयुका उद्यम के रूप मे झज्जर में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना में हरियाणा का हिस्सा 750 मैगावाट का है। यह परियोजना वर्ष 2010– 11 के दौरान चालू की जानी निर्धारित है।

4. केन्द्रीय विद्युत निगमों (एन. टी. पी. सी., एन. एच.पी. सी., टिहरी, एस. जे. वी. एन. एल. तथा एन. ई. ई. पी. सी. ओ) द्वारा स्थापित की जा रही सभी परियोजनाओ जेसे कहलगांव चरण–।।, बढ़ चरण–। तथा।। चमेरा–।।।, सेवा –।।, कोलडम, किशनगगा एच. ई.पी, कोटलीबहल एच. ई. पी., कोटेश्वर एच. ई. पी. इत्यादि से बिजली लेने के लिए हरियाणा पॉवर जनरेशन कॉरपोरेशन ने अपनी सहमति दी है। एम. ओ. यू. 7 पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर किये हैं। इन सब परियोजनाओं से वर्ष 2011 – 12 तक

लगभग, 1000 मैगावाट बिजली प्राप्त होनी सम्भावित है। इनके इलावा करीब 36 मैगावाट मार्च 2006 मे, 24 मैगावाट 2008 – 09 के लिए और 217 मैगावाट 2009– 10 के लिए मिलनी आपेक्षित है।

5. निजी क्षेत्र मे विकसित की जा रही कुछ परियोजनाओ से विद्युत क्रय के लिए हरियाणा पॉवर जनरेशन कॉरपोरेशन ने पीटीसी. के साथ भी समझौतोएम. ओ यू. पर हस्ताक्षर किये है। इन परियोजनाओं से 2011 – 12 तक लगभग 770 मैगावाट बिजली मिलनी आपेक्षित है। इनमें से क्रमशः 370 मैगावाट 2009– 10 के लिये तथा शेष (400 मैगावाट) 2011 – 12 के लिये एम. ओ यू. / पी. पी. ए. किए गए है।

6. निजी क्षेत्र मे विकसित की जा रही 4 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं सासन, मुन्द्रा, उडीसा तथा झारखण्ड (प्रत्येक की क्षमता लगभग 4000 मैगावाट) से 1450 मैगावाट विद्युत लेने के लिए हरियाणा सरकार ने स्वीकृति प्रदान की हे।

7 केस–1 के अन्तर्गत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलियो के माध्यम से भी राज्य सरकार 2000 मैगावाट विद्युत क्रय के लिए प्रबन्ध कर रही है।

8. राज्य मे वर्तमान बिजली की माग को पूरा करने के लिए अल्पकालीन आधार पर बिजली क्रय के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

9. जिला झज्जर मे चरण–।। के अन्तर्गत 1150+–15% मैगावाट क्षमता का कोयले पर आधारित, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलियो के आधार पर स्थापित किए जा रहे प्लांट से बिजली क्रय की जाएगी। इस परियोजना के लिए हरियाणा भूमि, कोयला तथा पानी लिंकेज की व्यवस्था कर रहा है। इस परियोजना के लिए मार्च 2006 के अन्त तक लैटर ऑफ हन्टैट (एल.ओ.आई) दिया जाना सम्भावित है तथा यह परियोजना 2010–11 में चालू होनी सम्भावित है।

10. यमुनानगर मे 300 मैगावाट क्षमता की तीसरी इकाई स्थापित करने की योजना बनाई जा रही

घोषणा

विधायकों की विधान सभा से सदस्यता रद्द करने बारे

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that the following members namely; Sarvshri Rakesh Kamboj and Dharam Pal Singh Malik who had been elected from 11-Indri Assembly Constituency and 39-Gohana Assembly Constituency respectively have been disqualified from the membership of Haryana Vidhan Sabha under 10th Schedule to the Constitution of India and the rules framed thereunder with immediate effect i.e. 13th March, 2008 and consequently they ceased to be members of the Haryana Vidhan Sabha and their seats have fallen vacant in terms of Article 190(3) of the Constitution of India.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, discussion on the Governor's Address will resume. Yesterday, Prof. Chhattar Pal Singh was on his legs but now he is not present in the House. So, Shri Shamsher Singh Surjewala may speak on the Governor's Address.

श्री एस, एस. सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय, यह जो गवर्नर एड्रैस सदन मे पेश किया गया है मैं उस पर बोलने के लिए खडा हुआ हूं। इस पर सदन मे विपक्ष और ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से बहुत चर्चा हुई है। बहुत से काऊंटर क्लेम किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष मे ये जो आई. एन. एल.डी. के सदस्य बैठे हुए हैं, इन्होने हमेशा किसानो के नाम पर वोत् बटोरने का काम किया हे। इन लोगो ने अपने राज में हमेशा ही किसानों का अहित किया है। अध्यक्ष महोदय, हम श्रीमती सोनिया गांधी जी और सैन्टर मे जो यू.पी.ए. की सरकार है उसका इस देश के किसानों की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होने सीमान्त और छोटे किसानो के 60,000 करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए है। इस कर्जा माफी से अगर हम देखें कि कितने व्यक्तियो यानि कि किसानों को लाभ मिला होगा तो इसमे अगर हम मान ले कि एक परिवार मे पाच सदस्य किसान है तो एक ही परिवार के 20 करोड़ के करीब माफ हुए बनते है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह जग जाहिर है कि गावो मे शहरो के परिवारों की तरह छोटे–छोटे परिवार नहीं होते हैं

बल्कि बडे–बड़े परिवार हैं। इससे इस बारे मे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गावो में एक परिवार के 30 से 40 करोड परिवारो को फायदा हुआ है। अगर हरियाणा मे देखे तो एक परिवार मे लगभग 11 से 12 सदस्यो तक लाभान्वित हुए है। अध्यक्ष महोदय, अगर इसको भी हम पांच परिवार के सदस्यो के हिसाब से तकसीम करे तो यह अमाउन्ट भी 60 लाख के करीब प्रति किसान या प्रति व्यक्ति बनती है। (इस समय भी उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 451 करोड़ रुपये गांवो के गरीबो के कर्ज के माफ किए थे ओर 1600 करोड रुपये बिजली के बिलो के माफ किए थे। इसके मुकाबले में चौधरी देवी लाल जी के समय मे जिन्होने कि किसानों के कर्ज माफ करने का काफी प्रचार किया था, उनके समय मे केवल 33 करोड़ रुपये ही माफ किए गए थे। उनके मुकाबले मे इस वक्त की भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने जो कर्जे माफ किए है वे बहुत ज्यादा माफ किए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यूपी, ए. सरकार बनने के बाद हमारी केन्द्र सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश से किसानों के कर्ज का व्याज जो पहले 14 ओर 18 प्रतिशत०ची दर पर किसानो को देना पडता था, उसको घटाकर सात प्रतिशत किया और वर्तमान बजट में एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये सात प्रतिशत की ब्याज दर पर किसान को और गरीब आदमी को देने का प्रोविजन किया गया है जोकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से पिछली सरकार के वक्त मे गेहूं की एम एसपी. 650 रुपये

के करीब थी जिसको यू.पी.ए. की सरकार ने एक वर्ष मे साढ़े तीन सौ और चार सौ रुपये बढ़ाकर ज्यादा किया है। इसी प्रकार से जो धान की फसल थी उसमे प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी दिया। डिप्टी स्पीकर सर, इसके मुकाबले मे अगर एनडी.ए. की सरकार जिसकी कि ओम प्रकाश चौटाला और प्रकाश सिंह बादल धुरी रहे, के वक्त मे धान के रेट देखे तो वह बहुत कम थे। अगर ये दोनो नेता किसानो का फायदा करवाना चाहते तो करवा सकते थे और वह सरकार ऐसा कर भी सकती थी क्योकि इन दोनो के जो मैम्बर ऑफ पार्लियामैट थे वह उस सरकार को चलाने के लिए पर्याप्त थे। इनके बिना वह सरकार चल नहीं सकती थी लेकिन इन्होंने उस वक्त कोशिश नहीं की थी। डिप्टी स्पीकर सर, पांच साल के लम्बे एन. डी.ए. सरकार के कार्यकाल मे ओम प्रकाश चोटाला और प्रकाश सिंह बादल अपने– अपने प्रान्तो में मुख्यमंत्री थे लेकिन उस वक्त केवल चालीस रुपये गेहूं के और चालीस रुपये पैडी के एम. एस. पी. के बढाए गए जोकि बहुत ही शर्म की बात हे, बड़े ही दुख की बात हे। जबकि हमारी कांग्रेस सरकार ने सादे तीन सौ, चार सौ रुपये एक साल मे ही बढ़ाए है और इसके अतिरिक्त बोनस भी दिया है। आने वाले समय में अगली फसल मे किसान की जो पैडी आएगी तो वर्तमान सरकार उसकी कीमत बढ़ाकर एक हजार रुपये क्विंटल करेगी इस बात की किसानो को बड़ी भारी उम्मीद है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान भूपेन्द्र सिह हुडा की सरकार ने गन्ने का जो भाव है उसको बढ़ाकर 130 रुपये क्विंटल तक किसानो को दिया है

जबकि यही गन्ना ओम प्रकाश चौटाला के राज मे 80 रुपये क्विंटल पर किसानों को मजबूरी में बेचना पड़ा था। इतना बड़ा गैप यह जाहिर करता हे कि कौन सी सरकार किसान हितैषी सरकार है और कौन लोग किसान के नाम पर वोट बटोरकर किसान के हमेशा दुश्मन रहे है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला के राज में किसान की जमीन जो है वह दो से वार लाख रुपये प्रति एकड के बीच मे ऐक्वायर की गयी और उस सरकार के जाने के तुरन्त बाद जब वर्तमान सरकार हरियाणा मे आयी तो उसने 15 से 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के बीच कि राशि मे किसानो की जमीन ऐक्वायर की। इसके अलावा हमारी इस सरकार ने यह प्रोविजन भी किया कि अगर ऐसी जमीन ऐक्वायर होगी तो पैकेज के रूप में 33 वर्ष तक 15 हजार रुपये प्रति एकड किसान को मिलेगे। यह किसान के लाभ के लिए अपने आप मे एक बहुत०ंचा शिखर है, मापदण्ड है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस असैम्बली के द्वारा भारत सरकार से माग करता हूँ कि इस समय जो ब्याज दर सात प्रतिशत है उसको घटाकर पांच प्रतिशत किया जाए और जो गरीब आदमी हैं, जो भूमिहीन लोग है उनको तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज दिया जाए। यह हमारी मांग है। यदि लीग टर्म में किसान को फायदा करना है तो ऐसा करना ही होगा। एक वक्त मे कर्जा माफ करना भी एक बहुत बडी बात है इससे भी किसान अपनी जिन्दगी नये सिरे से शुरू कर सकता है। लेकिन अगर लम्बे समय तक ब्याज दर कम कर दी जाए तो किसान को और गरीब को फायदा होगा। इसी तरह से थी टायर

बैंकिग सिस्टम को भी अगर अबालिश कर दिया जाए और यदि गांव की सोसायटीज को ही बैंकिंग सिस्टम मे बदल दिया जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात कल ही हो सकती है यह मुमकिन है। हमारी सरकार भी चाहे तो ऐसा कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसान की जो पैदावार है, किसान की जो आर्थिक दशा है उसको इस्टैब्लिश करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि किसान की फसल का बीमा गांव के स्तर पर किया जाए। सभी फसलों का खास तौर पर कॉमर्शियल फसलो का बीमा किया जाए और उनको गांव की यूनिट मानकर बीमा किया जाए। वर्तमान में जो ब्लॉक और तहसील यूनिट मानकर बीमा किया गया है उसका लाभ किसान को नहीं मिल पा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसान की जो आमदनी है वही उसको सप्लीमैंट करने के लिए अलाइड प्रौफेशनल है इसमे डेरी है, पौल्ट्री है, फिशरीज है, बी फार्मिग है, मशरूम है ओर ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो कि वैल्यू ऐडिड सारे के सारे काम हैं इनको सरकार को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इस वक्त ये फील्ड बहुत कमजोर है इसलिए किसान की माली हालत अच्छी नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसान के अच्छे आर्थिक जीवन के लिए जरूरी है कि जो इस वक्त डीजल मे भारी मिलावट होती है। चार लाख या तीन लाख रुपये का ट्रैक्टर किसान लेता है और चूंकि डीजल मे मिलावट है इस वजह से छह महीने मे ही उसका इंजन बैठ जाता है और वह 50 हजार रुपये मे भी रिपेयर नहीं होता है और

किसान के पास इतना पैसा भी नहीं है। इस प्रकार से किसान आत्महत्या के कगार पर पहुंचता है। इसी प्रकार से नकली दवाइया, नकली खाद, नकली बीज, नकली इम्पुट्स और खेती में काम आने वाले जितने इम्पुट्स है इन में बहुत बडा धोखा हे। मै मांग करता हू कि जो वर्तमान कानून है वह इस बारे मे बहुत कमजोर है उसमे अमैडमैंट करके जो लोग मिलावट करते हैं उनके लिए कम से कम दस साल की कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और जो दोबारा मिलावट करते हुए पकड़ा जाए उसके लिए उस कैद का प्रावधान होना चाहिए। चीन मे नकली चीज बेचने वालों को फांसी की सजा दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि जो सीमान्त किसान खेती करते हैं उनका आर्थिक तौर से कायाकल्प कैटल ब्रीडिंग से हो सकता है। पशुधन बहुत बडा धन होता है। पशुधन को बनाये रखने के लिये पहले परम्परागत रूप से बहुत छोटी–छोटी जगहो पर डंगरो की मडियां लगती थीं। लोग गांव मे भैंस और गाय पालते थे और बहुत से दूसरे पशु पालते थे और उनको मडियो मे बेचकर उनकी अच्छी कीमत मिलती थी। उसमे पिछले 10–20 सालो मे बहुत ज्यादा क्षति हुई है। अन्ध कहीं ऐसे मेले देखने को नहीं मिलते हैं उसके कारण पशुधन में बहुत कमी आई है। आज उनके लिए कहीं शामलात जगह भी नहीं बची हे। इस बारे मे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। किसान चाहे भूमिहीन हैं, चाहे छोटे–छोटे किसान हैं ये बहुत अच्छे काश्तकार नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से जैसे जब तक मै अच्छा आदमी

नहीं हू, मैं अच्छा काम कैसे कर सकता हू। गांव की हालत आज इतनी खराब है कि वहा की जो 70– 75 प्रतिशत आबादी है वहा न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। इन दोनो का बिलकुल अभाव है, कोई इंतजाम नहीं है। आज गाय मे हजारो–हजारो लड़के बेरोजगार हैं जिन्होने दसवीं और दस जमा दो क्लास पास कर ली है लेकिन उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। जहां तक जमीन की जोत की बात है तो जमीन की जोत आज बहुत कम हो गई है। बेरोजगार लड़के परिवार के लिए और समाज के लिए एक बहुत बडा भारी खतरा बने हुए है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार सब प्राथमिकताओ मे से खर्चा कम करके गाव के तमाम स्कूलों का वर्तमान सिलेबस बदलवाकर व्यवसायिक शिक्षा को शुरू करे ताकि हमारे बच्चे दस जमा दो करने के बाद अपना खुद का काम करके अपने पैरो पर खडे हो सके और उनको रोजगार मिल सके। आज रोजगार के बेशुमार साधन हैं आज हमारी बेटियो को अगर नर्सिग की ट्रेनिंग दे दी जाये तो आज दुनिया और देश दोनो मे नर्सिग की इतनी मांग है कि हरियाणा की लाखो लडकियो और लड़को को नर्सिग के रोजगार मे भेज सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार आमूल–चूल परिवर्तन करके सभी कालेजो में जहां आर्टस और साईस के सब्जैक्ट्स पढाये जाते हैं उनको बदलकर प्रोफैशनल कोर्सिज शुरू करवाये, ताकि बच्चे वहां पढ़ सकें। जिन बच्चों को आर्टस और साईस के सब्जैक्ट्स पढने ही हैं वे यूनिवर्सिटीज मे जाकर दाखिला ले और वहां अपनी पढ़ाई करे क्योकि आज आम शहरो मे जो कालेज खुले हैं जहां आर्टस और

साईंस पढाई जाती है वहां पर गरीब आदमी के लडके लड़कियां अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण उनमे पढ़ने के बाद उनको मैडीकल कालेज ओर इंजीनियरिंग कालेज में कहीं पर दाखिला नहीं मिलता और वे किसी कम्पीटिशन मे जाने के योग्य भी नहीं होते हैं। इसलिए व्यवसायिक शिक्षा के कालेज खोले जायें। ऐसा ही प्रौफेशनल विषयों का एक कालेज कैथल मे मैंने मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिह हुड्डा के हाथों से खुलवाया है। मैं शिक्षा मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि वे ऐसे ही प्रोफैशनल कालेज हर शहर में खुलवाने की कोशिश करें। लेकिन एक बहुत ही कमजोर कदम – उठाया है इसको तेजी से उठाने की जरूरत है इसमे एक साल भी खराब नहीं होना चाहिए। आज आमूल–चूल परिवर्तन करके सभी कालेजो को प्रोफैशनल कालेज बनाने की जरूरत है और इस सारे ढाचे में परिवर्तन करने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं स्पोर्टस के बारे मे कहना चाहूंगा। आज पशु पालन और नौजवान लड़के हरियाणा मे देश मे नम्बर एक पर हैं। हमारे पास सारा मैटीरियल मौजूद है। हमारे बेटे बेटियां और नौजवान हृष्ट–पुष्ट हो सकते है अगर हमारे गावो मे मैडीकल सुविधा का इंतजाम ठीक हो जाये। मै भारत सरकार और हरियाणा सरकार से यह मांग करता हूं गाव के तमाम लोगों की हैल्थ का बीमा जरूरी होना चाहिए, क्योकि गांव के आदमी के पास आज इतनी आमदनी या पैसा नहीं है कि वह डाक्टरों से महंगा इलाज करवा सके और मंहगी दवाई खरीद सकें। इस हाउस के तमाम माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता है कि प्राईवेट डाक्टर आज

फीस के नाम पर इतनी खाल उतारते हैं कि कोई गरीब आदमी उनसे इलाज करवाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज बीमारियां भी पहले से ज्यादा हो गई हैं पहले कैंसर और ऐड्स जैसी बीमारी शहरो तक ही सीमित थी जो कि आज गांवों तक फैल गई है। कहते हैं कि टी. बी. की बीमारी बिलकुल खत्म हो चुकी है आज यह बीमारी हमारे बच्चों और महिलाओ में बेशुमार है। इसके लिए वे बेचारे इलाज नहीं करवा सकते क्योकि टीबी. का इलाज लम्बा है। मैं –चाहता हूं कि सभी का बीमा होना चाहिए ताकि वे बेचारे पैसे के अभाव में मरे नहीं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि स्पोर्टस के स्कोप हरियाणा के अन्दर बेशुमार हैं इसलिए सरकार को स्वास्थ्य के सुधार पर जोर देना चाहिए और खेलों की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। हरियाणा के हर जिले मे चाहे कालेज हो चाहे स्कुल हो, खेलो के इस्टीच्यूट होने चाहिए। हरियाणा मे एक से ज्यादा स्पोर्टस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और यह मै इसलिए कहता हूं कि आज जो देश मे विभिन्न खेलों के लिए कोचिज हैं, अभी हाकी के खेल की वजह से जो हमारे देश की दशा हुई है उससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाता है। एनडी. टी. वी. ने 3 दिन पहले खेलो के बारे सर्वे किया, 54 परसैंट लोगो का यह ख्याल है कि क्रिकेट दूसरे सारे खेलो को निगल गया है, खा गया है इसने सारे खेलो को खत्म कर दिया है। क्रिकेट मे इतना पैसा है, क्रिकेट में इतनी सोदेबाजी है कि टेलीविजन ओर क्रिकेट के जो इस्टीच्यूट्स हैं उन्होने मिलकर इसको कमर्शियलाइज कर दिया है। पूरे देश मे फुटबाल खत्म है,

वाली–वाल खत्म हे, बास्केट बाल खत्म है, जगह–जगह गाव मे भी बच्चे क्रिकेट के नाम से घूमते फिर रहे हैं, किसी और खेल की आज हरियाणा में बात नहीं हे इसलिए में चाहूगा कि क्रिकेट को प्राथमिकता न देकर जो यहा ट्रेडीशनल गेम्स रहे हैं, जिनमें हम दुनिया में आगे रहे है उनको आगे बढाया जाए। हरियाणा इन खेलों मे बहुत अग्रणी हो सकता है और हरियाणा के लाखो बच्चे इन गेम्स के कोच के तौर पर दुनिया मे और हिन्दुस्तान मे हरियाणा का नाम शाइन कर सकते हैं, उनको रोजगार मिल सकता है और ऐसे बच्चे अपने मां बाप का नाम भी रोशन कर सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजनीति मे अपराध का बड़ा भारी दखल हो चुका है। यह पूरे देश और समाज के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है, बडे दुख की बात है कि हरियाणा की राजनीति में भी अपराध के जन्मदाता, इनैलो के भाई हैं, जिन्होने 1960 के मिडिल में ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी और ग्रीन ब्रिगेड के नाम से अपराधियो की फौज बनाई थी, जिनके पास नाजायज कट् टे होते थे ये कट्टे वे यू. पी. और दूसरे जगहो से लेते थे। हमारे यहां भी कट्टे बनते थे उन कट्टो के बल पर वे ओं पर कब्जे करते थे और विरोधियो को जान से मार देते थे। हरिजनो, गरीबो, बाल्मीकि, बैकवर्ड क्लास और भूमिहीनो को डराते थे। इस प्रकार इन्होने पूरी तरह से राजनीति मे दखल देने के लिए अपराध की शुरुआत की। बडे–बडे अपराधियो के नेता के साथ इनके

डायरैक्ट सम्बन्ध रहे हैं। इनसे पहले हरियाणा की राजनीति मे अपराध का कोई नाम नहीं शा इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कानून जो देखता है कि अपराध न हो वहां राजनीतिक तौर पर इस सदन को यह देखने की जरूरत है कि कोई अपराधी इस सदन मे दाखिल न हो सके और उसके लिए स्पीकर को जो भी करना पड़े चूकि उपाध्यक्ष महोदय, आप स्पीकर साहब को रिपोर्ट कर देंगे इसलिए मैं कह रहा हू कि सरकार को इसके लिये चाहे कानून मे कोई भी बदलाव .करना पडे तो करना चाहिए कि उसमें जो अपराधी लोग है, कुख्यात बदमाश है जिनको सब जानते हैं कि ये अपराधी हैं, ऐसे लोगो का राजनीति में दखल नहीं होना चाहिए उनके वोटिंग के राइट खत्म होने चाहिएं, उनके चुने जाने के राइट खत्म होने चाहिए। इस वक्त भी अपराधी है और मुझे बहुत दु:ख है कि 1300 से ज्यादा विधायक और सांसद ऐसे है जिनके खिलाफ फौजदारी के मुकद्दमे चल रहे है, क्रिमिनल केस चल रहे हैं। उनमें से 65 ऐसे केस है जिनमे सी.बी. आई. द्वारा राजनेताओ के खिलाफ केस चलाए जा रहे है। ऐसे सब लोगो को दण्डित करने की जरूरत है इनको हाउस से एक्सपैल करने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे पार्टी बदलने पर दो विधायको को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि इनीशिएटिव लेकर इन लोगो को भी डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए जिनके खिलाफ सीबी आई. द्वारा और पुलिस द्वारा अपराध के मुकद्दमे दर्ज है। वे ऐसे दनदनाते फिर रहे हैं। यदि

इस बात का इलाज नहीं होगा तो समाज से प्रजातंत्र का नामो–निशान मिट जाएगा। (शोर एव व्यवधान)

आवाजें: हमारी विधान सभा मे ऐसा तो कोई नहीं है।

श्री एस. एस. सुरजेवाला: कौन कहता है नहीं है, आप कमेटी बनाकर पता करवाए, सबका रिकार्ड दिखला ले। जो नोमिनेशन फाइल किया था उसके साथ जो एफीडैविट है उसको दिखवा ले, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इनैलो के नेता और इनके विधायक और इनके सांसद हे, यह बात पूरा देश जानता है इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इन शब्दो के साथ उपाध्यक्ष महोदय मै आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

डा० सुशील इंदौरा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि माननीय साथी श्री सुरेजवाला जी जो बात कह रहे हैं वे इस बात को ऑथैंटिक करके सदन की टेबल पर रखे ताकि सबको सच्चाई का पता चले। बिना किसी सबूत के मेरे साथी सदन को बरगलाने की कोशिश न करे।

श्री एस.एस. सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, हमारी हाई कमान ने एक? कमेटी बनाई थी जिसने इनके नेता के और उनके परिवार के काले कारनामो की एक किताब छापी थी। उस किताब में इनके क्रिमिनल केसिज का ब्यौरा और एफिडेविट लगे हुए हैं।

11.00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अभिभाषण पढा है उसके लिए मैं उन्हे धन्यवाद देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार को भी मुबारकवाद देता हूं कि बहुत लम्बे अर्से के बाद इस प्रदेश के अंदर श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व मे सरकार ने एक नये तरीके से काम करना शुरू किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जहां श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे मुख्यमत्री रहे जिनके भय और डर के मारे प्रदेश के लोग बहुत तकलीफ मे जिन्दगी गुजारा करते थे। उस समय चाहे विधान सभा का सदन हो, चाहे हरियाणा मे कोई भी जिला हो, तहसील हो, शहर हो या गांव हो वहां ऐसी व्यवस्था को अंजाम दिया गया कि लोगों के अदर एक? भय का वातावरण स्पष्ट नजर आता था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लाखो करोडो पूर्वजो और बुजर्गों ने देश की आजादी हासिल करने के लिए अपने जीवन की कुर्बानियां दी और जंगे आजादी के लिए जेलो में भी गये। उस समय सभी यही सोचते थे कि हमारे देश में प्रजातंत्र होगा। अपने लोग होंगे जो अपने नुमाइदो को चुनकर भेजेगे और वे नुमाइंदे देश की, प्रदेश की तथा लोगो की भलाई के लिए अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था को अंजाम देगे। लेकिन चौटाला जैसे लोगो ने हमारी व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और लोगों का प्रजातंत्र पर जो विश्वास था उसको तोड़ने का काम किया है। उन्होने प्रजातंत्र का ऐसा मखौल बनाया यदि आज उनकी काली करतूतों और काले कारनामो को याद करते है तो

हम शर्मसार हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनके राज मे हमें बहुत ज्यादा गैर–व्यवस्था देखने को मिली जहां नौकरिया काबिलियत और योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए थी उनको इग्नौर करके अयोग्य लोगों को आगे लाया गया। उनके राज में अध्यापक जैसे पदो को भी नहीं बक्शा गया। जेबी. टीचर जो छोटे बच्चो को पढाते हैं उनकी भर्ती भी अयोग्य शिक्षको से की गई जिनमें पैसे का भी लेन–देन हुआ। आज जो हमारी सरकारी की शिक्षा है उससे हरियाणा के लोगो का भरोसा उठ गया है जो सरकारी स्कूल हैं वे चाहे गांवों मे हों या शहरो में लोग उनमे अपने बच्चों को भेजने से कतराने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ा विश्वासघात हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिस तरह का अपना अभिभाषण दिया है मैं उम्मीद करता हूं और परमपिता परमात्मा से भगवान से यह प्रार्थना करता हू कि वे ऐसे लोगो को चुनकर यहां नहीं भेजें। हम यहां पर लोगों का विश्वास लेकर आते है कि हम प्रदेश में हो रही गलतियो को होने से रोकेंगे और एक ऐसी व्यवस्था लोगों को देगे और उनकी इस तरह से सेवा करेगे कि लोगो को यह लगे कि हमारे द्वारा भेजा गया नेता किस तरीके से काम कर रहा है जिससे लोगो का और पूरे प्रदेश का भला होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता सुख भोगने के लिए न होकर सेवा का एक माध्यम होता है और अगर चुने हुए नुमाइंदे लोगों के भरोसे इस सदन में आकर सत्ता के नशे में चूर होकर अगर लोगों के विश्वास के साथ न्याय नहीं करते हैं तो इससे बड़ा अपराध और कोई और हो ही नहीं

सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कई विभागो के बारे मे विस्तृत तौर पर जो कहा है, उसका समर्थन करता हूं। इसमे जो किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही गई हे उसमें हमे इस बात की खुशी है कि पूरे देश की सुध लेने की शुरुआत हुई है और जो अन्न दाता है उसके लिए सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था रखी है इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। हम उम्मीद करते हैं कि वे किसान जिनकी हालत ठीक नहीं है और जिनकी हालत को पिछली सरकार ने उनकी फसलों के सही समय पर उचित मूल्य न देकर बिगाड़ा था, उस किसान की बिगडी हुई हालत को सुधारने के लिए बड़ी राहत सरकार ने दी है। यह एक प्रशंसनीय बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और इस सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह भारत सरकार से भी निवेदन करें कि किसानों के साथ गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, छोटे कर्मचारी हैं या वे लोग है जिन्होने सरकारी बैकों से या कोआपरेटिव सोसायटीज से कर्जा न लेकर प्राईवेट लोगो से कर्जा लिया हुआ है उनके बारे मे भी उनको कोई न कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए जिससे वे लोग भी इस फायदे मे शुमार हों और सरकार में अपना विश्वास जताकर इस देश को आगे बढाने का काम करे। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो इरीगेशन वाटर के बारे मे जो बात कही गई है आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर एक समुचित सिचाई व्यवस्था को अंजाम देने की जरूरत है। इसके

लिए जहां तक एसवाईएल. का सम्बन्ध है हमारा यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग पडा है। मै भगवान से इस बारे मे भी प्रार्थना करूंगा कि इस पर भी जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के हक मे निर्णय हो। अब तक इस एस. वाई. एल. कैनाल के मुद्दे पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी द्वारा बहुत ज्यादा राजनीति की जाती रही है और हरियाणा प्रदेश के लोगो को सपने दिखाये जाते रहे हैं कि एसवाई .एल. कैनाल का निर्माण और उसमें पानी लाने का काम सिर्फ वे ही करेगे। हमे इस बात का बेहद खेद है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी के लोग एस. वाई.एल कैनाल के नाम पर हरियाणा के लोगो के साथ हमेशा धोखा करते आये और उन्होने एक ऐसा ढोग किया, एक ऐसा दिखावा किया कि एसवाईएल. कैनाल मे पानी अगर कोई लायेगा तो वह श्री चौटाला जी ही लायेंगे जबकि असलियत यह हे कि पंजाब मे प्रकाश सिंह बादल के साथ मिलकर श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी के लोग हमेशा ही मिली भगत की राजनीति करते रहे और एस वाई. एल. कैनाल में पानी लाने के बजाय उन्होंने इस पानी को रोकने का ही काम किया और सच बात तो यह है कि पानी से पिछली सरकार का कोई लेना–देना ही नहीं था। मैंने कल भी सदन मे एक बात कही थी और आज फिर उसे दोहराना चाहता हूं कि इन लोगो को महसूस करना चाहिए और यह बड़े अफसोस की बात है कि जहां आज दुनिया में ई–गवनैंस और जो दूसरी आधुनिक टैक्नीक्स हैं उनकी जानकारी लेकर प्रदेश और सरकारी कार्यालयों को आगे बढाने के लिए लोग

सपने ले रहे है। दुनिया कहां की कहा पहुंच गई है। हमारे राजनैतिक दलो के नेता जो खुद अनपढ की तरह हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा से ज्यादा नहीं है, जिनके अन्दर पूरा ज्ञान नहीं है, वे इस प्रदेश को व्यवस्था क्या देगे? वे प्रदेश के लोगो को गुमराही और गुमनामी के अन्धेरे मे धकेलने का काम करते है जिससे वे लोग उन पर निर्भर रहे। उपाध्यक्ष महोदय, चौटाला जी ने तो ऐसे–ऐसे बुरे काम किये हैं कि जिससे पानी नहरों से नहीं बल्कि लोगो की आखो से निकले, ये क्या पानी लाने की बात करेंगे? हमारी सरकार ने पानी के समान बंटवारे को लेकर हाँसी बुटाना नहर का जो निर्माण कार्य शुरू किया है, वह प्रशंसनीय काम है। जब इस नहर का काम पूरा हो जायेगा तो दक्षिण हरियाणा के लोगो को उनके हिस्से का पानी मिलेगा और उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस इलाके से आते हैं आपके इलाके से लगा हुआ हमारा इलाका है। हम तो कामना करते है कि हमारे खेतो के लिए पानी भले ही न मिले लेकिन हमारे नालो मे कम से कम इतना पानी चले कि जो हमारे जमीन के नीचे खारा पानी है वह पानी मीठा हो जाये और हमारी बहन–बेटियो को, बच्चो को पीने का पानी मिल जाये। उसके लिए इस सरकार ने जो हाँसी बुटाना नहर का काम किया है वह एक प्रशसनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के लिए जो राहत दी गई है वह प्रशंसनीय कदम है। कृषि का काम पशु–पालन से जुडा हुआ है और पशुधन को बढावा दिये बिना कृषि को बढावा नहीं दिया जा सकता। आज हमारे बच्चे जो गाँवों में बेरोजगार बैठे हुए हैं मैं उम्मीद करता हूँ

कि अगर सरकार सस्ती व्याज दरों पर लोगो को गाय–भैंस खरीदने के लिए लोन दे दे तो हमारे बच्चे जो गाँवो मे बेरोजगार घूम रहे हैं वे गाय–भैंस पाल कर दूध का काम, डेयरी का काम कर सकते हैं। सरकार उनको सही तरीके से वित्तीय सहायता दे तो पशु धन मे बढोतरी होगी और वे अपनी आजीविका कमा सकेगे। जिस हरियाणा को दूध और दही के नाम से जाना जाता था आज उसी हरियाणा मे जब नकली दूध के केस पकड़े जाते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। फरीदाबाद, गुड़गाँव, पानीपत, करनाल और बडे–बड़े शहरो मे भी आज दूध की बड़ी भारी कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ इतनी राहत सरकार दे रही है वही कम से कम दूध और दही तो स्वच्छ मिले। उसके लिए चाहे सरकार को सबसिडी भी देनी पडे तो देनी चाहिए। गाँवो मे नौजवान बेरोजगार बच्चों को गाय भैंस फ्री मे देनी पड़े तो देनी चाहिए। हरियाणा सरकार के जो उपक्रम हैं उनको बढावा देना चाहिए ताकि कम से कम दूध तो हमे असली क्वालिटी का मिल सके। इसके लिए प्रयास करना चाहिए और हरियाणा में जो नकली दूध और नकली घी की शिकायत आ रही हैं उसके लिए हमारे महकमे को शिकजा कसना चाहिए। जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे मुर्राह नस्ल की भैंसो का नाम बहुत प्रचलित था वह हमारा बडा सौभाग्य था। मुर्राह नस्ल की भैंसो को बढ़ावा देने के लिए एक? बहुत अच्छी परियोजना पशुपालन विभाग

ने तैयार की थी। इस नस्ल को बढ़ाने को लिए इस नस्ल के कटडे व कटडियॉ तैयार करने के लिए बहुत अच्छी योजना थी लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं वह योजना कहीं खत्म हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से प्रार्थना करूँगा कि अगर भारत सरकार भी इसमें पैसा नहीं देती है तो हमारी सरकार का खजाना पैसे से भरा हुआ है, हरियाणा सरकार को खास तौर से मुर्राह भैंसो की प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए राहत देनी चाहिए। शिक्षा के मामले मे जो बात श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कही है मैं उनका समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा से हमारे बच्चो को रोजगार नहीं मिल पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्कूलो की चौकिंग के लिए जाता हूं और सरकारी स्कूलो मे जा कर बच्चो से किताब ले कर उनसे पूछता हू कि क्या पढाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी चिन्ता और शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती कि सरकारी स्कूलो में सरकार खजाने से एक बड़ी धनराशि खर्च करने मे लगी हुई है लेकिन बच्चो का शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। जो विषय बच्चो को पढ़ाया जा चुका था मैने उश्रके बारे मे उन्हे पूछा कि इसमे क्या है तो उनको उसके बारे मे कुछ पता नहीं था। यहा तक कि कई बार जब हम अध्यापकों से पूछते हैं तो अध्यापको तक को इस बात का पता नहीं होता कि जो विषय वे पढा रहे हैं उसके मायने क्या हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के ऐडीशनल डायरैक्टर को ले कर मैंने अम्बाला के प्रेम नगर स्कुल मे जा कर वहां की व्यवस्था को देखना चाहा और 7वीं

क्लास के बच्चो से जब मैंने पूछा कि आपको क्या पढाया जा रहा था। इस समय ऐडीशनल डायरैक्टर मेरे साथ थे, डी.ई. ओ और स्कूल की प्रिसिपल के मेरे साथ थे। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू का पाठ उनको पढाया जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनको वह पढाया गया है और क्या उन्हे वह पाठ आता है तो उन्होंने कहा कि हां यह पाठ पढ़ाया गया है और इसके बारे में उन्हे मालूम है। मैंने क्लास से पूछा कि बताईये कि यह सरदार भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव कौन थे। उपाध्यक्ष महोदय, पूरी क्लास मे एक भी बच्चा यह नहीं बता सका कि ये शहीद कौन थे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर स्कूलो मे शिक्षा का यह स्तर हे तो इससे तो हमारे बच्चो का समय और सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा हे और आने वाले दिनो मे यह प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। हमे अध्यापको और बच्चों मे इसके बारे मे जागृति लानी चाहिए। स्कूलो का जो सिलेबस है, वह तबदील करने पर हमे विचार करना होगा। हमे अपने स्कूलो के बच्चो को ये बाते बतानी होंगी ताकि उनकी उस के साथ उनकी कक्षा की पढाई के साथ जितना ज्ञान उनके अन्दर हो सकता है उसको वे समझ सकें तभी हम हरियाणा में अपने बच्चों में आत्म–विश्वास पैदा कर सकेगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी राशि स्वास्थ्य विभाग पर खर्च होती है इसमें सारे अस्पताल, डिस्पैंसरीज, प्राईमरी हैल्थ सैंटरज मे जो व्यवस्था है. उसमें सुधार की जरूरत है। (बुश समय माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, हमे इस बात पर विचार करना होगा

कि जो सार्थक व्यवस्था है वह सब अस्पतालो मे हो ताकि वहां लोगों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप कन्कलूड करें। आप कल भी बोल चुके हैं, आप इरीगेशन पर भी बोल चुके हैं और पॉल्युशन पर भी बोल चुके हैं। आप हैल्थ और इन्दर स्टेट विषय पर भी बोल चुके हैं। ऑनरेबल नये मैम्बरज बोलने के लिए बैठे हुये है उनको भी बोलना है इसलिए आप दो मिनट मे कन्कलूड करे

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरे 3 प्वायंट्स जिन्हें हैं मैं 2–3 मिनट्स में कन्कलूड कर दूंगा। स्पीकर सर, मैं आपकी मार्फत सभी चुने हुए नुमाइदों से अपील करता हूं कि विवाह–शादियो के नाम पर जो पाखण्ड प्रदेश के अन्दर चल रहा है वह बन्द होना चाहिए। प्रदेश के अन्दर शादियों के समय बड़े–बडे आयोजन किये जाते हैं, बहुत मंहगे महगे पकवान बनाए जाते हैं और बहुत से लोगों को आमन्त्रित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के विधायको और मन्त्रियो को एक नई पहल करनी चाहिए कि वे ऐसे अवसरों पर न तो बड़े आयोजन खुद करे और न ही ऐसी शादियो में जा कर शुमार हों। इस तरह की शादियो मे बड़ी तेजी से धुंआ उगलती हुए गाड़ियां निकलती हैं, सड़को के०पर गाडियो का भागना दौड़ना होता है और ट्रैफिक की समस्या होती है। यदि ऐसी पहल होती है तो इससे समाज मे बहुत बडा सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, उधर बच्चो के इम्तिहान

हो रहे होते हैं और इधर शादियों और सगाइयो मे बड़ी०ंची आवाज मे डी जे. बजा कर सारे मौहल्ले और गांव को सिर पर उठा लिए जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था देखती रहती है तथा उनको रोकने का कोई इन्तजाम नहीं होता है। मुहल्ल पडोस मे कोई बीमार है, पढने वाला विद्यार्थी है इस तेज आवाज से उनको बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि पूरे प्रदेश में इस डी.जे. के बजाने पर तुरन्त प्रभाव से पाबन्दी लगनी चाहिये जिससे कि मुहल्ले और गांव की व्यवस्था मे किसी प्रकार की कोई बात न हो। स्पीकर सर, फ्यूचर ट्रेडिंग ऐक्ट 1952 में पार्लियामैट ने पास किया था। इस फ्यूचर ट्रेडिग ऐक्ट के आने के बाद सौदेबाजी हो रही है जिसकी वजह से आए दिन हर चीज के दाम बढ़ते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि पार्लियामैंट ने 1952 मे इस ऐक्ट को लागू किया था और सात साल के बाद उन्होंने इसको बन्द करके विदड्रा कर लिया था लेकिन बी. जेपी. की सरकार जाते–जाते इसको रिवाईव कर गई और आज इस फ्यूचर ट्रेडिंग ऐक्ट की वजह से देश के अन्दर मंहगाई का बोलबाला चल रहा है। यह जो मंहगाई की मार है यह फ्यूचर ट्रेडिंग ऐक्ट की वजह से है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह फ्यूचर ट्रेडिंग ऐक्ट लागू होना है तो मैं इस बारे मे सरकार को सुझाव देना चाहूगा कि जितने भी बोर्ड और कारपोरेशंज हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वे बोर्ड और कारपोरेशंज इस फ्यूचर ट्रेडिंग ऐक्ट के तहत अपने आपको रजिस्टर करवाए ताकि वे बडे–बडे पैसे वाले प्राईवेट लोग किसानो

के साथ धोखा न कर सके क्योंकि पहले ही सौदेबाजी हो जाती है, उनकी मर्जी के मुताबिक ही रेटो का जिक्र किया जाता है। मेरा आखिरी सुझाव है कि जैसे हिमाचल में और दूसरे प्रदेशो में बाहर का आदमी आकर जमीन नहीं खरीद सकता है उसी तरह से हरियाणा में भी ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बाहर का आदमी आकर यहां पर जमीन न खरीद सके। आज इसकी वजह से हमारे छोटे–छोटे किसानो को बहुत नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा मे बाहर के लोगो पर जमीन खरीदने पर पाबन्दी होनी चाहिए। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल (अम्बाला कैंट): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने पर समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हू और सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं देश के प्रधान मंत्री और श्रीमती सोनिया गाधी ने देश के सीमान्त और छोटे किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। जब हरियाणा में काग्रेस की सरकार आई थी, उस वक्त किसानो के बिजली के 1600 करोड़ रुपये के बिलो को माफ किया गया, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री

जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करने का इतना बडा कदम उठाया था उसको देखकर हर प्रान्त के मुख्यमंत्री और राजनीतिज्ञो ने आश्चर्य प्रकट किया था। इनके इस कदम को देखते हुए ही केन्द्र की सरकार ने हमारे देश के सीमान्त किसानो और छोटे किसानो के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं इसके लिए फिर से उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस हरियाणा की सरकार के इन तीन वर्षों मे शिक्षा, विज्ञान, कृषि और दूसरे क्षेत्रों मे बहुत ही तरक्की हुई है। वर्ष 2005–07 मे हरियाणा सरकार का राजस्व की प्राप्ति 17,992 करोड रुपये हुई है। यह पिछले साल से 3 प्रतिशत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, यह जो लोगो के बैनीफिट के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जमीने ऐक्वायर की गई है और उन जमीनो का जो लोगो को मुआवजा दिया गया हे वह पूरे भारत में सबसे ज्यादा दिया गया है। इसी के साथ हरियाणा मे 2006–07 मे खाद्य पदार्थों का उत्पादन 147 लाख टन हुआ था और वह आज तक की सबसे ज्यादा पैदावार हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कितना ज्यादा ध्यान कृषि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उनका ध्यान कितना सफल रहा है। अध्यक्ष महोदय, पहले जो कोआप्रेटिव बैंकों में लोन की रिकवरी के वक्त मे गिरफ्तारी का प्रोविजन था उसको भी खत्म किया गया है तथा 451 करोड रुपये के व्याज भी माफ किए गये है। इसके अलावा यह भी घोषणा की गई है कि जो भी एक बार मे अपना मूल लोन वापिस कर देगा

उसको कई और तरह के लाभ दिए जाएगे। इसके अलावा हरियाणा में हर जिले मे हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं और अम्बाला मे तो यह पार्क बन चुका है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हू। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा मे जो सडको के निर्माण का कार्य हुआ और हरियाणा मे इण्डस्ट्री के उत्थान के लिए माननीय मुख्यमत्री जी ने कदम उठाए हैं उसकी वजह से इस सरकार के तीन साल के कार्यकाल मे हरियाणा मे एक किस्म से सड़कों का जाल सा बिछ गया है। बडे–बड़े ब्रिजिज बन गए हैं। इसकी वजह से हमे यह महसूस होता है कि आज से पहले हरियाणा को कभी इतना लाभ नही हुआ था। अध्यक्ष महोदय, अब मै शहरी विकास के बारे में बात करना चाहता हूं कि शहरी विकास के लिए कई स्कीम्स आई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन मे फरीदाबाद और पंचकुला को लिया गया है। इसमे फरीदाबाद के लिए 1,203 करोड़ रुपये से भी अधिक की सात विस्तृत परियोजनाओ वाली रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की गई हैं। उसमें से भारत सरकार ने 275.33 करोड़ रुपये की पांच विस्तृत परियोजनाओ को मंजूरी दे दी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन हे कि अम्बाला कैंट को भी इस जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी का एक अलग ही स्तर है। मै इस बात को सदन मे बताना चाहूंगा कि आजादी की जंग की पहली चिंगारी अम्बाला छावनी से पैदा हुई थी। 10 मई, 1857 को अम्बाला मे

बटालियन नं० 5 और 7 थी जिसने सबसे पहले अग्रेजो का विरोध किया था और घेराव किया था। उसके बाद यह चिंगारी अलग–अलग प्रान्तो मे फैली। मेरठ मे या दूसरे प्रान्तो मे इसके बाद ही यह चिंगारी फैली थी। सबसे पहले अम्बाला छावनी से ही आजादी की जंग की शुरुआत हुई थी इसलिए अम्बाला छावनी को विकास के नक्शे पर विशेष रूप से अलग से रखा जाए, ऐसी मेरी सरकार से गुजारिश है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन मे अगर अम्बाला छावनी आता है तो अम्बाला छावनी में बहुत ज्यादा तरक्की होगी और यह उन शहीदो के लिए यादगार भी रहेगा, जिन्होने अम्बाला छावनी में अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानिया दी। इसके अलावा पिछले तीन सालो में हमारी सरकार ने एजुकेशन मे भी बहुत काम किए हैं। कम्प्यूटर और एजुसेट के माध्यम से शिक्षा देने का काम किया जा रहा है जिसके कारण अब स्ट्रडैंट्स को एक नयी तरह की एजुकेशन मिलेगी। सर, मैं यह बात कहना चाहूंगा हालांकि यह बात मैंने शिक्षा मंत्री जी को भी कही थी कि स्कूलों मे विद्यार्थियों का स्तर बहुत नीचे है। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैंने सर्दियों में कुछ स्कूलों मे जाकर देखा है कि बच्चों के पास पहनने के लिए स्वैटर नहीं है, कपडे नहीं हैं, जूते चप्पलें नहीं हैं। हमसे तो जितना बन सका है उतना हमने उनको देकर मदद की है। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार की तरफ से ऐसी नीति बननी चाहिए ताकि उन विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके। सरकार द्वारा उन विद्यार्थियो की दैनिक जरूरतो की जो चीजे हैं, वह देनी

बहुत जरूरी है। सरकार यदि पहली से लेकर 12वीं क्लास तक शिक्षा मुफ्त कर देती है तो इसका बहुत ज्यादा लाभ विद्यार्थियो को होगा क्योकि अभी तक जो बच्चे वास्तव में गरीबी के कारण स्कूलो मे नहीं जा पाते हैं वे स्कूल जाना शुरू कर देगे और वे पढने मे सक्षम हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं हैल्थ के बारे मे भी कहना चाहूंगा। लिंगानुपात को सही करने के लिए सरकार की तरफ से काम किए गए हैं और अब भी स्टेबल बनाने की कोशिशें जारी है। इसके अलावा मैं अम्बाला छावनी सिविल अस्पताल के बारे मे कहना चाहूंगा हालाकि इसके बारे में मैने पहले भी कहा है कि इस सिविल अस्प्ताल की हालत बहुत खराब है क्योकि न तो वहां पर कोई इक्विमैंट्स हैं और न ही उस अस्पताल की प्रीपर बिल्डिंग है। वहां पर अभी भी वही बिल्डिंग है जो पिछले 50– 60 सालों से है जबकि अब पॉपुलेशन भी बढ गयी है, लोगो की सोच भी बदल गयी है और टैक्नालोजी भी बदल गयी है इसलिये मेरी सरकार से गुजारिश है कि अम्बाला के सिविल अस्पताल की बिल्डिंग को दोबारा बनाया जाए। इसके अलावा वहां पर स्लम बस्तियों में डिसपैसरीज भी बनाने की आवश्यकता है क्योंकि वहां के सिविल अस्पताल आने जाने में ही लोगो के तीस–तीस चालीस–चालीस रुपये खर्च हो जाते हैं इसलिए अगर स्लम बस्तियो मे डिसपैंसरीज बन जाएंगी तो लोगो को इतना खर्च भी नहीं करना पडेगा और उनको अपने घरों मे ही स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाएगी। इसी तरह से अम्बाला छावनी मे एक सुभाष पार्क है यह बीस एकड़ जमीन में बना हुआ है। यह

अरबो रुपयों की भूमि है। पिछले तीन सालों से इस पार्क की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गयी है। अभी लोग वहां बैठकर शराब पीकर झगड़ा करते हैं इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस पार्क का हुडा या किसी दूसरी अथौरिटी से नवीनीकरण कराया जाए ओर इसमें दोबारा से प्लांटेशन करवायी जाए। इसी तरह से पहले अम्बाला छावनी मे गुरू गोबिन्द सिंह जी के नाम से एक लाईब्रेरी खोलने का पत्थर रखा गया था लेकिन अभी तक भी इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। सिख भाई हमसे इसके बारे में पूछते हैं। वहां पर इसको बनाने के लिए जगह भी है सब कुछ है पैसा भी आया हुआ है लेकिन अभी भी इसका निर्माण होना बाकी है। लोगों की इसको बनाने की मांग भी है इसलिए मेरी गुजारिश है कि गुरू गोबिन्द सिंह के नाम से वहां पर लाईब्रेरी जरूर बनायी जाए।

श्री अध्यक्षः बंसल साहब, आप कन्कलुड करें।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसलः स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 1871 मे जब से अम्बाला बना था तब से लेकर अब तक अम्बाला छावनी के अंदर किसी भी तरह की प्रोपर्टी की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती थी क्योकि पूरे हरियाणा मे अम्बाला छावनी ही एक ऐसो जगह थी जिसकी जमीन केन्द्र सरकार के नाम थी लेकिन जब हमने इस बारे में मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की और जब उन्होंने केन्द्र सरकार से इस बारे में बात की तो उसके बाद अम्बाला छावनी की जमीन को

केन्द्र सरकार से हरियाणा सरकार को ट्रांसफर करवाया गया है। स्पीकर सर, तकरीबन 1000 एकड जमीन को तीन सालों मे ट्रांसफर करवाया गया और इसके बाद अम्बाला छावनी म्यूनिसिपल कमेटी में इस जमीन को ट्रांसफर करवाया गया। मेरी मांग है कि इस पौलिसी को जल्दी एडॉप्ट करके लोगो को लाभ दिया जाये। इससे 50–60 हजार लोगो को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के काम कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अम्बाला का जो प्रशासन है वह लोगों पर अत्याचार कर रहा है। वहां पर जिन लोगो के मकानो की लीज खत्म हो गयी है उन पर प्रशासन कब्जा कर रहा है जिसके कारण लोगो में बहुत ज्यादा रोष है, बहुत बडी दिक्कत हे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस कार्य को तुरन्त रोका जाए। इसके अलावा वहां पर जो डिफेंस के ऑफिसर्ज हैं वह मकानों को ताला लगाकर वहां रहने वाले हमारे दलित भाईयों, हरिजन भाईयो को तंग कर रहे हैं, उनको रौंदा जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है। पहले भी अम्बाला छावनी मे डिफैंस की एस्टेट ऑफिसर सुजाता गुजा ने आर्मी ऑफिसर्ज को साथ लेकर और अम्बाला सिविल फोर्स को लेकर उन हरिजनों के मकानो पर बुलडोजर चलवाया और उन पर अत्याचार किए। मैंने इस बारे में मुख्यमत्री जी से भी कहा था कि इन मकानों मे हमारे कमजोर वर्ग के भाई किराए पर रहते हैं ये पिछले तीस चालीस सालों से किराए पर रह रहे हैं, उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि अम्बाला छावनी में बहुत काम हुए हैं लेकिन अम्बाला

छावनी मे अभी भी 30 परसैट से ज्यादा स्लम एरिया है, जिसके अन्दर तेली मंडी, दीना मंडी, मोची मंडी, बाजीगर कालोनी, लालकुर्ती इलाके हैं। इनमे अभी तक कोई सुलभ शौचालय नहीं है न ही सडको का निर्माण हुआ है। मुख्यमत्री जी के प्रयासों से बाकी अम्बाला में 60 परसैंट सड़के बन चुकी हैं। 80–90 परसैंट पानी का अरेजमैंट हो चुका है। ये कुछ ऐसे इलाके बचे है जिनमे काम होना बाकी है। उनमे भी काम किया जाए। इन शब्दो के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान .लेता हूं।

श्री शादी लाल बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय अभिभाषण पर बोलने के लिये जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं. अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष पूर्व इस हरियाणा सरकार का गठन हुआ था और कुछ ही समय बाद आपने भी इस पद का कार्यभार संभाला था तो उस समय एक सोच आई थी कि हरियाणा की सबसे०ंची पंचायत मे जब सदस्य चुनकर आते हैं तो उनके बैठने का स्थान कैसा हो ताकि वे अपना योगदान हरियाणा के विकास के लिये दे सके। आपकी सोच और माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के सहयोग से इस भवन का कायाकल्प हुआ है। ऐसे वातावरण में बैठकर हम सुचारू रूप से सोच सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं ओर अच्छी प्रकार से सदन को चला सकते हैं और हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। तीन वर्ष पूर्व हालात क्या थे और आज हालात क्या हैं, दोनों का

मुकाबला करें और आकलन करे कि हरियाणा सरकार ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हरियाणा जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है इसकी 70 प्रतिशत आबादी गांवो मे रहती है चाहे वह किसान हैं, गरीब मजदूर हैं या छोटे दुकानदार हैं। अगर हरियाणा प्रदेश को हमने सारे देश का प्रथम प्रदेश बनाना है तो उसके लिए यह जरूरी है कि यह विकास गांवो से और किसान से शुरू हो। उस आबादी से शुरू हो, जो काफी पिछड़ चुकी है, उस से शुरू हो कर विकास आगे चले, तब बात बनती है। सबसे पहले बात आती है कि किसान का विकास कैसे हो ? जब इस सरकार का गठन हुआ था किसान पर कर्ज काफी ज्यादा हो चुका था। किसान का कर्ज माफ कर देना एक? बात है और किसान पर कर्ज क्यो हुआ, इसके लिए सरकार को चिंतन करना चाहिए। जब कोई छोटे से छोटा उद्योग लगाते हैं तो प्रौडक्शन कॉस्ट निकालते हैं लेकिन खेती ऐसी चीज है जिस पर कॉस्ट ऑफ प्रौडक्शन निकलती नहीं है बल्कि एम. एसपी. आ जाती है, सेलिंग प्राइज आ जाती है। यह केन्द्र सरकार तय करती है। पिछले पांच सालो मे 1० रुपये प्रति वर्ष एम. एसपी. मे बढौत्तरी होती थी। दस रुपये बढकर 640 से 650 रुपये पर खत्म हो जाती थी। जैसे ही इस प्रदेश की बागडोर हुड्डा साहब ने संभाली और देखा कि हरियाणा प्रदेश मे किसान की इतनी दुर्गति हो रही है तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार के हालात रहे तो हरियाणा प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। मुख्य मंत्री जी के प्रयासो के फलस्वरूप आज गेंहू की एमएस. पी. एक हजार रुपये हो चुकी है। हमें यह विचार भी करना चाहिए कि क्या

यह काफी है? हमे इस बात पर विचार करने की भी जरूरत है कि आज किसान की लागत क्या है और सेलिंग प्राइज क्या है? यह कंट्रोल कौन करेगा? बाकी जो उद्योग चल रहे हैं उनके मालिकों को यह अधिकार होता है कि किस भाव मे वस्तु बना रहे हैं और किस भाव मे बेचेंगे। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृषि उद्योग को इंडस्ट्री के रूप में मान्यता दी जाए तो शायद कुछ किसान का भला हो जाए। मान्यता की बात आने पर एक यह आर्गूमैंट आ सकता है कि किसान ने भाव बढा दिया तो आम आदमी क्या करेगा। आम गरीब आदमी के बारे मे भी इस सरकार को कुछ न कुछ चितन अवश्य करना चाहिए। एक बात यह भी है कि सारा बोझ एक वर्ग पर ही क्यो आए। दूध पर एम. एसपी. नही हे, डेरी प्रौडक्ट्स पर एमएस. पी. नहीं है, फिशरीज पर कोई एम. एस. पी. नहीं है। दूसरी कई चीजे हैं जिनको फार्मर्ज बाजार में ले जाते है और किस भाव मे बिकता है, यह सर्वविदित है। मैं चाहूंगा कि सिर्फ गेहूं और धान मे एमएसपी. होना काफी नहीं है इसके लिए हमे कुछ और करना चाहिये, कृषि को उद्योग का रूप दिया जाए ताकि इसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइज बराबर आ सके। मुख्यमंत्री जी ने जब इस प्रदेश का कार्यभार सभाला तो यह विचार भी किया कि कृषि में उत्पादन कैसे बढ़े? उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उन्होने कार्यवाही की उसके फलस्वरूप वर्ष 2006–07 मे उत्पादन कुल 141.58 लाख टन था लेकिन हुड्डा साहब के ऐफर्ट्स से उसी साल यह उत्पादन 147.63 लाख टन हो गया और इस साल वर्ष

2007–2008 मे जो निर्धारित उत्पादन है वह 152.45 लाख टन है। इसलिए उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। यह ठीक है कि इस प्रोडक्शन के पीछे और भी कई कारण हैं। एक तो पानी की सप्लाई का समान बटवारा हुआ है। हर खेत और जमीन जो पानी के प्यासे थे उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी का समान बटवारा किया गया है इसलिए भी उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इससे भी आगे जो कार्यवाही अब हो रही है उसके बारे मे विपक्ष के साथी कहते है कि यह हांसी–बुटाना लिंक नहर और दादुपुर नलवी नहर क्यो बनाई जा रही है। मैं नहीं समझता कि ये इस बात का विरोध क्यो कर रहे हैं और उनके मन में क्या है? उनके मन मे यह सोच है कि अगर यह नहर नहीं बनती है तो जो पानी हमारे पास चल रहा था वह चलता ही रहेगा। इसलिये ये पानी के समान बंटवारे का विरोध कर रहे हैं। एक भाग हरियाणा का हम स्वतंत्र कह ले और दूसरा गुलाम कह ले। हुड्डा साहब की यह सोच है कि हरियाणा के हर हिस्से में पानी का समान बटवारा होना चाहिए। नौकरियों मे समान बंटवारा हो और विकास मे बराबर की भागीदारी हो। मैं हुड्डा साहब का इस हाउस के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हुड्डा साहब की जो सोच थी वह बहुत अच्छी थी और उन्होने जो हरियाणा को दिया। (विघन)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, अमर उजाला अखबार मे चौटाला साहब का एक बयान है कि हांसी–बुटाना नहर की जरूरत नहीं। चौटाला साहब यहां पर

हाउस में कुछ कहते है और प्रैस मे जाकर कहते हें कि इस नहर को बनाने की जरूरत नहीं। यह तो रिकार्ड की बात है।

श्री अध्यक्ष कौन से अखबार की खबर है और किस तारीख का अखबार है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, यह 13–3–2008 के ''अमर उजाला' ' अखबार की खबर है। वे सदन में क्या कहते है और बाहर जाकर क्या बयान देते है। इसके बारे मे उनको हाउस मे स्पष्टीकरण देना चाहिए। इससे इनकी नीयत का पता चलता है। एक कहता है कि गृह युद्ध हो जायेगा, दूसरा कहता है कि इस नहर को बनाने की जरूरत नहीं है। इनकी दोहरी नीति। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, जब चौटाला साहब ने प्रैस मे यह बयान दिया तो मैं भी उनके साथ प्रैस मे मौजूद था। उन्होने प्रैस मे यह कहा था कि हरियाणा प्रदेश का ढांचा ऐसा है कि एक नहर से दूसरी नहर तक का पानी कहीं भी पहुचाया जा सकता है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है क्योकि सरकार ने इस नहर को बनाने के लिए भारत सरकार से पंक्चर करने की परमिशन भी नही ली है इस वजह से वह पैसा कहीं बर्बाद न हो जाए। होना तो यह चाहिए था कि पहले सरकार भाखड़ा नहर को पंक्चर करने के लिये भारत सरकार से परमिशन लेकर हांसी–बुटाना नहर बनाती तो कोई ऐतराज नहीं था, नहीं तो यह

पैसा खराब हो जाएगा। परमीशन लेने के बाद इस नहर को बनाना चाहिए था। माननीय मंत्री जी लाग लपेट लगाकर इस बात को बढ़ा रहे हैं? (विघन)

श्री नरेश कुमार प्रधानः अध्यक्ष महोदय, यदि एक? नहर से दूसरी नहर मे पानी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है तो हम 40 साल प्यासे क्यों मरे? दक्षिणी हरियाणा क्यों सुख– सूख कर मर रहा था। इन्होने काफी लम्बे समय तक राज किया था। पहले पानी क्यो नहीं पहुएचाया? सदन मे इन्होने यह कहा था कि हांसी–बुटाना नहर बनाने की जरूरत हे और हम हांसी बुटाना कैनाल को बनाने के लिए सहमत हैं। जब तक ये झूठ बोलना नहीं छोडेगे, हम भी इनका पीछा नहीं छोडेगे चाहे ये श्रीलंका तक चले जाये। हम इनका पीछा नहीं छोडेगे। (विघन)

श्री अध्यक्षः बत्तरा साहब, आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करे।

श्री शादी लाल बतराः अध्यक्ष महोदय, यह कन्ट्रोवर्सी तो थी कि हासी– बुटाना नहर बननी चाहिए या नहीं। लेकिन हरियाणा के विकास के लिए यह नहर बननी बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी नहर है जो आगे चलकर हरियाणा के हर हिस्से मे फसलों का उत्पादन बढायेगी। लेकिन विपक्ष के कुछ लोगों की सोच यह है कि सरकार ने ऐसा क्यो किया? मैं यह नहीं समझ पाया कि उनकी ऐसी सोच क्यों है? एक तरफ तो पानी का समान

बटवारा करने के लिए सरकार ने साधन जुटाये हैं और दूसरी तरफ एस. सी., बी सी. और जो गरीब आदमी कर्जे के नीचे दबे हुए थे। जिनकी खेती की जमीन थोडी है उनके कर्जे के ब्याज माफ किए हैं, जो भूमि विकास बैंक से लिए गये थे।

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, कन्कलूड कीजिए क्योकि आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं। 14– 15 मैम्बर्ज की लिस्ट आई हुई है। You please keep my limitation in view too.

श्री शादी लाल बतराः इसी प्रकार से कोआप्रेटिव बैंको के कर्ज के ब्याज माफ किए हैं और जो पूरी तरह किश्त दे रहे थे उनको टैक्स मे दो परसैट छूट मिल गई। जब केन्द्र सरकार ने यह देखा तो उसने भी 60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के कर्जे माफ कर दिए और इस पर भी इनका ऑब्जैक्शन आ रहा हे कि ये एरियर्ज भी माफ होने चाहिए थे, आउटस्टैण्डिग भी माफ होने चाहिए थे। अगर इन्हे ऑब्जैक्शन करना है और टैक्नीकलटीज पर जाना है तो ये अपने अंदर थोड़ा झांककर देखें कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होने किसानों के लिए क्या किया? अब जो किया गया है इनके मुताबिक यह अभी भी कम है जबकि इनको तो धन्यवाद करना चाहिए था उसकी बजाय ये इस बात को भी क्रिटीसाइज करके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय सीमा बांधी हुई है इसलिए अब मैं गवर्नर एड्रैस पर आ जाता हूं। जहां मैंने हाउस के माध्यम से यह मांग की है कि दूध के लिए, फिशरीज के लिए और खेती

के लिए भी एमएसपी. मुकर्रर हो और इनको कृषि का दर्जा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यदि आज हम देखे तो क्राइम पहले सें बहुत कम हुए हैं, ऐक्सीडैंट्स पहले से बहुत कम हो गए हैं लेकिन होते जरूर हैं। अगर जी.टी.रोड पर वायरलैस कैमरे लग जाएं और हर 15–20 किलोमीटर पर एक स्टेशन मन जाए ताकि कही भी कोई ऐक्सीडैंट या घटना होती है तो उसका केन्द्र में पता लग जाए और विघ्न 2 मिनट्स या विघ्न 5 मिनट्स मे यहां ऐकुलैस या क्रेन पहुंच जाए तो काफी जानें बच जाएंगी। जितने भी नैशनल हाइवेज हैं अगर वहां वायरलैस कैमरे लग जाते हैं तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा लेकिन इससे लोगो को सुविधा हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जहां हम कह रहे हैं कि आगे बढने के लिए सुख शांति चाहिए, हारमनी और भाई–चारा चाहिए तो उसके लिए हमें वायरलैस कैमरे चाहिएं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूगा कि जीटीरोड पर दिल्ली से हिसार तक, दिल्ली से जयपुर तक जो हरियाणा का एरिया है उस हरियाणा के एरिया में और शहरों मे जो भी हाइवेज हैं वहां वायरलैस कैमरे लग जाएं तो सरकार का गवरनैंस सुचारू रूप से चल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के मामले में कुछ कहना चाहूंगा। शिक्षा के लिए पहले 290 करोड़ रुपये का बजट था लेकिन 2007–08 में हमारी सरकार ने शिक्षा का बजट 540 करोड़ रुपये किया है। यह एक सराहनीय कदम है। कुछ सदस्यों के मन में सोच थी कि ऐजूकेशन की गुणवत्ता बढाई जाए। उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम आने वाली पीढियो को चाहे और कुछ दे पाएं या न दे पाएं लेकिन

ऐसी शिक्षा जरूर दें कि जिससे वे अपने पैरो पर खड़े होकर अपने मां बाप के साथ–साथ पूरे प्रदेश का नाम०ंचा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, डिलीवरी के टाइम जो मदर डैथ का रेट था वह 2005 से पहले एक लाख पर 300 था लेकिन अब यह कम होकर एक लाख पर 142 हो गया है, यह इस बात को दर्शाता है कि हैल्थ के प्रति यह सरकार कितनी जागरूक और कटिबद्ध है और कितनी सचेत है। अध्यक्ष महोदय, न्यू बोर्न बेबीज का डैथ रेट पहले 62 था, अब वह भी कम होकर 42 हो गया है। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र मे विवेक से काम किया है। इसके साथ–साथ मैं रिवैन्यू रिसीट्स का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। वर्ष 2004–05 में ये रिसीट्स 11149 करोड़ थे और वर्ष 2006–07 में 17952 करोड़ थी और वर्ष 2007–08 मे ये रिसीट्स 19630 करोड़ हो गई जो इस बात को दर्शाती हैं कि सरकार की गवरनैंस कैसी है, और खर्चे कैसे कम किए जाएं 9 इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं और इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए अध्यक्ष महोदय, मै आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री रणधीर सिंह (बरवाला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानो के लिए सराहनीय काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किसानों के लिए जो सबसे जरूरी और

अहम मुद्दा था, वह था कर्जा माफी। पिछली सरकार के मुख्यमत्री ने हरियाणा प्रदेश के किसानों से वायदे किए थे कि हरियाणा प्रदेश की जनता, आप मुझे वोट दो, मैं सभी किसानों के विल और अन्य कर्जे माफ करूंगा लेकिन उस मुख्यमंत्री ने बजाय कर्ज माफ करने के हरियाणा के किसानों के०पर लाठियों से जुर्म ढाए और कई किसानो को गोलियो से उड़ाया। लेकिन इस सरकार के मुख्यमंत्री ने कुर्सी पर आते ही एक सोच यह बनायी कि हरियाणा के किसानो की हालत पहले ही ठीक नहीं है और उन्होने हरियाणा प्रदेश के किसानों की इतनी दयनीय हालत को देखते हुये हरियाणा के किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बकाया बिल माफ करने का सबसे पहला कार्य किया। उसी के साथ–साथ हरियाणा प्रदेश के किसानो और गरीब भाइयो ने जो हरियाणा के बैंको से ऋण ले रखा था जिसकी डिफाल्डिग अमाउंट बहुत ज्यादा खडी हो गई थी उस पर हमारे मुख्यमंत्री ने विचार करके किसानों और गरीब भाइयों के कर्ज का ब्याज माफ करके वहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन प्रदेश की जनता की मुख्य मांग बिजली है। जनता की इस मांग को पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बिजली में सुधार करने के लिए और बिजली का उत्पादन बढाने के लिये विशेष कदम उठाये है जबकि आज से पहले जो भी सरकारें रही उन्होंने बिजली की बढती हुई मांग की तरफ कोई ध्यान नही दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी 5 हजार मैगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए

थर्मल पावर प्लांट लगवा रहे हैं जिनका काम जोरो पर चल रहा है। बिजली का मुद्दा हरियाणा प्रदेश के लिए अहम मुद्दा है, विपक्ष के साथी बार–बार इस मुद्दे को सदन में उठा भी रहे हैं। आज से दो दिन पहले श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसी सदन में बोलते हुए कहा कि एक भी यूनिट बिजली मौजूदा सरकार ने पैदा नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने बिजली की बढ़ती हुई मांग की तरफ ध्यान क्यो नहीं दिया और उन्होने एक भी जगह बिजली का उत्पादन बडाने के लिए कोई थर्मल पावर प्लांट क्यों नहीं लगाया जबकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा झाडली, यमुनानगर और खेदड आदि कई जगहो पर बिजली उत्पादन बढाने के लिये नये–नये थर्मल पावर प्लांट्स लगाये जा रहे है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से श्रम बस्तियो मे रहने वाले गरीब भाइयों को पीने का पानी मुहैया करवाने के लिये हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही अहम फैसला लिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने श्रम बस्तियों मे रहने वाले गरीब भाइयो को पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए 3 हजार पानी के कनैक्शन टूटी और टंकी के साथ फ्री देकर बहुत ही सराहनीय काम किया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश मे जितनी भी श्रम बस्तियां हैं उनमे मुफ्त पीने के पानी के कनैक्शन देने की जरूरत है। मेरे हल्के के कुछ एरियाज में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते

ही मेरे बरवाला हल्के मे पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए सैनेटरी बोर्ड की मीटिंग में 467 लाख रुपये की व्यवस्था की थी उसमें से 20 लाख रुपये अभी दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, बरवाला में स्लम बस्तियों में और हांसी– दौलतपुर रोड पर सरहेडा में बहुत बडा सैनी मौहल्ला है वहां पर बूस्टिंग स्टेशन लगाने की जरूरत है इसलिए इस ओर हमारे मुख्यमंत्री महोदय विशेष ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे मे जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले बजट मे 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि शिक्षा को बढावा देने के लिए हमे टैक्नीकल शिक्षा और नर्सिंग शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे साथी भाई कर्ण सिंह दलाल ने और माननीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने इस बारे में सदन मे विस्तार से बताया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पशु पालन को बढावा देने के लिये भी बहुत अच्छे कदम उठाये हैं। जैसा कि हमारे साथी कर्ण सिहं दलाल जी ने बताया कि हमारे प्रदेश के गरीब से गरीब तबके के लोग भी दूध बेचकर गुजारा कर सकते हैं। इसलिए पशु पालन के बारे में दलाल साहब ने जो योजना रखी है उसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि गरीब लोग गाय और भैंसें पालकर प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा दें और अपना गुजारा भी कर सके। इसी प्रकार से आज अगर उद्योग धंधों के बारे में देखा जाये तो हमारी सरकार आने के याद से हरियाणा प्रदेश मे उद्योगों की संख्या काफी बदी है। कल इस

सदन में जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला बैठे थे तो यह बात हो रही थी कि उनकी सरकार के समय मे कितने उद्योग–धंधे उनकी दमनकारी नीतियों और तानाशाही भय के कारण हरियाणा से पलायन कर गये थे। उद्योगों के बारे में हमारी सरकार की कल्याणकारी नीतियां और भयमुक्त व्यवस्था के कारण उद्योग–धंधों की संख्या बढती जा रही है और इससे हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश विकास की तरफ बढेगा और इससे चारो ओर खुशहाली होगी। हरियाणा प्रदेश मे सिचाई व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए मैं हरियाणा सरकार के सिचाई मंत्री और मुख्यमत्री. दोनो का धन्यवाद करता हूं। प्रदेश मे सिचाई व्यवस्था अच्छी बनाने के लिये हमारी सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये है। तीन बडी नहरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ– साथ पिछले 20– 30 साल से जो खाले और नाले कच्चे थे उनको पक्का करने का कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है। अनेक माईनर्ज बनाये जा रहे है जिनमे से मेरे हल्के में भी दो माईनर बनाये गये है। इन सबके लिये मैं माननीय सिंचाई मन्त्री और माननीय मुख्यमंत्री को बार–बार धन्यवाद करना चाहता हूं। जब बात सडको की आती है तो सड़को के मामले मे भी हरियाणा नम्बर वन प्रदेश है। नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज की अच्छी हालत के साथ– साथ अच्छी लिंक रोड्स का भी जाल बिछाया जा रहा है और जिनकी हालत ठीक नहीं है उनकी मुरम्मत का काम भी युद्धस्तर पर चल रहा है। मेरे हल्के की कुछ सड़को के लिए मैंने माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मन्त्री जी से बात की तो

उन्होने मुझे आश्वासन दिया कि उन्हे जल्दी ही रिपेयर करवा दिया जायेगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हू। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विजली मंत्री जी को अपने हल्के की बिजली की समस्या के बारे मे बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में किसानों को 100 कनैक्शनज देने का कार्यक्रम पिछले 4 साल पहले किया गया था लेकिन उन कनैक्यानज को सम्बन्धित किसानो को देने का काम अभी तक भी कम्पलीट नहीं किया गया है। उनमे से 11 कनैक्शनज ऐसे हैं, जिनका 2004 मे टैण्डर हुआ और उनके०पर यह लिखा गया कि यह डिस्पयूटिड है। मेरी सरकार से माग है कि किसान को बिजली जरूर मिलनी चाहिए क्योकि यह किसान की खेती–बाडी से जुडा हुआ मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस किस्म के जो मामले है उनका जल्दी से निपटारा करके किसानो के लम्बित कनेक्शनज जल्दी दिये जाये। इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से लोकल बॉडी मिनिस्टर से मांग करता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बरवाला एक मध्यम दर्जे का शहर है उसका समुचित सुधार किया जाते। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने पैसा काफी दिया है लेकिन मेरे हल्के का अभी तक 30 प्रतिशत ही सुधार हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि बरवाला शहर के सम्पूर्ण विकास के लिए और ज्यादा पैसा दिया जाये। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रामफल चिडाना (बडोदा, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, किसानो के कर्जे माफ करने के बारे मे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा हुई और बड़े जोर–शोर से इस पर वाह–वाही लुटने की बाते हुई। स्पीकर सर, मै आपको बताना चाहता हूं कि हमारा किसान सिर्फ सरकारी बैको से ही लोन नहीं लेता, उस पर साहूकारो का भी कर्ज है और उनका ब्याज भी ज्यादा होता है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है किसानो का कर्जा माफ होना चाहिए क्योंकि किसान इस देश की रीड की हड्डी है लेकिन इसके साथ–साथ गरीब आदमी भी हैं उनके बारे मे भी कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिए। जब तक इस देश का किसान आत्महत्या करनी बन्द नहीं कर देता तब तक कर्ज माफी का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था करनी पडेगी जिससे प्रदेश का किसान आत्महत्या न करे। जब भी किसी सरकार का आखिरी बजट होता है उसमे किसानो की सुध ली जाती है। 3–4 साल पहले जो किसानो की आत्महत्या की दर थी अगर उस समय कोई व्यवस्था की जाती तो यह दर अगर कम नहीं होती तो बढ़ती भी नही। जिस समय सरकार बनी उसी समय से किसानो के बारे मे सोचना चाहिए था। हर बार अंतिम वर्ष मे किसानों की सुध ली जाती है ताकि उनके वोट मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ कि चौधरी देवी लाल जी ने पहली यार बुढापा पैशन लागू की थी। आज एक परिवार के

एक सदस्य को 300 रुपये प्रति मास मिलते हैं। इस हिसाब से पति–पत्नी को 600 रुपये प्रति मास मिलते हैं और एक साल मैं 7200 रुपये और 5 साल में 36000 रुपये एक परिवार को मिलते हैं। यह रकम भले ही कम है लेकिन सरकार को और नियम बनाने चाहिएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगो को फायदा हो, हरेक आदमी खुशहाल हो। अध्यक्ष महोदय, आप लोगो ने चर्चा की कि हम गरीब लोगो को 100– 100 गज के प्लाट दिये जाये। अध्यक्ष महोदय, 100 गज के प्लाट से कुछ नहीं होता। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मैंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है। घर मे छोटी से छोटी बीमारी पर भी बहुत खर्च आ जाता है, बच्चो को पढाना पड़ता है। लडके–लडकियो की शादी करनी पड़ती है। गरीब आदमी के पास आमदनी का कोई साधन नहीं होता। इसलिए वह सोचता है कि इस प्लाट को ही बेच दिया जाये ताकि दह अपने खर्चे निकाल सके। प्लाट के०पर मकान बनाना भी बहुत महंगा हो गया है। लोहा आज 40 से 50 रुपये प्रति किलो हो गया है। ईंट और सीमेंट भी बहुत मंहगा हो गया है। ऐसे मे एक गरीब आदमी कैसे मकान बना सकता है? जहाँ तक पानी की टंकी मुफ्त देने की बात है तो मेरा कहना है कि पानी की टंकी से कुछ नही होगा उनको रोजी–रोटी भी देनी होगी। मैं इस बात का तो समर्थन करता हूँ कि किसान को गेहूँ का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए लेकिन गरीब परिवारो के लिए भी सरकार को कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। एक गरीब आदमी 15–16 रुपये प्रति किलो के भाव का आटा कैसे खरीद सकता है? गेहूँ

और चावल इतना महंगा हो गया है कि उसकी पहुंच से बाहर है। अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार सब्सिडी देकर उनके लिए गेहूँ और चावल उपलब्ध नहीं करवायेगी तब तक गरीब आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वजीफे का प्रावधान किया है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी चाहे किसी भी जाति का हो अगर वह पढाई में अच्छे नम्बर लेता है तो उसको वजीफा मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान मे यह बात भी लाना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में अध्यापको की भारी कमी है। गरीब आदमी प्राईवेट स्कुलों मे तो बच्चो को भेज नहीं पाता और सरकारी स्कूलों मे अध्यापको की कमी है। इसलिए मेरा कहना है कि वजीफे की राशि को तो परिवार के लोग घर के काम में ही खर्च कर देते है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूगा कि स्कूलों मे अध्यापक पूरे होने चाहिएं। आजकल स्कूलों मे अध्यापक गलत काम भी करने लग गये हैं। हमने अखबारो मे पढा है कि स्कूलों में लड़कियो के साथ बलात्कार होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि संविधान के 50वे संशोधन को केन्द्र सरकार ने लागू किया है, लेकिन हरियाणा सरकार को भी वह संशोधन 1995 से लागू करना चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि

स्कूलों में लडकियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार सिर्फ स्कूलो मे ही नहीं होते। इस तरह का हादसा घर मे भी या किसी भी पार्टिकुलर जगह पर हो सकता है।

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी): अध्यक्ष महोदय, I am on a point of order माननीय सदस्य ने यह कहा है कि बुढ़ापा पैशन योजना चौधरी देवी लाल ने चालू की थी। मै इस महान सदन की जानकारी के लिए सदन का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि यह बुढ़ापा पैशन स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चालू की थी और उस वक्त इस पैशन के तहत 60/– रुपये मिला करते थे। स्पीकर सर, मैं जब समाज कल्याण मन्त्री थी उस वक्त माननीय सुरजेवाला जी की अध्यक्षता में एक? कमेटी बनी थी जिसने यह रिक्मैंड किया था कि यह 600/– रुपये की राशि थोड़ी है और इस राशि को बढ़ा कर कम से कम 100/– रुपये किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, अगले जो इलैक्शन हुए उसमे हमारी सरकार नहीं आई और चौधरी देवी लाल जी की सरकार आ गई। यह राशि 60/– रुपये से बढा कर 100/– रुपये करने का क्रैडिट तो चौधरी देवी लाल जी की सरकार को जाता है लेकिन पैंशन शुरू करने का क्रैडिट उनकी सरकार को नहीं है बल्कि पहली बार बुढापा पैंशन शुरू करने का क्रैडिट श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार को है।

श्री रामफल चिड़ाना: स्पीकर सर, माननीय मन्त्री महोदया जी ने जो बताया है मैं उसको मानता हूँ। यह बात ठीक

है लेकिन चौधरी देवी लाल जी ने यह पैशन राशि 100/– रुपये की थी और फिर उसके बाद 2007– रुपये की बुढ़ापा पैंशन चौधरी देवी लाल के कहने पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की थी। मैं यह महसूस करता हूँ कि इस राशि को बढा कर कम से कम 500/– रुपये किया जाना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार इस राशि को 500/– रुपये करने से क्यों हिचकिचाती है। हरियाणा सरकार भी इसका क्रैडिट ले सकती है वह राशि को क्यो नहीं बढाती है। बुढापा पैशन की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं 50वे संविधान संशोधन की बात करता हूँ जो 1995 से लागू होना चाहिए था। (विघन) यह संविधान सशोधन सरकार ने 2006 से लागू किया है जबकि यह 1995 से लागू होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, अस्पतालो मे डॉक्टरो की कमी है। हमारे गरीब आदमी प्राईवेट अस्पतालो में इलाज नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वहां पर डॉक्टरो की फीस बहुत ही महगी है और उन अस्पतालो मे लोगो को बहुत ही महंगी–महगी दवाईयां लेनी पड़ती हैं। स्पीकर सर, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकारी अस्पतालों मे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरो को लगाया जाना चाहिए। सभी अस्पतालो मे डॉक्टरो की संख्या पूरी होनी चाहिए ताकि वहां पर गरीब आदमी और हमारी बिरादरी के लोग अपना इलाज करवा सके। स्पीकर साहब, मेरे गाव में पशुओ का एक अस्पताल है लेकिन कई साल हो गये हैं वहां पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर कोई परमानैट डॉक्टर

लगाया जाए। स्पीकर सर, सरकारी नौकरियों की भर्ती मे जो बैकलॉग है उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति आयोग के अनुसार दिनांक 30– 11 –2006 को 21648 पदो का बैकलॉग था। यह खबर दैनिक भास्कर अखबार मे छपी थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि हम अनुसूचित जाति के भाइयो की भलाई के काम करते है लेकिन दिनांक 30– 11 – 2006 को 21648 पद खाली पडे हुये थे जो कि अनुसूचित जाति और बैकवर्ड जातियो के लोगो से भरे जाने थे। स्पीकर सर, गैस्ट टीचर्ज की बात लीजिए। सरकार ने ऐसी पॉलिसी क्यो बनाई जिसमे हमारे गरीब भाइयो को रिजर्वेशन नही मिली। अगर उनको रिजर्वेशन मिलती तो तीन साल पहले उनको फायदा होता। जो गैस्ट टीचर्ज लगे थे अगर वह पॉलिसी ठीक होती तो कम से कम चार–पांच हजार हमारे अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के बच्चो को नौकरी करने का मौका मिलता और इस मंहगाई में उनको अपने घर के खर्च चलाने की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। चार हजार हमारे बच्चो को नौकरियों पर लगाया जाना चाहिए था। स्पीकर सर, इसी प्रकार से पब्लिक हैल्थ मे जो भर्तियां हुई वहां पर भी नौकरियो में रिजर्वेशन का जिक्र नहीं किया गया। स्पीकर सर, एक तरफ तो कांग्रेस की सरकार यह कह कर सस्ता में आई थी कि काग्रेस का हाथ गरीब के साथ लेकिन अगर सरकार की यही सोच होती तो हमारे 4– 5 हजार गरीब लोगो को बेरोजगार न रख कर उनको नौकरियो में लगाया जाता। (विघ्न) स्पीकर सर, गोहाना के आस–पास कई बी.एड कॉलेज

खोले गए है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहा पर बडे–बडे डोनेशन्ज लिये गये हैं, वहां पर हमारे नौजवान बच्चो को एडमिशन में बड़ी दिक्कत आई। अध्यक्ष महोदय, सरकार की पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि हमारे लोगों को उन कालेजो मे एडमिशन और रिजर्वेशन मिले। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं हमारे लोगो के पलायन के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। यहां पर यह बात बार बार कहते हैं कि पिछली सरकार ने यह कर दिया पिछली सरकार ने वह कर दिया, यदि इसी प्रकार से चलना है तो फिर पिछली सरकार को बुरा क्यो कहते हैं। पेटवाड़ गांव मे अनुसूचित जाति के लोगों के मकान गिराये गये। हिसार मे सुल्लान पुर गांव मे पलायन हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2006 में करनाल जिले मे बीबीपुर गाव के कम से कम 50 गरीब परिवार कर्ण पार्क मे आ कर डेरा डाले रहे और दस दिन तक वहां पडे रहे। उनके धर्म परिवर्तन की बात अखबारो के पहले पेज पर आई थी कि वहा पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। मै वहां पर गया था। इस खबर के बाद ही वहां पर शासन और सरकार सचेत हुए और उन लोगो को समझा बुझा कर वापिस उनके गाव भेजा गया। स्पीकर सर, इस प्रकार की बात नही होनी चाहिए।

12.00 बजे

श्री अध्यक्षः चिडाना जी आप बैठ जाएं। आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं। (विघन) आपकी पार्टी अब तक बोलते

हुए 1 घंटा 43 मिनट का समय ले चुकी है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री रामफल चिड़ानाः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने हल्के की और बाते कहनी हैं। आप मुझे 10 मिनट और बोलने दे। (विघन)

अति विशिष्ट व्यक्ति का अभिनन्दन

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Shri Mohan Lal, Minister of Transport, Government of Punjab is sitting in the VIP Gallery. I welcome him.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः चलो ठीक है आप एक दो मिनट मे कन्क्रल्यूड करे।

श्री रामफल चिडानाः अध्यक्ष महोदय, आज महंगाई बहुत जोरो से बद रही है। अध्यक्ष महोदय, यह जो एस. ई.जैड. स्कीम है यह बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें जो गरीबी की जमीने एक्वायर की गई हैं, यह ठीक है उनको 30 या 33 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है लेकिन उन गरीब लोगों को आज कोई काम नहीं मिला है और आज वे बेरोजगार घूम रहे है। उनके पास आज कोई काम नहीं है। इसी तरह से आज हरियाणा मे बिजली की बहुत बडी दिक्कत है। इसको भी सरकार को दूर करना चाहिए। इसके साथ ही यहा पर कानून व्यवस्था की बात

करते हैं कि आज हरियाणा मे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, बत्तरा जी ने खुद सदन में यह कहा था कि रोहतक जिले मे हर रोज डकैतियां, हत्याए ओर अपहरण हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक? खबर अखबार मे छपी थी कि कृपा राम पूनिया जी को धमकी मिली है। अब ये यहां पर कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मै सदन मे बेरोजगारी की बात करना चाहूंगा। हमने सुना था कि हरियाणा मे 10,000 टीचर्ज लगाए जाएंगे और हमे उम्मीद थी कि हमारे बच्चे भी उनमे लगाए जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, प्रापर्टी डीलर्ज की बात करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले अखबारो मे नवीन जिन्दल (एम. पी.) के बारे में खबर छपी थी। अब इतने बडे–बड़े लोग ऐसी बाते करने लग गए हैं। इसी तरह से मैं खिलाडियो के बारे मे भी दो बाते कहना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी पदक जीत कर आते हैं उन सभी का सम्मान होना चाहिए। जो खिलाडी सरकार के चहेते होते है उनका अच्छी तरह से सम्मान किया जाता है और जो चहेते नहीं हैं उनका सम्मान अच्छी तरह से नहीं किया जाता है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, अखबारो में एक खबर छपी थी कि कुरक्षेत्र मे एक मंत्री को अपमानित किया गया था तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी गोहाना मे गए थे और उन्होने वहां पर सीवरेज सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। स्पीकर सर, नवम्बर के पहले हफ्ते मे वहां पर सीवरेज की पाईप लाईन बिछाने का काम

शुरू हो गया था लेकिन आज तक 100 मीटर तक भी पाईप लाईन बिछ नहीं पाई है। इसका कारण यह है कि इस सरकार ने अपने एक चहेते को वहा पर ठेका दिया हुआ है और उसकी मंशा है कि इस सरकार के रहने तक वह काम करता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जींद और गोहाना मे से भारी भारी व्हीकल्स गुजरते हैं और इस काम की वजह से वहां पर सडको की बहुत बुरी हालत हो गई है। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, गोहाना मे 8 नम्बर ड्रेन के विकास मे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस दिक्कत को दूर करे। अध्यक्ष महोदय, हमारे गोहाना मे काफी जमीन है और मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर एक बडा और बढिया सा पार्क बना दे ताकि लोग वहा पर घूम–फिर सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। उनको भी ठीक किया जाए।

श्री अध्यक्षः चिडाना जी, आपके हल्के मे जो सड़क का 500 गज का टुकडा रह गया था उसको पूरा कर देगे। अब आप अपनी सीट पर बैठे। सदन मे और भी सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री रामफल चिड़ानाः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक? दो बातें और कहनी हैं। अध्यक्ष महोदय, रिढाना गांव मे एक पुल है, उसकी बहुत ही खस्ता हालत है। वह कई सालों से टूटा हुआ है। इस बारे में मैं कई बार अधिकारियों को मिल भी चुका हूं और लिखकर भी दे चुका हूं। उसकी वजह से वहां पर कई घटनाएं हो गई है और मौते भी हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, पशु भी उस पुल

पर से गिर जाते है। उसको बनाने के बारे मे यह सरकार विचार करे। इसी तरह से धनाना गांव है, वहां पर ऐसी स्थिति है कि अगर थोड़ी सी वर्षा हो जाए तो वहां पर पानी इक्ट्ठा हो जाता है। नांदल गांव मुख्यमंत्री जी के हल्के मे आना है। अगर वहा से ड्रेन की खुदाई की जाए तो यह प्रोब्लम हल हो जाएगी। गोहाना में नए बस अड्डे की बात चल रही है। (विघ्न) **श्री अध्यक्षः** चिडाना जी, आप कन्कलुड करे।

श्री राम फल चिड़ानाः स्पीकर साहब, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि गोहाना में गुरूकुल विश्वविद्यालय खुला है। इसको बनवाने मे हमारे इलाके के लोगो का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब अरबों– खरबो रुपयों की बिल्डिग वहा बनाकर दी गयी है तो वहां के लोगो को उस विश्वविद्यालय में एडमिशन मे रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। स्पीकर सर, आज गरीब की बहुत ज्यादा दयनीय हालत हो गयी है। राष्ट्र के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए आजकल जेसी. बी. मशीनो से काम हो रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इनके कारण गरीब आदमियों के लिए अपनी रोजी रोटी कमाकर पेट भरना मुश्किल हो गया है इसलिए उनके लिए भी सरकार की तरफ से स्कीम्स बनायी जानी चाहिए ताकि वे लोग मी अपनी रोजी रोटी ठीक तरह से कमा सके। स्पीकर सर, आपने मुझे टाईम दिया इसके लिए धन्यवाद।

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, चिडाना साहब ने जो एक बात कही है उसको मैं क्लैरीफाई करना चाहता हूं। इसेने कहा कि गोहाना के पास जो बी. पड कालेज खुला है उसमे एससीज. के बच्चो को एडमिशन नहीं दी गयी है इनकी यह बात सरासर उचित नहीं है क्योंकि एडमिशन करने का अधिकार बी.एड कालेज के एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। सरकार की परमिशन से बाकायदा काउसलिग करके रूल्स के मुताबिक एडमिशन दी गयी है फिर भी यदि ऐसा कोई केस इनके सामने आया है तो ये हमें बता दें, उस पर कार्यवाही की जाएगी।

Major Nirpender Singh Sangwan (Dadri): Sir, thank you very much for granting me time to speak on the Governor's Address.

On the outset, I congratulate the Hon'ble Chief Minister and his ministerial colleagues for having made huge advances towards progress in the last three years. I will be failing in my duty, if I don't congratulate the Finance Minister and his staff for making the money available to all departments for making this progress. I thank Mrs. Sonia Gandhi and the Prime Minister for waiving off of Rs. 60,000 crores of loans for poor farmers.

Agriculture is the backbone of Haryana and this goes without saying that food-grain production is another all-time high. But the impact of this will be filled up only when every grain of the farmer is purchased by the Government or other agencies. And for this we have to make effort that the farmer should get right price for his produce. Besides

purchase, the food-grains should be having adequate space for storage within the State or outside otherwise the whole impact will be lost because grains get spoiled and it become unedible and we have to put it into the wastage storage. I congratulate the Haryana Marketing Board for setting up the terminal markets which are in the proposal and **I** wish that more such markets are to be set up in the State to give benefit to all levels of farmers.

Equitable distribution of water in Haryana is the key point of our Government. Steps are being taken towards achieving the target and we are looking forward to the completion of Hansi-Butana Link Canal. Besides drinking water being supplied by the irrigation channels, I would also request that special attention is to be paid more so in southern Haryana where the water for the animals is in scarcity. Village ponds should be filled up so that in summer there is no paucity of drinking water for animals. Speaker

Sir, for this we need more minors & channels and reduction in theft cases of water क्योंकि जमीदार जो है वह चोर नहीं है परन्तु उसकी छाती के०पर से पानी गुजर रहा हो और उसके बावजूद भी वह अपने खेत को पानी न दे सके, इस कारण से उसको मजबूरन चोरी करनी पड़ती है। यह चोरी तभी खत्म हो सकती है जब हम ज्यादा माइनर और ज्यादा चौनल बनाएं ताकि उनके सहारे खेतो मे पानी पहुंच सके। पॉवर की हमारे पास बहुत कमी है परन्तु यह कमी जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा और हम सबको भी पता है कि हमे विरासत में मिली है। पता नहीं

क्या मजबूरी रही कि पूर्ववर्ती सरकारो ने बिजली के उत्पादन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए? जिसकी वजह से आज खपत बढ़ती जा रही है। अब उत्पादन का जरिया हमारी सरकार ने बनाया है। अगले साल और उससे अगले साल सारे कारखाने उत्पादन शुरू करेगे, तभी इसका फायदा लोगो तक पहुच सकेगा। इसमे मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि एक सब– स्टेशन मेरे खुद के हल्के में छपार मे जनवरी मे चालू होना चाहिए था, वह अभी तक चालू नहीं हुआ है। इस पर ध्यान दिया जाए और इसे जल्द से जल्द चालू किया जाये। Speaker Sir, for buildings and roads, I also congratulate Capt. Ajay Singh Yadav and his full team of officers who have done commendable job in renovating the Haryana Vidhan Sabha. Lot of roads and bridges have been made in my Dadri constituency. Some roads are under progress. Speaker Sir, as a whole, lot of work is being done. I would like to put a point that because of usage, lot of roads have broken but no attention is being paid for repairing them because it is thought that when a new road is being made, there is no need to repair it. Speaker Sir, Haryana Government has brought about Special Economic Zone, which is a very commendable work. Now, we look forward to our children getting employment in these Special Economic Zones. I would request the Government that Dadri itself has no industry. There was only one cement factory which was closed down 15 years back. Speaker Sir, I would also request the Government that for the residents and younger generation there is no avenue of employment so, HSIDC may set up an industrial sector at Dadri because it has all the amenities like there is

rail head, this town has also excellent road connections and there is reasonables rates of land. Moreover, it is only 5 K.M. from Jhadli where power plant is coming up. Therefore, I again request the Government to look into the matter. Speaker Sir, HUDA is doing commendable job by putting up new sectors to stay residents as well as industries. Speaker Sir, I think there is need to do more for servicemen, Ex-servicemen and serving soldiers because this one section of the society which is in the service of nation and they are away from their families and motherland. They are looking at the frontiers but when they come back there is no availability of plots for them. Sir, at some places like Dadri, there is no defence colony and they have to buy land at an exorbitant price somewhere else. So, I would request the Government that more defence colonies in Haryana may be made by the HUDA.

Mr. Speaker: Major Sahib, please conclude your speech.

Maj. Nirpender Singh Sangwan: In education, a lot has been done. I congratulate the Education Minister for looking into the education at a priority but I would request that the repair of buildings should be made and the vacancies of the Education Department should be filled up on a priority. The curriculum should be such that it is in consonance with the international standard so that our children get employment internationally also. Today becuase of this, in Gurgaon, there aa about 3 to 4 lacs people who come outside from Delhi and around and our own children are only about 20 to 30 thousand who are employed. So, the table should be reversed and 3 to **4** lacs of our own children should be

employed and, if needs, we take about 20-30 thousand persons from outside. Most of the points have been put across on Sports, Health, Building and Repair, Animal Husbandry but due to paucity of time, I conclude my speech. Thank you very much.

श्री रमेश गुप्ता (थानेसर): धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे गर्वनर साहब के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। मै इस अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आप द्वारा विधान सभा का जो नवीनीकरण कराया गया है इसके लिये आपको बहुत–बहुत मुबारिकबाद देना चाहता हू। काफी समय पहले से ही विधान सभा का नवीनीकरण होना जरूरी हो गया था। आपने अच्छा स्टैप लिया ताकि सभी सदस्यो को बोलने और बैठने की सुविधा प्रदान हुई है। गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण पढा है उससे यह पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हरियाणा का चहूमुखी विकास करने की सोच है और हरियाणा प्रदेश को नम्बर 1 राज्य बनाने की सोच है वह इस अभिभाषण मे साफ झलकती है। जब यह सरकार आई उससे पहले किसानो की बुरी हालत थी। मुख्यमंत्री जी का पहले से ही प्रयास था कि किसानो की हालत मे सुधार हो और इसके लिए ये निरन्तर प्रयास भी कर रहे थे। पहले उन्होंने किसानो के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए उसके बाद 800 करोड़ रुपये के सहकारिता विभाग के व्याज माफ करने का काम किया गया। इसके बाद गेहूं और जीरी के रेट भी बढाये क्योकि तीन वर्ष से सैन्टर मे भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है ओर हरियाणा मे

भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इसलिए गेहूं के रेट में 300–400 रुपये की वृद्धि की है और उसके साथ 100 रुपये का बोनस भी मिल सकता हे। इसी प्रकार से जीरी का भाव भी 1050 रुपये प्रति क्विटल किया है। मै आदती होने के नाते जानता हूं कि जो किसान पहले कर्ज के नीचे दबे हुए थे वे अब सुख की सांसे ले रहे हैं। इसी प्रकार से गन्नौर में 500 एकड क्षेत्र पर एक विश्व स्तर की अग्रस्थ मण्डी फल एवं सब्जियो की मण्डी बनाने जा रहे है। यह एक अच्छा कदम है। इससे जो फल और सब्जियां बेचने वाले थे जिसके लिए आजादपुर मण्डी में दिक्कत होती थी उनको काफी राहत मिलेगी। सरकार ने यह बहुत ही सराहनीय फैसला लिया है। शहरो की तर्ज पर गांवों मे भी सुधार किये जा रहे हैं। कई मॉडल गाव भी बनाये जा रहे है। मेरे हल्के मे ज्योतिसर जोकि एक ऐतिहासिक टाऊन है जहा भगवान कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था को मॉडल गांव बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने चार करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। सड़के भी बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ 1532 गांवो की फिरनी बनाने के लिए दस लाख रुपये दिए हैं उनको बनाने की शुरुआत हो चुकी है। उसमे टैण्डर का काम अलॉट हो चुका है। उसके लिए पूरा पैसा दिया जाए ताकि वह काम पूरा हो सके। वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा रिवैन्यू काफी बढा है यह हमारी सरकार का सराहनीय कदम है। जो रिवैन्यू पहले 11149 करोड रुपये था वह अब 19630 करोड़ रुपये हो गया है। रिवैन्यू रिसीटस मे योजना आयोग ने राज्य का वर्ष 2008–09 का प्लान बजट 6650 करोड

रुपये स्वीकृत किया है जो पहले साल से 25. 5 परसैंट अधिक है इससे पता लगता है कि हमारे हरियाणा की इकोनमी हालत ठीक होती जा रही है। समान जल बटवारे का कार्य जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय की सोच है, उसके तहत यह हांसी बुटाना लिक नहर का निर्माण और कुरुक्षेत्र मे दादुपुर नलवी का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है इससे कुरुक्षेत्र जिले और दूसरे जिलो को काफी लाभ होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे भी हल्के मे राक्षी नदी की मंजूरी दी गई थी, उसकी खुदाई हो चुकी है और कुछ लैड एकवायर होनी है इसलिए मैं इरीगेशन मिनिस्टर से रिक्वैस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी लैंड एकवायर हो ताकि यह काम जल्दी पूरा हो सके। अध्यक्ष महोदय, जहा तक पीने के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए इन्दिरा गांधी पेयजल स्कीम है और जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि यह स्कीम बडी तेजी से चल रही है, हमारे हल्के के कई गांव इस स्कीम के तहत कवर हो गए है लेकिन शहरो को इस स्कीम के तहत कवर करना अभी बाकी है। हमे उम्मीद है कि आने वाले फाइनैंशियल इयर मे शहरो को इस स्कीम के तहत कवर कर लिया जाएगा इससे सीवरेज को भी फायदा पहुंचेगा। कुरुक्षेत्र में कई टयूब्ल्ज जिनको पंचायत चलाने मे असमर्थ थी उनको पब्लिक हैल्थ ने अंडर टेक कर लिया था। स्वच्छ जलधारा से वहां के लोगो को लाभ मिला है इसके लिए मैं मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। 11 हजार सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, यह बहुत बडी नियुक्तियां हुई हैं इससे बाल्मिकी समाज को बहुत फायदा हुआ है इसके लिए मैं मंत्री महोदय का

धन्यवाद करना चाहूंगा। चूल्हा टैक्स और हाउस टैक्स माफ होने से बहुत से लोगो को लाभ मिला है। हरियाणा के 40 साल के इतिहास मे बिजली उत्पादन बहुत कम था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 5000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बनाने का फैसला लिया है जिस पर काम जारी है इससे हरियाणा में बिजली की कमी दूर होगी। ट्रांसमिशन के काम के लिए भी बजट रखा गया है कि ट्रांसमिशन ठीक होना चाहिए और मेरे हल्के मे जो सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं वे लगभग कम्पलीट हो चुके है और हमने मुख्यमंत्री महोदय जी से उनका उद्घाटन करवाना है। मेरे साथियो ने यहां आवाज उठाई है कि कालोनीज मे जो लाल डोरे के बाहर है वहां बिजली की तारे टूटी हुई हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां भी कई जगहो पर पिपली मे भी और कई जगहों पर भी तारें टूटी हुई है जिसकी वजह से हादसे होते रहे है इसलिए मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा प्रावधान जरूर किया जाए कि ये तारे बदलवाने का काम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सड़कों के सुधार के लिए 3 हजार करोड रुपये रखे गए हैं यह बहुत अच्छी बात है। सभी जगह हाइवे बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहां पेहवा से हरिद्वार की सड़क को भी 4 लेनिंग करने की घोषणा की हुई है इसलिए मैं मंत्री जी से भी निवेदन करूगा कि इस सड़क को अंडर टेक किया जाए और लाडवा से निकालते हुए इस सड़क को 4 लेनिंग किया जाए क्योंकि हमे रेलवे लाइन भी नहीं मिल रही है, हमारी यह डिमांड काफी समय से रही है कि पेहवा से हरिद्वार रेलवे लाइन बने

इसलिए मैं कहना चाहूंगा जब तक पेहवा से हरिद्वार तक हमें रेलवे लाइन नहीं मिलती तब तक कम से कम इस सड़क को 4 लेनिग तो जरूर किया जाए। उमरी से ब्रहमसरोवर को सड़क जाती है, वहा उस सडक पर एक फाटक पड़ता है और उस सड़क पर काफी रश रहता है वहां एक रेलवे ओवर ब्रिज की जरूरत है इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में एस.ई.जैड बनाए जा रहा है इससे हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, 2 लाख करोड़ का बाहर से भी निवेश आ रहा है इससे हमारा हरियाणा प्रगति की ओर जाएगा। इसके साथ–साथ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि कुरुक्षेत्र को भी ऐसी टाऊनशिप में लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के साथ–साथ वर्कर्ज की तरफ भी विशेष ध्यान दे रही है जिसके कारण वर्कर्ज हादसे 0.49 प्रतिशत तक रह गये हैं जोकि बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, टुरिज्म की तरफ भी हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर बैल्ट को टुरिज्म के लिए बढ़ावा दिया गया है। कुरुक्षेत्र वर्ल्ड फेमस नगरी है इस लिए यहा पर टुरिज्म की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टुरिस्ट्स यहां आये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शिक्षा की तरफ भी हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक किताबे फ्री दी जायेगी और मॉडर्न टैक्नोलोजी ऐजूसैट प्रणाली के जरिये बच्चो को शिक्षा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त एससी. वर्ग

के लड़के– लड़कियों को वजीफे देने की भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ताकि बच्चे बीच मे ही अपनी पढाई न छोड़े। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हैल्थ की तरफ भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। हैल्थ के अंदर मॉडर्न टैक्नोलोजी अपनाई जा रही है जिनके कारण मोरटेलिटी रेट मे कमी आई है और जच्चा–बच्चा की तरफ भी सरकार की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ–साथ गरीब परिवारो के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी सरकार ने शुरू की है। इसी तरह से हैंडीकैप्ड लोगों को भी पैंशन सुविधा दी जा रही है। इसी तरह से हमारी सरकार ने राष्ट्रीय ई–शासन योजना शुरू की है जिसके तहत खजाना, भूमि रिकार्ड, सम्पत्ति पंजीकरण, गृह कर, वैट पंजीकृत डीलर्ज, प्रबंधकीय सूधना–तंत्र और वृद्धावस्था पेशन को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रावधान किया है। ऐसा होने पर प्रदेश के लोगो को अच्छा ई– शासन मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अंत मे मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हू जो हमारी सरकार का विजन है। इतने अच्छे अभिभाषण के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तथा वित्तमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के जरिये हरियाणा प्रदेश सुनहरे भविष्य की तरफ अग्रसर होगा।

नियम 22(2) के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move Motion under Rule 22(2):-

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the discussion on Governor's Address be postponed in favour of Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2007-2008.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the discussion on Governor's Address be postponed in favour of Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2007-08.

Mr. Speaker: Question is—

That the discussion on Governor's Address be postponed in favour of Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2007-08.

The motion was carried.

वर्ष 2007–08 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2007-08.

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिह): अध्यक्ष महोदय, मै वर्ष 2007–08 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, Shri Anand Singh Dangi, Chairperson, Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2007-08.

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Anand Singh Dangi): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2007-08).

वर्ष 2007–08 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon' ble Members, now, discussion and voting on Supplementary Estimates (Second Instalment) 2007-08 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper (No. 1, 3 to 16, 20 to 21 and 23 to 25) will be deemed to have been read and moved together and a general discussion on the supplementary demands is permitted. The Members are, however, requested to indicate the demand No. on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 31,14,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 25,54,90,000/. for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 3-Home.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 60,54,37,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 4-Revenue.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 6,46,99,000/. for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 5-Excise & Taxation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 88,80,82,000/. for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 6-Finance.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,96,32,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 107,67,98,000/. for capital expenditure be granted to the

Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 8-Buildings Roads.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 64,63,21,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 9-Education.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 76,56,70,000/. for revenue expenditure and Rs. 7,64,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 10-Medical & Public Health.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 112,75,86,000/. for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 11 - Urban Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,24,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 12 - Labour & Employment.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 41,27,72,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of

Demand No. 13 - Social Welfare and Rehabilitation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,80,27,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 14 - Food & Supplies

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 410,15,11,000/- for revenue expenditure and Rs. 40,90,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 15- Irrigation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 5,94,61,000/- for revenue expenditure and Rs. 65,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 16- Industries.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,73,15,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 20 - Forests.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 184,36,95,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 21 Community Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 39,68,00,000/- capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 23 - Transport.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 83,000/- for revenue expenditure and Rs. 6,20,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 24 - Tourism.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,02,85,000/- capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 25 - Loans & Advances by State Government.

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker: Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is -

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 31,14,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 1- Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is -

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 25,54,90,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 3- Home.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 60,40,37,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 4 - Revenue.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 6,46,99,000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 5 - Excise & Taxation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 88,80,82,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 6 - Finance.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,96,32,000/. for revenue expenditure and Rs. 3,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 7 - Other Administrative Services.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 107,67,98,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray char& s that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 8 - Buildings & Roads.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 64,63,21,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 9 - Education.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 76,56,70,000/- for revenue expenditure and Rs. 7,64,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 10 - Medical & Public Health.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 112,75,86,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 11- Urban Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,24,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 12 - Labour & Employment.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 41,27,72,000/- for revenue expenditure be granted to the

Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 13 - Social Welfare and Rehabilitation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,80,27,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 14 - Food & Supplies.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,10,15,11,000/- for revenue expenditure and Rs. 40,90,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 15 - Irrigation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 5,94,61,000/- for revenue expenditure and Rs. 65,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 16 - Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is -

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,73,15,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 20 - Forests.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 184,36,95,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 21 - Community Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is —

That a Supplementary sum not exceeding **Rs**. 39,68,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 23 - Transport.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 83,000/- for revenue expenditure and Rs. 6,20,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 24 - Tourism.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,02,85,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2008 in respect of Demand No. 25 - Loans & Advances by State Government.

The motion was carried

अति विशिष्ट व्यक्ति का अभिनन्दन

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय श्री चिरजी लाल शर्मा जी जो कि हरियाणा प्रान्त से काग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है और पूर्व सांसद है इस समय स्पीकर गैलरी मे मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं।

Mr. Speaker: I also welcome Shri Chiranji Lal Sharma.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion on Governor's Address will resume.

डा० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी): स्पीकर सर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से स्पष्ट हे कि सरकार की नीति और नीयत दोनों ही विकास की है और यह भी सच है कि विकास के फायदे तभी होंगे जब हम आर्थिक लक्ष्यो के साथ–साथ सामाजिक लक्ष्यो को भी प्राप्त करेगे और सामाजिक लक्ष्य हमे तभी प्राप्त होगे जब समाज के कमजोर वर्गो को हम बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाये दे सकेगे। स्पीकर सर, इस सब के लिए मैने एक छोटा सा प्रयास अपनी कास्टीच्युएसी मे किया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी जब 27 नवम्बर, 2007 को मेरी कांस्टीक्ट्रएंसी में आई थी, उस समय भी मैंने उनके सामने अपना एक कोर प्वायंट प्रोग्राम रखा था जिसको मैं डॉ० भारद्वाज कोर प्वायंट प्रोग्राम कहता हूँ और जब मैं कभी लाईफ लाईन मे जाता हू ओर

वहा श्री राहुल गांधी जी से मिलता हूं तो मैं उनसे भी यह बात कहता हूं और इस फोर प्वायंट प्रोग्राम में जो फोर प्वायंट्स हैं उनमें सबसे पहले जल का प्वायंट है। हर घर मे स्वच्छ जल मिले, दूसरा हर घर में सैनीटरी लैट्रिन हो, तीसरा हर बच्चे को शिक्षा मिले और चौथा भ्रष्टाचार की समाप्ति हो। स्पीकर सर, मैं यह समझता हू कि अगर हम इस फोर प्वायंट प्रोग्राम पर काम करें तो बाकी की सारी तरक्की स्पोटेनिशियली साथ–साथ होती रहेगी और हम हरियाणा को हिन्दुस्तान मे रहने के लिए एक अच्छी जगह बना सकेगे। सर, इस बात मे कोई शक नहीं है कि हमारी जो राजस्व प्राप्तिया हैं, रेवेन्यू रिसीट्स हैं वे काफी बढ़ी हैं और आगे भी बहुत अच्छी आशा की किरण दिखाई देती है। वर्ष 2005– 2006 मे यह प्राप्तिया 13,853 थी और वर्ष 2007–2008 मे 19,630 करोड़ रुपये हो गई है और फरवरी–मार्च 2007 मे ओले पडने से किसानो की फसलो के बर्बाद हो जाने के बाद हमने किसानो को 2003 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था। सर, फसलों का नुकसान तो इस बार भी बहुत हुआ है और मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर उस नुकसान की भरपाई की जाये तो बहुत अच्छी बात होगी क्योकि हमारे सरकारी खजाने मे काफी पैसा उपलब्ध है और अगर उससे किसानो की मदद की जायेगी तो इससे किसानो को अच्छा फायदा हो सकेगा। जो राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएं गेहूं और दलहन की खेती को बढ़ाने के लिए और उनका निवेश बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं ये भी स्वागत योग्य हैं। इसके अतिरिक्त पशुधन को प्रोत्साहन देने के

लिए हिसार मे एक नये पशु विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, यह भी बहुत अच्छी बात है। इसके साथ मैं सरकार से यह प्रार्थना भी करूंगा कि भिवानी मे भी एक पशु विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करे क्योकि वहां पर भी एक पशु विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। इराके अतिरिक्त भिवानी मे एक 50 साल से भी ज्यादा पुराना टैक्सटाईल कालेज है जो कि शायद हिन्दुस्तान मे अपनी किस्म का यह एक अनूठा कालेज है और इसका लैवल मानचौस्टर के बराबर है और अगर भिवानी मे एक टैक्सटाईल यूनिवर्सिटी बनाई जाये तो इस यूनिवर्सिटी को बनाने मे सरकार को ज्यादा असुविधा भी नहीं होगी और उस पर ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा क्योकि वहां पर आलरेडी कालेज ऐग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बच्चो को पढने का अच्छा मौका मिलेगा। जैसा औषधीय पौधो के लिए 20 हर्बल पार्क हरियाणा सरकार द्वारा राज्य मे स्थापित किए गये हैं यह भी बहुत अच्छी बात है। मेरे हल्के मे भी एक गाव है नन्दगाव, वहा के लोगो की भी यह डिमाण्ड है कि वहां पर भी एक हर्बल पार्क स्थापित किया जाये। स्पीकर कर, इसके लिए भी मै आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर भी लोगों की डिमाण्ड के अनुसार एक हर्बल पार्क खोला जाये। दक्षिण हरियाणा में जो पानी की कमी है उसकी तरफ सबका ध्यान है। हाँसी–बुटाना नहर का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है और जब यह पक्चर हो जायेगी तो हमारे इलाके को इसका बहुत फायदा होगा। मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि मेरे हल्के

मे एक गाँव रूपगद है उसमे आर०जी० 7000 पर एक पम्प स्थापित होना है। मंत्री जी दो बार वहाँ का दौरा भी कर चुके है और उसके लिए अपनी स्वीकृति भी दे चुके हैं लेकिन उस पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उस पर शीघ्रातिशीघ्र काम शुरू करवाया जाये। पालूवास और सांगा माईनर की जो रिपेयर करवाई गई है उसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। लोग इस बात से बहुत खुश है जल आपूर्ति की जहाँ तक बात है 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने का लक्ष्य हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है। इस विषय मे हमे अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे कुछ वाटर वर्क्स जिनमें राजगढ है और एक डिस्पोजल जीतू वाला मोड की है जिस पर 2004 से काम जारी है लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ है, उसको शीघ्र पूरा करवाया जाये। इसी तरह से कितलाना वाटर वर्क्स के लिए 90 लाख रूपये की राशि देकर काम शुरू किया था लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ है। गौरीपुर गाँव में पानी की बहुत किल्लत है उसमें भी इंडिपैंडैट वाटर वकर्र बनवाया जाये। भिवानी शहर के लिए मैं पहले ही आपसे रिक्यैस्ट कर चुका हूँ कि भिवानी मे री वाटर दबी बहुत कमी है। आप बिजली मंत्री भी हैं और जल आपूर्ति मंत्री भी हैं तो मैं चाहूगा कि जब पानी सप्लाई का समय होता है उस समय अगर बिजली मिल जाये तो लोगों को पर्याप्त मात्रा मे पानी मिल पायेगा। प्रहलादपुर मे एक वाटर वर्क्स का शिलान्यास 2 मार्च, 2006 में हुआ था लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उसको शीघ्र शुरू करवाये। बिजली का

जहां तक सवाल है, मैं विपक्ष के साथियो का ध्यान भी इस तरफ खींचना चाहूंगा जो कि बिजली पर बहुत सी बाते कहते रहते हे। 739 लाख यूनिट प्रतिदिन की औसत से यह सरकार लोगो को बिजली उपलव्य करवा रही है। मेरे पास जो डाटा मौजूद है वह ग्रामीण सैक्टर, शहरी सैक्टर और औद्योगिक सैक्टर मिलाकर यह डाटा है। इससे प्रतीत होता है कि 2004 मे जो पिछली सरकार बिजली दे रही थी यह सरकार उससे कहीं ज्यादा बिजली आज दे रही हे। जो रिलेटिव बिजली की कमी है वह जरूरत बढने की वजह से है उस वजह से नहीं कि हमने बिजली कम कर दी। ओम प्रकाश चौटाला जी का यह बयान कि मुख्य मंत्री बिजली दिल्ली को बेच रहे हैं, बिलकुल गलत है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया। हमारे मुख्य मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिह हुड्डा' के हाथो में हरियाणा के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। अध्यक्ष महोदय, इसका एक प्रमाण मैंने और श्री मांगे राम गुप्ता जी ने अपनी आखो से देखा था जब हम एयरपोर्ट पर थे। जब एयरपोर्ट का नाम चेंज करने की बात आई तो माननीय मुख्य मत्री जी अज गये और चट्टान की तरह अडे रहे। सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिह बादल और नागरिक उडुयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी स्टेज पर ही मौजूद थे। उस समय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस बात पर अड़ गये थे कि जब तक हमारा हिस्सा इसमे तय नहीं हो जायेगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। (इस समय मेजे थपथपाई गई)।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नही है, जब तक केन्द्रीय मंत्री ने यह तय नहीं कर दिया कि हरियाणा का इतना हिस्सा होगा तब तक मुख्य मंत्री जी उसमे शामिल नहीं हुए।

डा० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, जहा तक हरियाणा के हितो का सवाल है, मुख्य मंत्री जी कभी पीछे हटने वाले नहीं है उसके बाद जब एम.ओ.यू साईन हुआ, उसमे हमने देखा की 51 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र का और पंजाब का और हरियाणा का सादे चौबीस–सादे चौबीस प्रतिशत हिस्सा था। अब एयरपोर्ट पर हरियाणा का भी उतना ही हक है जितना कि हमारे बजे भाई पंजाब का है। मैं बिजली के बारे मे थोड़ी सी बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमें अक्षय०र्जा और सौर०र्जा के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सौर०र्जा के बारे में एक बात तो यह है कि आफ्टर सेल उनकी सर्विस ठीक नहीं है। एक बार बल्व खराब हो जाते हैं तो खराब ही पड़े रहते है उनको बदला नही जाता। मेरा बिजली मंत्री जी से अनुरोध है कि आफ्टर सेल सौर०र्जा वाली लाईटों को शीघ्र चालू करवाया जाये और उनकी सर्विस ठीक रखी जाए। बिजली की कमी पूरी तरह से तो तभी दूर हो सकती है जब हम न्यूक्लियर पॉवर बनाना शुरू कर देगे। मैं कनाडा मे गया था वहां पर बिजली एक मिनट के लिये भी नहीं जाती क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर पॉवर है। जहां तक भवन एवं सडकों का सवाल हे, तीन हजार करोड़ रुपये की योजनाए हैं जो

कि बहुत ही अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, भिवानी मे दो आर.ओ. बी. पास हुए हैं मैं अपने पी.डब्लयू.डी. मिनिस्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि 18 नवम्बर को एक पुल का शिलान्यास हुआ था लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू करवाने की मेहरबानी करें।

श्री अध्यक्षः डॉ० साहब, अब आप कन्क्रलुड करे (विघ्न) आप दो मिनट मे कन्कलुड करें।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः स्पीकर सर, मैं पांच मिन्ट में कन्कलुड कर लूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस.ई.जैड. का सवाल है, भिवानी मे भी एक एस. ई.जैड. होना चाहिये। जैसे जगाधरी, फरीदाबाद, रोहतक और खरखौदा मे मॉडल टाउनशिप बने हँ उसी तरह का मॉडल टाउनशिप भिवानी में भी बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे भिवानी में काठमण्डी टाउनशिप 1975 मे बना था और उसके बाद उसकी मैंटीनैस बिलकुल नहीं हुई है। वहां पर सीवरेज सारा बन्द पड़ा हुआ है और उसकी चारदीवारी भी नहीं है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इसकी मेटीनैस करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, लौहारू रोड से कनैक्ट करने के लिए एक लाजपत मार्किट है उसमे अगर पानी की सप्लाई और सीवरेज डाल दिया जाए और सडक बना दी जाए तो काठमण्डी की कनैक्टिविटी लौहारू रोड से हो जाएगी और काठमण्डी का थोड़ा उद्धार भी हो

जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से भिवानी मे टैक्सटाईल हब बन सकती हे। क्योकि वहां पर निवार की और निवार दाने की फैक्टरीज सबसे ज्यादा हैं। इसी प्रकार से टूरिज्म मिनिस्टर भी हमारे भिवानी की हैं मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार होटल मैनेजमैंट ईस्टीच्यूट जगह–जगह खोले जा रहे हैं भिवानी मे भी एक होटल मैनेजमैंट सस्थान अगर खोला जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। स्पीकर सर, शहरी विकास मे भी काफी काम हुआ है लेकिन सरकार से मेरी प्रार्थना है कि हमारे भिवानी में एक बैंक कॉलोनी है और यह कॉलोनी 15 साल से बनी हुई है। अभी तक इस बैंक कॉलोनी का रैगुलर नहीं किया गया है जिसके कारण वहां पर रहने वाले लोगों के सिर पर हर समय तलवार लटकती रहती है कि पता नहीं कब उनके मकान गिरा दिए जाए। इस कॉलोनी को भी अगर रैगुलर करें तो ठीक रहेगा। हाउस टैक्स, चूल्हा टैक्स मुआफ कर दिए गए है और 11 हजार सफाई कर्मचारियो की नियुक्ति हुई है मैं समझता हूं कि उससे सफाई के काम मे भी काफी सुधार होगा। वर्ष 2008 को हम शिक्षा वर्ष के रूप मे मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे भी शिक्षा को काफी बूस्ट मिलेगा। मेरे हल्के में कुछ ऐसे गांव हैं जहां के स्कूलों को अपग्रेड किये जाने की जरूरत है। एक राजगढ़ गाव है वहा की बच्चियो को पढने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। यह स्कूल अपग्रेडेशन के सारे नॉर्म्स पूरे करता है। इसी तरह से हालूवास का स्कूल भी सभी नॉर्म्स पूरे करता है।

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करता हू कि इन स्कूलो को अपग्रेड करने की कृपा करें। तकनीकी शिक्षा के बारे में भी मेरा कहना है कि मेरे हल्के मे नंदगांव मे शिक्षा मन्त्री जी गये थे। वहा पर एक आईटीआई. खोले जाने की बहुत जरूरत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां पर एक आईटी. आई, जरूर खोला जाए। जहां तक हैल्थ का सवाल है, मेरा यह हमेशा से मानना है कि जब हम हैल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमे पब्लिक हैल्थ के बारे मे बात करनी चाहिए। जब तक हम लोगो का जीवनस्तर नही सुधारेगे तब तक हम हैल्थ के पैरामीटर्ज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि बी, पी.एल. मे जीवनयापन करने वाले लोगो को डिलीवरी के लिए 700 रुपये दिये जा रहे हैं और अनुसूचित जाति के लोगों को 500 रुपये डिलीवरी के लिये दिये जा रहे हैं इससे डैफिनेटली मदर मोरटैलिटी और इच्छैंट मोरटेलिटी काफी डाउन आई है। स्पीकर सर, हैल्थ के बारे में सर्वीच्च संस्था मैडिकल कॉलेज, रोहतक हे जिससे आप भी जुड़े हुए हैं। आप उस वक्त भी वहा पर आते थे जब मैं वहा पर एक स्टूडैंट था। इस मैडिकल कॉलेज मे आज कोई न्यूरो सर्जन नहीं है, आज वहा पर कोई रेटिनल सर्जन नहीं, वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होती, कोई गेस्ट्रोऐंटोलोजिस्ट नहीं है। अगर किसी की सी.वी.टी मे स्टोन फंस जाए तो हम एंडोस्कोपी के बिना निकाल नहीं सकते। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि हमने इस अस्पताल को पीजीआई. का लैवल तो दे दिया है लेकिन इस

संस्था मे काफी सुधार करने की आवश्यकता है क्योकि यह सस्था हमारी सर्वोच्च संस्था है। अध्यक्ष महोदय, पी.एन. डीटी. के बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं लेकिन एक ही बात पर जोर नहीं होना चाहिए कि अल्ट्रा साउंड हमे सील करने हैं, बन्द करने हैं क्योकि अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टूल है जिससे कि हम बीमारी का पता लगाते है। इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए क्योकि यह नॉन इन्वेसिव है और इस पर कुछ खर्च नहीं आता है। पी. एन. डीटी. जहां पर गलत मिल जाए वहां जरूर कार्यवाही करे लेकिन सिर्फ अफवाहो के आधार पर अल्ट्रासाउंड बन्द कर देना ठीक नहीं है। इसके लिए मैं सरकार को सचेत करता हू। अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग में माल न्यूट्रीशन को दूर करने के लिये पोषाहार प्रति बच्चे के लिए 2 से 3 रुपये कर दिया गया है जब कि प्रैगनैट बूमैन का अढाई रुपये से बढा कर 5 रुपये कर दिया है। सरकार ने यह बहुत ही अच्छा काम किया है। स्पीकर सर, कुश अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों मे तकनीकी ट्रेनिंग, ड्राइविंग, जेबीटी., होटल मैनेजमैंट, एयर होस्टैस की ट्रेनिंग देने की जो बात है, वह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास अनस्किलड पॉपुलेशन की कमी नहीं है उनको सिर्फ स्किलड बनाए जाने की जरूरत है। अगर हम उन्हे स्किल्ड बना दें तो हम उनकी प्रगति भी कर सकेंगे। स्पीकर सर, गोल्डमैन हॉक की एक भविष्यवाणी थी जो सिर्फ ज्योतिष के आधार पर नहीं थी बल्कि उसने डाटा कलेक्ट करके एक सांइटिफिक ऐनालिसिस किया था। उसके आधार पर यदि हम देखें तो वर्ष 2050 मे चीन के बाद

विश्व में दूसरी बडी आर्थिक शक्ति भारत तभी बन सकता है जब हम अपने अन–स्किलड पॉपुलेशन को ट्रेंड करे।

श्री अध्यक्षः डॉ० साहब, आपको दो मिनट का समय दिया गया था लेकिन उसके बाद भी आपको बोलते हुए पांच मिनट हो चुके हैं। You are snatching the right of other members, आप और जो कहना चाहते हैं वह लिख कर भिजवा दे वह आपका पढा हुआ माना जाएगा और विधान सभा के रिकार्ड पर भी रखवा देंगे अब आप बैठें (विघन)

डॉ० शिवशंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद। बैंको का तो बहुत थोड़ा ब्याज होता है मैने स्वयं बैंक मे नौकरी की है। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसानो को साहूकारों के चुंगल से छुटकारा दिलाने के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, किसानों के अलावा मजदूर, कामगार, छोटे व्यापारी और बेरोजगार युवा जैसे अनेकों ऐसे–ऐसे लोग हैं जो कर्जदार है उनके बारे मे भी मे कोई प्रावधान होना चाहिए था।

Mr.Speaker: Dr. Sahib, you are snatching the time of other members. आप बाकी सब लिखवा कर भेज देना और वह हम रिकार्ड में लगा देगे। आप बैठ जाएं।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः .....

श्री अध्यक्षः इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। आप बैठ जाएं। ईश्वर सिह पलाका जी बोले। (इस समय माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह पलाका सदन में उपस्थित नहीं थे।) निर्मल सिंह जी आप बोले।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल): स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण मे इस सरकार की उपलब्धियो की चर्चा की गई है। मैं इनके हक मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मनमोहन सिंह जी, सोनिया गाधी जी और हरियाणा के मिनिस्टर्ज का धन्यवाद करूगा जिन्होने इस बारे में जबरदस्त वकालत की है। आज हिन्दुस्तान का और स्टेट का किसान इस बात कि लिए डिजर्व करता है और उसको इरा बात की जरूरत भी थी क्योकि वह इस देश की रीढ़ की हड्डी है तथा अन्नदाता है। अध्यक्ष महोदय, जहा अराऊंड दि वर्ल्ड मे गेहूं का उत्पादन घटा है वही हरियाणा मे खाद्यानो के भण्डारो की चिन्ता को ध्यान मे रखते हुये सरकार ने किसानो को प्रोत्साहन देने के लिये जो कर्ज मे माफी की है, मै उसका स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसकी शुरुआत हरियाणा मे कोआप्रेटिव हेंको के कर्जे और बिजली के बिलों की माफी से हुई है। हमे भविष्य मे भी किसानों का इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए क्योकि किसान की उपलब्धियो से ही हरियाणा की इकोनोमी और इतना बड़ा ढांचा

खडा है। इसके साथ ही गरीब लोगो के परिवार बढ चुके थे, उनके रहने की जगह कम हो रही थी। इस सरकार ने उनको 100 गज का प्लाट देने का काम किया है। इस सरकार का यह सराहनीय फैसला है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गरीब बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिये कि वे स्कूलों में जाए और उनकी आर्थिक हालत को देखते हुए लड़को को 100 रुपये प्रति महीना और लडकियों को 150 रुपये प्रति महीना छात्रवृत्ति देने का काम किया है। इसी तरह से पैशन के बारे में फैसला लिया गया है कि पैंशनर्ज की लिस्ट को हर साल रिव्यू किया जाएगा और हर साल उसमे नए पैंशनर्ज को ऐड भी किया जाएगा। इसी तरह से इस सरकार ने चौकीदारो की तनखाह लगाई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे कई हरिजन सरपंच रिजर्वेशन होने के बाद बनकर आए है उनको रख–रखाव के लिए 100 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है। यह हमारी सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की हर किस्म की जिन्स मे इजाफा किया गया है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र मे पहले पॉपुलर की खेती होती थी लेकिन पिछली सरकारो की वजह से किसानो ने उसकी खेती करना बंद कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के नजरिए का काम है कि इन्होने किसानो को पॉपुलर के उचित दाम दिए और आज फिर से किसान पॉपुलर की खेती करने मे लग गए हैं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में समान पानी के बटवारे की बात की गई है। इस बारे मे मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तरी हरियाणा मे भी दादूपूर नलवी नहर का

निर्माण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 1982 मे हमने इस बारे मे बात उठाई थी और इस पर बहुत राजनीति होने के बाद इसको मंजूरी भी मिल गई थी और इसको बनाने का ऐस्टीमेट उस समय 45 करोड रुपये के करीब आया था। लेकिन राजनीति के चलते हुए उस मंजूरी को वापिस ले लिया गया और जिन लोगो की जमीने ऐक्वायर की गई थी, उनको वापिस कर दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा सरकार ने आकर इस नहर को बनाने की इजाजत दे दी हे, यह इस सरकार की बहुत बडी अचीवमैट है। इससे किसानो को बहुत फायदा होगा। कुरुक्षेत्र में भी पानी का लैवल नीचे न चला जाए इसलिए इस नहर का बनना बहुत जरुरी था। इस नहर के बनने से उत्तरी हरियाणा मे भी लोगो को पानी का फायदा होगा, उसमे इजाफा होगा। मैं यह कहना चाहूगा कि वाटर लैवल मे कमी को देखते हुये बाध बनाने का प्रोविजन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन दे दिया है इसलिए मुझे आशा है कि यह जल्दी बनवाया जाएगा। स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण मे यह भी कहा गया है कि हथनीकुड से शहजादपुर तक यमुना के सरप्लस पानी को लेकर एक नहर बनायी जाएगी। इसके अलावा पूर्व वक्ताओ ने एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। स्टेट मे ऐजुकेशन का गिरता स्तर एक चिन्ता का विषय है। हमारे जो दसवीं, बीए. या एम. ए. पास बच्चे हैं आज वे एक छोटी सी दरखास्त लिखने के योग्य नहीं हैं। हमे इसका कारण ढूढना होगा। मैं समझता हूँ कि जो शिक्षित लोग हैं वे न तो इस बात के लिए डैडीकेटिड हैं और

न ही उनकी तैयारी है। जब हमारे अध्यापक खुद ही कुछ नहीं जानते तो वे बच्चो को क्या पढ़ाएंगे। शिक्षा का जो पढाने का तरीका है, उसको हमे पूर्ण रूप से बदलना पड़ेगा। चाहे हमें इसके लिए शिक्षक हायर करने पड़े। अगर हम शिक्षक हायर नहीं कर सकते तो फिर हमें अपने ही शिक्षकों को और ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। प्राईमरी तक तो बच्चो पर बर्डन नहीं होना चाहिए उनको केवल लैग्वेज सिखाना चाहिए। हमारे स्कूलों मे ग्रेडिंग सिस्टम लागू होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पता चल सके कि वे किस लाईन में जाना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा साईस या मैथस पढना चाहता है तो उसके लिए कालेज होने चाहिए। इसी तरह से टैक्नीकल ऐजुकेशन की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चो को रोजगार मिल सके। स्पीकर सर, इसी तरह से हेल्थ का मामला है। हरियाणा के जो स्कूली बच्चे है उनकी हैल्थ की तरफ भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। स्पीकर सर, मैं अपने गांव के स्कुल मे गया था। वहां पर मैंने पूछा कि दसवीं क्लास के बच्चे कहां हैं तो मुझे बताया गया कि वे सामने ही बैठे हुए हैं। मुझे यह देखकर बडा शॉक लगा कि दसवीं क्लास के बच्चे इतने कमजोर हैं। पहले तो स्कूलो मे पीटी. हुआ करती थी लेकिन अब वह गायब है। इसी तरह से पहले विधिवत रूप से टूर्नामैंट हुआ करते थे, लेकिन अब वे भी गायब हैं। अब तो बच्चे सिर्फ टीवी. या कम्प्यूटर पर ही बैठे रहते है जिसके कारण उनका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। पेरेटस को भी इस पर विचार करने की जरूरत है और सरकार को भी इस बारे मे सोचने

की जरूरत है कि कैरने हम सदेश पहुंचा सकते हैं कि हमारे बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाए। पहले तो स्कूली बच्चे थोड़ी डिसटैन्स के लिए पैदल या साईकिल से स्कुल चले जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है! अब साईकिल गायब हो गयी हैं। अब बच्चे या तो बस से स्कूल जाते हैं या उनके माँ–बाप उनको अपने स्कूटर से स्कूल छोड़कर आते हैं इसलिए यह चिन्ता की बात है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को भी चाहिए कि वह हर बच्चे की हैल्थ की फाईल बचपन से ही बनवाए ताकि यह पता चल सके कि किस बच्चे का उसकी उस के हिसाब से कितना डिवैल्पमैंट हो रहा है। मेरा कहना यह है कि इस मामले मे लोगों को वार्निंग दी जानी चाहिए। हमे इसकी तरफ ध्यान देना ही होगा और लोगो को शिक्षित करना होगा कि सीमित साधनो से कम खर्च करके कैसे वे अपने बच्चो को हैल्दी रख सकते हैं। स्पीकर सर, आज स्पोर्टस का स्तर प्रदेश में बहुत नीचे आया है। अब स्कूलों मे स्पोर्टस नहीं है। पहले तो पंचायतो के अच्छे टूर्नामैंट हुआ करते थे लेकिन इनमे अब पहले जैसा जोश और सेनक नहीं रही है। अब तो बस एक फार्मेलिटीज जैसी बात रह गयी है इसलिए इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा में अब भी बहुत से स्पोर्टसपर्सन पैदा हो सकते हें। रेलवे में या अन्य दूसरे महकमों मे स्पोर्टस का कोटा है। कई महकमो की बडी–बडी टीम है इसलिए अगर स्पोर्टस पर ध्यान दिया गया तो हमारे बहुत से बच्चो को इनमे चांस मिल सकता है। इसलिए हमारे यहा पर विशेष रूप से डिस्ट्रिकट लेवल पर स्पोर्टस के भी कालेज होने

चाहिएं। जिस तरह से राई मे स्पोर्टस का कालेज है वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कालेज होने चाहिएं।

श्री अध्यक्षः निर्मल सिंह जी, कैसे प्रदेशों की या देश की जो फाउंडेशन है, मजबूत हो, उसके बारे मे जो आपने डिटेल में बताया है, इससे बडा और कोई भाषण नहीं हो सकता। आपने बहुत ही विस्तार से इस बारे मे बताया है। Mange Ram Gupta Ji, kindly look into the speech delivered by Shri Nirmal Singh.

श्री मांगे राम गुप्ताः ठीक है जी।

श्री निर्मल सिंहः धन्यवाद सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया।

श्री ईश्वर सिंह पलाका (रादौर, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन मे किसानों की कर्ज माफी के बारे मे बहुत चर्चा हुई है। कर्ज माफी का मुद्दा बहुत जोर–शोर से उछाला गया है। स्पीकर सर, मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा लोगो को लाभ होने वाला नहीं है। स्पीकर सर, आज छोटे किसान की और गरीब मजदूर की हालत बड़ी खराब है। आज प्रदेश में बिजली और पानी की बहुत दिक्कत है। हर रोज लोग इकट्ठे हो कर दिन–प्रति दिन जाम लगा रहे है। हमारे

सदन के नेता माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जब काग्रेस की सरकार बनी, तब यह वायदा किया था कि तीन साल मे पूरी बिजली देगे। स्पीकर सर, आज कांग्रेस की सरकार बने हुए पूरे तीन साल हो गए हैं। लेकिन आज तक 24 घंटे बिजली तो दूर की बात है किसानो को गांवों मे 4 घंटे बिजली भी नहीं मिलती हे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दो साल मे पूरी बिजली देगे। दो साल मे यह नहीं पता कि कोन मुख्यमत्री होगा। शायद मुख्यमंत्री जी सच बोल रहे हों कि आने वाले दो साल में इनेलो का राज आ जाएगा और श्य घंटे बिजली मिलेगी। हर वर्ग को फायदा मिलेगा। (विघ्न) सपने देखना तो हमारा अधिकार है। आज मजदूर, किसान हर वर्ग बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचा रहा है। किसान को बिजाई के समय पूरी बिजली नहीं मिलती है। जब वह डी.ए. पी. खाद लेने जाता है तो उसके लिए उसको लाइन में लगना पडता है। हम कहते हैं कि किसान को उसकी फसल का अच्छा भाव दिया जाए। किसान समृद्ध और खुशहाल होगा तो सारा समाज खुशहाल होगा और समाज मे समानता आएगी लेकिन उसके साथ–साथ जो गरीब मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं जो बेचारे बेजमीन आदमी हैं उनके बारे में भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए और उनको सस्ता राशन मुहैया करवाना चाहिए ताकि वे समाज मे अपना पालन–पोषण ठीक ढंग से कर सकें। आज मंहगाई की वजह से इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया है कि गरीब आदमी को खाने के लाले पड रहे हैं। केन्द्र के बजट में महगाई को रोकने के लिए

कोई खास कदम नहीं उठाए गए है। जिन चीजो के भाव पिछले दिनों बढे हैं यदि आप परमीशन दे तो मैं उनके बारे मे बता देता हूं।

श्री अध्यक्षः आप लिखकर भिजवा देना।

13.00 बजे

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, सरसों के तेल का दाम 50 रुपये प्रति लीटर से बढकर 60 रुपये प्रति लीटर, रिफाइंड तेल का दाम 50–85 रुपये प्रति लीटर से बढकर 75 से 80 रुपये प्रति लीटर, मूंगफली के तेल का दाम 75–30 रुपये लीटर से बढकर 90–95 रुपये प्रति लीटर, आटे का रेट 15 रुपये किलो, दाल चना का रेट 40 रुपये किलो, काला चना 35 रुपये किलो, काबुली चना 40 रुपये किलो से बढ़कर 52 रुपये किलो, चीनी 15 रुपये से 17 रुपये किलो और परमल चावल 15 रुपये से बढकर 20 रुपये किलो व बासमती चाइल 30 रुपये से बढ़कर 50 रुपये किलो, वनस्पति घी 50 रुपये किलो से बढकर 80 रुपये किलो और देसी घी 150 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 160 रुपये किलो, अरहर दाल 40 रुपये किलो से बढ़कर 50 रुपये किलो और मूंग दाल 25 रुपये किलो से 32 रुपये किलो का रेट हो गया है। मसूर की दाल 40 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो, चायपत्ती 150 रुपये से 170 रुपये प्रति किलो, चाय पत्ती खुली 110 रुपये से 120 रुपये प्रति किलो और धनिया 50 रुपये से 60 रुपये प्रति किलो।

इस प्रकार और भी हजारो ऐसी चीजे है जिनके दाम आसमान को छू रहे है और आम आदमी इन चीजो को लेने मे असमर्थ है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से सरिये के दाम आसमान को छू रहे हैं। यह सब सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर आदमी को सुविधायें मुहैया कराये। हर आदमी को बिजली पानी मिले, रहने के लिए मकान मिले और हर हाथ को काम मिले। आज एस.ई. जैड के नाम पर किसानो की जमीन को औने पीने दामो में सरकार पूजीपतियो को देने मे लगी हुई हैं जिससे किसान जो उस जमीन पर मेहनत करने वाला है वह खत्म हो जाएगा और सारी जमीन पूजीपतियो के पास चली जायेगी। चुनाव के समय काग्रेस के सदस्य जब जनता के बीच में जाते हैं तो यह नारा देते हैं कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष पलाका साहब, आप गर्वनर एड्रैस पर बोले। आप कभी तो केन्द्रीय बजट पर बोलने लग जाते हूँ और कभी कहीं बोलने लग जाते हैं आप गवर्नर एड्रैस पर ही बोले।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं गवर्नर एड्रैस मे शिक्षा के बारे में कोई खास बात नजर नहीं आई। कांग्रेस सरकार के तीन साल के शासन मे मेरे हल्के के एक भी स्कूल का स्तर आठवीं से दसवीं तक नहीं बढ़ाया और न ही किसी पाचवी के स्कूल को आठवीं स्तर तक बढ़ाया गया। हम विपक्ष के सदस्यो का भी कोई अधिकार होगा, हम भी हरियाणा के लोग है।

श्री अध्यक्षः पलाका साहब, आप इस बारे में लिखकर भिजवा देना। गुप्ता जी काबिल मंत्री हैं। अगर वे स्कूल नार्म्स को पूरा करते होगे तो जरूर कसीडर करेगे।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने चाहिए। इसी प्रकार से स्पीकर सर, मेरे हल्के मे एक भी कन्या उच्च विद्यालय नहीं है। न तो बबैन मे और न ही रादौर मे। इसलिए लडकियो का स्कूल जरूर खोलना चाहिए।

श्री अध्यक्षः रादौर मे तो कालेज है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, मैं कन्या उच्च विद्यालय की बात दहर रहा हू। यदि लड़कियों का स्कूल अलग हो तो अच्छी बात है। अगर सरकार लडकियो का स्कुल अलग से खोल दे तो बहुत बढिया

श्री अध्यक्षः अगर नॉर्म्स पूरे करते होगे तो जरूर खोलेगे।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, आज महिलाओ की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। जो अनुसूचित जाति के बच्चो को वजीफे देने की बात कही गई है। स्पीकर सर, वजीफे तभी दे पायेगे जब अच्छी एजुकेशन दे पायेगे। स्कूलो में अध्यायक नहीं हैं, जिन स्कूलो में 5 अध्यापक जरूरी है वहा पर दो ही अध्यापक

स्कूल को चला रहे हैं। कई बार हमें अखबारों मे पढ़ने को मिलता है कि किसी स्कूल को अकेला गैस्ट टीचर ही चला रहा है।

श्री अध्यक्षः आपके नोटिस मे अगर कोई ऐसा केस है तो आप लिखकर भिजवा देना। अब आप कन्कलूड करे आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास के नाम पर बडे–बड़े दावे किए जाते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में कहीं विकास नजर नहीं आता। मेरे हल्के में विधायक बनने से आज तक तीन सालो मे सिर्फ 14 लाख रुपये विकास के नाम पर मिले हैं इसके अलावा कुछ नहीं मिला। (शोर एवं व्यवधान) जबकि दूसरे विधायको को 50–50 लाख रुपये तक मिले हैं। (शोर एव व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, आप भी विपक्ष में बैठते थे और मैं भी 1० साल तक विपक्ष मे बैठा करता था तो हमे एक नया पैसा भी रिवाडी ब्लॉक के लिए नही मिला था। इन्होने कम से कम माना तो सही कि इन्हे 14 लाख रुपये मिले हैं।

श्री अध्यक्षः आपने अपनें हल्के मे जो घोषणा की उस बारे में कभी आपने लिखकर दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, मैंने विधायक बनते ही अपने हल्के के कामों के लिये 55 लाख रुपये के

एस्टीमेटस भिजवाए थे, जब मैं इस बारे मे अधिकारियो से मिला तो उन्होने कहा कि आपकी फाइल सी.एम. साहब के पास अंडर कसीड्रेशन पड़ी है। मैंने पूछा कि उस पर विचार एक महीने में हो जाएगा, 3 महीने मे हो जाएगा या कब तक हो जाएगा? तो वे कहने लगे कि इस बारे मे तो हमे पता नहीं है तो इस तरह से अधिकारी आज भयमुक्त हैं। अधिकारी विधायकों का टैलीफोन सुनने के लिये तैयार नहीं होते। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपके हिसाब से अधिकारी भयभीत होने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर शिह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अधिकारियों को सरकार का डर तो होना ही चाहिए, सही काम के लिए तो अधिकारियो मे सरकार का डर होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) कोई विधायक फोन करे तो कहा जाता है कि अधिकारी व्यस्त हैं। दफ्तर में इतने क्या व्यस्त होते हैं कि एक मिनट फोन भी नहीं सुन सकते। इसलिए मै कहना चाहूंगा कि प्रशासन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः पलाका साहब, आप एक मिनट मे अपने हल्के की बात खत्म करे।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः इस सरकार ने आने से पहले अनेक किस्म के वायदे किए थे लेकिन सरकार ने आने के बाद

व्यापारियो के साथ धोखा किया है। सीलिंग ऐक्ट के नाम पर छोटे दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह सीलिंग ऐक्ट क्या है? (विघ्न)

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः प्रदेश सरकार ने सत्ता मे आने से पहले सभी युवाओ को रोजगार देने का वायदा किया था, विदेश में रोजगार दिलवाने का वायदा किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप अपने हल्के की बाते लिखवा कर भिजवा दें।

आई. जी. शेर सिंह (जुलाना)ः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं जब सन 2000 मे आप मेरे साथ विधानसभा मे मैम्बर बने उस समय इनकी सरकार हुआ करती थी और ये सत्ता पक्ष में बैठते थे और कहा करते थे कि आप भूल जाओं कि हम कहीं जाएंगे, आप कभी इधर नहीं आ सकते हैं। ये अब उधर विपक्ष मे जा चुके हैं। अब जिस तरीके से यहां कहा गया कि इनका रास्ता बाहर का है। अब ये लोकदल की सरकार कभी वापिस नहीं आएगी। ये अपने आप को किसानो की सरकार कहते थे।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आई. जी. शेर सिंह जी जो बात

कह रहे है वह ठीक कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री काल के दौरान बजट सैशन चल रहा था। मैं उधर बैठता था और चौटाला साहब सामने बैठते थे। मैं जो बात बता रहा हूं वह 9 मार्च के दिन की है। उस दिन चौटाला जी खडे होकर मुझ से पूछने लगे कि गुप्ता जी आज क्या तारीख है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान मे नहीं था कि वे मुझ से तारीख क्यो पूछ रहे हैं? मैंने उन्हे कहा कि आज 9 मार्च है। मेरे तारीख बताने के बाद चौटाला जी ने मुझे कहा कि गुप्ता जी आपने तो पब्लिक मीटिंग मे कहा था कि 9 मार्च तक चौटाला मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि उनके हालातो को देखते हुए मैंने किसी पब्लिक मीटिंग मे यह बात कही होगी कि 9 मार्च तक चौटाला जी मुख्यमंत्री नहीं रहेगे। उस दिन ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूरे सदन के सामने मुझे कहा कि आज 9 मार्च है और मैं मुख्यमत्री हूँ तथा जब तक जीऊंगा तब तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहूगा। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है। उसके बाद मैंने चौटाला जी को कहा कि मुख्यमत्री जी आप मेरी बात सुन लें, मैं हालात के अनुसार यह बात कह रहा हूं, ज्योतिष के मुताबिक नहीं कह रहा हूं कि यह टर्म तो आप पूरी कर लेंगे क्योकि विधायकों का बहुमत आपके साथ है। लेकिन अगले चुनावों मे आपकी हालत ऐसी होगी जिसके बारे मे आप सोच भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है आप विपक्ष के नेता भी नहीं बन पायेगे। अध्यक्ष महोदय, यह

रिकार्ड की बात है। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमत्री बनना तो दूर की बात है, आगे इनके 9 विधायक भी चुनकर नहीं आयेगे।

आई. जी. शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने बिलकुल ठीक बात कही हे, हम उसके साक्षी हैं। जो लोग अपने को किसानो के मसीहा कहा करते थे वे लोग जींद की धरती पर आकर नाचते थे। मौजूदा सदन मे तीन मंत्री और दो विधायक जींद से है उनको मालुम है कि वे लोग अपनी सरकार के समय में ऐसा नाच जींद की धरती पर नाचते थे कि अपने को किसानों का नेता कहने वाले लोग गोलियो से किसानो को भुनवाकर अपनी मौहब्बत दिखलाया करते थे। जिस क्षेत्र से हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वहां से 9 भाई शहीद हुए थे। जो लोग अपनी सरकार को किसानो की सरकार कहा करते थे वे अब जा चुके है, अब उनकी सरकार कभी नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था कि 'व्यय जवान, जय किसान''। इसमे कोई शंका की बात नहीं है कि वह नारा आज हमारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने सार्थक करके दिखाया है। केन्द्र की यू. पीए सरकार ने देश के किसानो की सुध ली है और 60 हजार करोड़ रुपये के किसानो के कर्जे माफ किए हैं। इसी तरह से जब हरियाणा प्रदेश मे हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारे सभी भाईयो की सरकार बनी उसने गांवो में रहने वाले गरीबों और किसान भाईयो के 1 हक करोड रुपये के बिजली के बिल माफ किए जिसके लिए उन्होने

किसी से कोई वायदा भी नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप गांवो में जाये और देखे चाहे कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं आज वे खुश हैं, जो लोग लोकदल का झण्डा उठाये फिरते थे वे भी आज कहते हैं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार किसानो के लिए अच्छे कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से पता चलता है कि सरकार की जो पौलिसीज हैं वे forward looking and people friendly है। हमारी सरकार ने जितना धन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश कि जनता के लिए रखा है उससे प्रतीत होता है कि हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है और हम सभी भाई 2005 मे हुडा साहब के नेतृत्व में प्रदेश मे जो कांग्रेस की सरकार बनी है उसे आम आदमी की सरकार कह सकते हैं। पहले जब केन्द्र मे एनडी.ए. की सरकार आई तो आपने देखा होगा कि उन्होंने सैनिको का सम्मान किस तरीके से किया था। वे लोग तो सैनिको के ताबूत तक बेच कर खा गये थे और जब हरियाणा में भी श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी उस समय पैरा मिलिटरी फोर्सिज के जो जवान शहीद हुआ करते थे उनको 2.50 लाख रुपये मिलते थे वह राशि भी उन्होंने देनी बंद कर दी थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने इस राशि को फिर से देना शुरू किया और इसलिए किया क्योंकि खुन सभी का एक जैसा होता है। हमारे सैनिक साथी देश की सीमाओं पर लड़ते हैं और देश की आतरिक सुरक्षा मे भी महत्यपूर्ण भूमिका

अदा करते हैं। ऐसा करते–करते वे शहीद भी हो जाते हैं उस स्थिति मे उनका पूरा सम्मान होना चाहिए और उनको अधिक से अधिक आर्थिक मदद मिलनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे किसान और मजदूर भाई खेतो मे दिन रात पसीना बहाकर काम करते हैं। सेना के जवान हमारे प्रहरी है और किसान–मजदूर भाई हमारा पेट भरते है। जब ये दोनो सुरक्षित हो तो देश का वातावरण अच्छा बन जाता है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश का वातावरण इस तरीके का बन चुका है कि यहा किसी भी वर्ग का कोई भी आदमी ठीक तरीके से रह सकता है और किसी भी तरह का कोई भी काम ठीक तरीक से भयमुक्त होकर कर सकता है। इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह जो हरियाणा ओर केन्द्र मे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई हे यह सभी वर्गो को साथ लेकर चलने वाली सरकारे हैं और पार्टीकुलरली जो लोग गांवो मे रहते हैं वे चाहे 75 प्रतिशत हो या उससे ज्यादा या उसके आस–पास, उनके कल्याण के प्रति राज्य और केन्द्र सरकार दोनों कटिबद्ध हैं कि किस प्रकार से उनकी सुरक्षा की जाये, किस तरीके से उनकी देखभाल की जाये और किसान की फसल के उत्पदान को किस तरीक से बढाया जाये। कृषि का उत्पादन दो तरीको से ही बढता है उसके लिए एक तरीका यह है कि किसान को पानी मिले और पानी तीन तरीको से मिलता है या तो बरसात हो वह कब होगी या नहीं उसके बारे मे कुछ नहीं कहा जा सकता। पानी उपलव्य कराने के लिए सरकार के हाथ मे 2 चीजे होती है कि पानी किस तरीके से उपलव्य कराया जाये। इसी सोच

के दृष्टिगत हमारी सरकार ने हमारे पास पानी के जो उपलव्य साधन हैं उनको सुव्यवस्थित करने के साथ–साथ न्यायोचित ढग से उसके समुचित बटवारे के लिए कारगर कदम उठाये और वह पानी हांसी– बुटाना नहर के माध्यम से हमारे किसान भाईयों को जिनमे दक्षिणी हरियाणा के किसान भाई भी शामिल हैं उन्हे जल्दी ही मिल जायेगा। ये जो लोग इस तरह की बाते कहते हैं कि इस नहर मे कभी भी पैक्चर के जरिए पानी नहीं आयेगा, वे वही लोग है जो चब उस तरफ बैठते थे तब कहते थे कि अब हम यहां आ गये है तो आप इस तरफ कभी भी नहीं आ सकते। मै उनको कहना चाहूंगा कि अब तो यहां से भी बाहर ही जाएगे। हमे पानी के लिए, कारखाने चलाने के लिए, घर की जरूरतो के लिए और अन्य लगभग सभी दैनिक जरूरतो के लिए बिजली की जरूरत होती है। बिजली से हम सिंचाई के लिए पानी भी निकाल सकते दै जो डीजल के मुकाबले में ज्यादा सस्ता पडता है। इसके लिए हमारी सरकार ने बिजली की अनेक परियोजनाओं पर कार्यवाही शुरू कर दी है जिन पर बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है। आप खेदड मे जाकर देखिए, आप यमुनानगर में जाकर देखिए और आप झाडली मे जाकर देखिए ये बिजली के कारखाने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयत्नों से ही लगाये जा सके हैं। अगर बिजली के ये कारखाने पिछली सरकार द्वारा लगवाये जाते तो बिजली की किल्लत की जिस मुसीबत का हमे आज सामना करना पड़ रहा है उसकी नौबत ही न आती। इस बारे मे हम इनको 2010 से पहले इन कारखानो में बिजली का उत्पादन होने

के बाद बता देगे। तो इस प्रकार की ये बातें हैं कि हरियाणा मे पूंजी निवेश किस प्रकार बढा और उस समय किस तरीके से अनेक ओद्योगिक घराने यहां से पलायन कर गये। यहां तक कि छोटे–छोटे जो राईश मिलरज थे वे भी यहां से पलायन करके पंजाब मे चले गये। मुझ से पहले इस बारे में अनेक माननीय सदस्यों द्वारा जिक्र किया जा चुका है। इस प्रकार का वातावरण उस समय था। आज ये लोग कह रहे है कि आज हरियाणा मे भय का वातावरण है क्योकि ये लोग भय के वातावरण में विश्वास रखते हैं। हम तो सभी वर्गों के साथ मिलकर काम करने और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने मे विश्वास करते हें।

Mr. Speaker: Now, please conclude I.G. Sahib.

आई. जी. शेर सिहः ठीक है स्पीकर रनर, मै दो चार बाते और कह कर अपनी बात समाप्त करता हू। स्पीकर सर, मेरा जो जुलाना हल्का है यह विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। वहां पर किसी जमाने मे एक ग्रोथ सैन्टर सैंक्शन हुआ था लेकिन उसको बाद मे शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उस पूर्व सैक्शंड ग्रोथ सैन्टर को वहा पर स्थापित किया जाये। जुलाना मे ही एक आई. सी.एल. फैक्ट्री है जोकि बन्द पड़ी है। यह फैक्ट्री पहले बन्द हो चुकी थी। पीनी में भी एक फैक्टरी बन्द पडी है। वहां पर काफी जमीन है और सरकार अगर प्रयास करे तो वहां पर भी कोई फैक्ट्री लगाई जा सकती है। इसके साथ मे 2– 3 नहले के बारे में

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। कुछ गाव ऐसे हैं जो पानी से बिलकुल वचिंत है न तो उनके पास जमीन के नीचे का पानी है और न ही नहर का पानी है। एक निडाना गांव है जो कई सालो से कोशिश कर रहा है जिसको लुदाना माईनर से जोड दिया जाये तो कई गांवो को इस पानी का फायदा होगा। इसी प्रकार से लजवाना गाव है जो कई सालो से कोशिश कर रहे है कि मेहरडा से भिवानी माईनर से एक छोटी सी सब माईनर निकाल दे तो तीन गांवों को इसका फायदा होगा क्योकि यह पूरा एरिया ड्राई पडा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया गया है। स्कूलों के बारे मे पूरे आकडे दिये गये हैं। मेरे हल्के मे भी कई स्कूल अपग्रेड किये गये है लेकिन 4– 5 स्कूल अब भी प्राईमरी स्कूल रह गये हैं जिनमे किशनपुरा, बीडवाली ढाणी, खेमा खेडी और भी दो तीन गांव है जिनके नाम मै लिख कर भिजवा दूंगा। शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि उनको भी अपग्रेड कर दिया जाये। पिछली सरकार के समय में तो कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ था। दो– चार रोडस के बारे मे भी मै कहना चाहूंगा। बीबीपुर से किनाना वाया बैहबलपुर जो कि किसानो की फसलो को मार्केट तक ले जाने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। पोखर खेडी से बीबीपुर, रामरा से बीबीपुर, ढाणी से रामगढ़, डिघाणा से कामकली, लजवाणा कला से करसौला, सामलो खुर्द से लजवाना के लिये, ये कुछ रोड हैं जो कि किसानो की फसलो को मडियो तक ले जाने में लाभदायक सिद्ध होगे। हॉस्पिटल के बारे मे मेरा कहना है कि जुलाना मे जो

सी एचसी. है वह बहुत जर्जर हालत मे हे। 2006 मे जब माननीय मुख्य मंत्री जी जुलाना गये थे उस समय उन्होने कहा था कि अगर आप लोग जमीन दे दो तो हम आपके हॉस्पिटल को नये तरीके से बनवा देगे। हमने साढे 4 एकड़ जमीन मुफ्त दे दी है, उस पर अगर हॉस्पिटल जल्द बना दिया जाये तो लोगो को उसका बहुत फायदा होगा।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हू। सबसे पहले ससार में पहली बार 60 हजार करोड़ रुपये के किसानो के कर्जे माफ करके किसानों को जो जीवन दान दिया है इसके लिए नै यू.पी.ए. सरकार को बधाई देता हूं। मैं सदन का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि इस बारे मे जो पहली बार आवाज उठाई गई वह आवाज भी हमारे हरियाणा प्रदेश मे उठाई गई, क्योकि हरियाणा किसानो के मामले मे हिन्दुस्तान मे प्रमुख स्थान रखता है, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। विशेष आर्थिक जोन के लिए राज्यो द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के ऐवज मे दी जाने वाली मुआवजा राशि 22 लाख रुपये प्रति एकड़ करके हरियाणा प्रदेश ने देश भर मे किसानो को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मात्र 3 साल पहले हरियाणा प्रदेश के अन्दर एक झूठी सरकार राज करती थी। मेरे गाव की एक हजार एकड़ जमीन ऐक्वायर की जा रही थी, उसमे मुआवजा राशि

2 लाख 60 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा था और आज उसी जमीन के भाव 22 लाख रुपये दिये जा रहे हैं इसके लिये भी हम हरियाणा सरकार और माननीय मुख्य मत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। आज उसी जमीन की मुआवजा राशि 22 लाख रुपये है। मैं इसके लिये सरकार का बहुत ही धन्यवादी हूं। मैं इसके लिये हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सरकार भविष्य मे भी ऐसे कार्य करती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही किसानों के जो कर्ज मुआफ किये गये हैं वह वहुत ही सराहनीय कार्य है। वे लोग जो लैंडलैस हैं, भूमिहीन भाई हैं और छोटे–मोटे धन्धे करके रोजमर्रा के कामों से अपनी आजीविका कमाते हैं जैसे रेहडी और पटरी पर बैठे हुए जो दुकानदार हैं उन भूमिहीन और लैंडलैस भाईयो ने भी छोटे–मोटे कर्जे ले रखे हैं। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे भाईयो के कर्जे मुआफ करने पर भी जरूर विचार किया जाए। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो यह बहुत ही बड़ा जनहित का कार्य होगा। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस विषय मे जरूर ध्यान दिया जाए। और इन लोगो की भलाई के लिए इनके कर्जे भी मुआफ किए जाएं। आज सोनीपत जिले के गन्नोर मे लगभग 500 एकड़ क्षेत्र पर सरकार एक विश्व स्तर की टर्मिनल मार्किट बनाने जा रही है इस पर भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। इस टर्मिनल मार्किट के बनने से मेरे वे छोटे भाई जो बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। स्पीकर

सर, पशुपालन संस्थान को बढ़ावा देने के लिए हिसार मे पशु विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है जो सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है इस पर भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। एसवाईएल. के माध्यम से नदियों की टेल पर हरियाणा के हिस्से का न्यायोचित शेयर देने के लिये भी सरकार ने अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। एस. वाई. एल. के पानी के पूरे उपयोग और जल का समान वितरण करने के लिये सिंचाई क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पहल की गई है। प्रदेश मे पानी की कमी वाले दक्षिणी क्षेत्रो मे पानी पहुंचाने के लिये भाखड़ा मेन लाईन को हांसी बुटाना ब्रांच से जोड़ने का कार्य जल्दी ही पूरा होने जा रहा है 2086 क्यूसिक क्षमता वाली 109 किलो मीटर लम्बी नहर जल संरक्षण और भूमिगत जलराशि को पुनर्निमित करने मे सहायक सिद्ध होगी। इसके लिये भी मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि यह एक ऐतिहासिक कार्य हरियाणा सरकार करने जा रही है। स्पीकर साहब, नहरी के कमाण्ड क्षेत्र में सभी खालों को पक्का करने की परियोजना पर भी तेजी से और सुचारू रूप से काम हो रहा है जोकि एक ऐतिहासिक काम है और किसान के हित मे है। इससे किसानो को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। स्पीकर सर, इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो मे आठ लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफ्त व्यक्तिगत पेयजल कनैक्शन्ज उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। इस स्कीम को अगले तीन वर्षो मे 340 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा। फरवरी, 2010 के अन्त तक 3.29 लाख परिवारो को कनैक्यान्ज

दिये जाएंगे। इसके लिए भी मैं हरियाणा सरकार और दरियादिल मुख्य मत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। स्पीकर सर, यमुना नगर में स्थापित की जा रही उक्त मेगावाट बिजली की दो इकाइयो में से पहली इकाई ने 13 नवम्बर, 2007 से कार्य करना शुरू कर दिया है तथा दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन मार्च, 2008 तक शुरू होने की सम्भावना है। इसी प्रकार से हिसार में खेदड मे 1200 मेगावाट के कोल बेस्ट राजीव गांधी थर्मल प्लांट का कार्य शुरू किया जा चुका है। इस प्लांट को वर्ष 2009–10 मे शुरू किये जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार से बिजली की कमी को पूरा करने के लिये हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के संयुक्त उद्यम से जिला झज्जर में झाडली के अन्दर 1500 मेगावाट क्षमता का प्लांट स्थापित करने जा रही है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए। आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिये बढाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री नरेश कुमार प्रधानः अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चलाई जा रही एक्टिविटीज मे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को बिजली के

कनैक्शन्ज देने के लिये कुल 242 करोड रुपये की लागत से कई स्कीमें लागू की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पड़ोसी साथी माननीय सदस्यो ने अपने सम्बोधन मे कहा था कि कांग्रेस की सरकार पैंशन बढ़ाने में हिचक कर रही है। उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने पैंशन दिल खोलकर दी है। चौकीदारो की तनखाह, सरपंच की तनखाह और नम्बरदार की तनखाह बढाई है। यहां तक कि हिजडो को भी तनखाह देने के बारे में विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं काग्रेस सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होने विकलांगो को हक रुपये प्रतिमाह पैंशन दी है। अध्यक्ष महोदय, अब कोई उस पैंशन को लेने नहीं जाता है तो उसमे सरकार का क्या दोष है। (विघन) अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि अगर उनको 600 रुपये पैशन कम लगती है तो वे हमारे दरियादिल मुख्यमंत्री जी से डिमाण्ड करें। ये हमारे जननायक मुख्यमंत्री है तो ये उनको लिखकर दे, हम भी इस पैंशन को बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बाते और कहना चाहूगा कि मेरे हल्के मे पासूर माईनर, झांगी माईनर और दूल्हेडा माईनर हैं अगर उनको खुदवाकर 8 और 10 नम्बर ड्रेन तक बदा दिया जाए तो इससे वहां के लोगो को बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, बादली में माजरी गांव है। वहां पर हमारे पड़ौसी भाई अपने कार्यकाल मे एक कालेज का नींव पत्थर रखकर आए थे। इन्होने उस समय कहा था कि यह कालेज एक साल मे बनकर तैयार हो जाएगा। इन्होने उस वक्त हमारे साथ बहुत बड़ा

खिलवाड़ किया था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां पर कुछ नहीं किया गया। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वहां के मजदूर भाईयो ने वहां पर चन्दा इक्टठा करके उस कालेज की बिल्डिंग को बनवाया है। आज वहां की संस्था से एफिलिएटिड कालेज चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस बिल्डिंग मे स्थाई कालेज खोला जाए।

श्री अध्यक्षः नरेश जी, आप अपनी बाकी बाते लिखकर दे देना। आप बैठ जाएं। अब श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा जी बोलेंगे।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा (मुंढाल खुर्द): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गवर्नर महोदय, के अभिभाषण पर बोलने की इजाजत दी इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हू। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस की प्रौसीडिग मे जितने भी सदस्य बोलें है उन्होने हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का किसानो के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ करने के लिए धन्यवाद किया है। आज देश के किसान यह महसूस करते हैं कि केन्द्र की सरकार में उनकी भी कोई सुध लेने वाला बैठा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे विरोधी भाई कहते हैं कि इसमे यह क्लीयर नहीं है कि किस के कर्जे माफ हुए हैं। Speaker Sir, in this regard technicalities and modalities will be worked out later but it is a fact that loan of farmers worth Rs. 60,000 cores

have been waived off by the UPA Government. इसके लिये मै प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह व हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में किसानो के लिए जो सबसे जरूरी बात है वह उनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की हे। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये हमारे मुख्यमत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हांसी बुटाना नहर का निर्माण शुरू किया है और जिस पर 350 करोड़ रुपये लगेगे और जल्दी ही यह बनकर तैयार हो जाएगी। इस बारे मे जितने भी डाउट्स रेज किये गए वह सब क्लीयर हो चुके हैं। यह डाउट्स लोगों मे भ्रांति पैदा करने के लिए रेज किए गए थे। स्पीकर सर, दूसरी बात मैं एस. वाई. एल. कैनाल के बारे मे कहना चाहूंगा। हालांकि यह मामला कोर्ट के मातहत अभी विचाराधीन हे लेकिन मौजूदा हालत मे हमे ज्यादा से ज्यादा पानी कैसे मिल सकता है इसके बारे में माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय मुख्यमत्री हुड्डा जी का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं। भाखडा कैनाल से जो मेन कैनाल पानी लेकर आगे जाती है उसकी क्षमता 10794 क्यूसिक्स है लेकिन सिल्डिंग की वजह से, गाद की वजह से यह कैनाल 9 हजार क्यूसिमर से ज्यादा पानी नहीं ले जा पा रही है। अगर इसकी डिसिल्टिंग अच्छी तरह से हो जाए और उसका रख–रखाव ठीक तरह से हो जाए तो मैं समझता हू कि हमे काफी मात्रा मे पानी मौजूदा हालात मे मिल सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान भी इस तरफ दिलाता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि काफी वर्षा के बाद हरियाणा प्रान्त ने उस कैनाल की डिसिल्डिंग

के ऐक्सपैंडीचर की पैमेट की है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि 21 मई से लेकर 21 सितम्बर तक भाखड़ा बाध का फिलिंग सीजन होता है इस सीजन के दौरान वाटर ऑन डिमांड मिलता है। यह मेरा सोचना है इसको वैरीफाई भी किया जा सकता है। इस दौरान जितना पानी आप चाहे भाखड़ा बांध से ले सकते हैं और वह पानी स्टोर भी कर सकते हैं। अगर हमें पानी की जरूरत नहीं है तो यह भी कहा जा सकता है कि बारिश हो गयी लेकिन जो लोग भिवानी जिले के या दक्षिणी हरियाणा के इलाके के हैं उन लोगो के इलाकों मे यह पानी दिया जाना चाहिए क्योकि इससे इन इलाकों मे वाटर लेवल०पर आ जाएगा जिसके कारण आगे चलकर हमें काफी पानी मिलेगा। मै इसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस बारे मे ध्यान दे। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब डिसिल्डिग रिपेयर का काम चल रहा हो तो इसकी मोनीटरिंग भी सही तरह से करवायी जानी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि मोनीटरिंग ठीक तरह से हो रही है या नहीं हो रही है क्योकि मेरी ऐसी इफोर्मेशन है कि डिसिल्डिग अच्छी तरह से नहीं होती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सालों के बाद हरियाणा प्रान्त की राशि रख–रखाव के लिए और डिसिल्टिग के लिए पहली बार दी है वरना पिछले दस सालो से एक भी पैसा इस काम के लिए नहीं दिया गया है। इस तरह से हम 21 मई और 21 सितम्बर के दौरान भाखड़ा सिस्टम से जो पानी ले सकते है वह आरडी. 160

और मेन कैनाल की आरडी. 390 से ले सकते हैं। आरडी. 150 वाला पानी जुई और भिवानी के एरियाज मे आ जाएगा और मेन कैनाल की आरडी. 390 वाला पानी हिसार, फतेहाबाद के एरियाज मे और सिवानी केनाल की तरफ चला जाएगा। मेरा इसके लिए माननीय मुख्यमत्री जी से आग्रह है कि इससे काफी राहत लोगों को मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय के अभिभाषण मे ट्रांसपोर्ट के बारे मे वर्णन नहीं है लेकिन 1966 से जब से हरियाणा बना था तब से चार पांच साल के अंदर ही हरियाणा प्रान्त ने अपनी पहचान सारे देश मे तो बनायी ही, पूरे ससार में भी हरियाणा प्रान्त का कई जगह वर्णन होता था और यह कहा जाता था कि हरियाणा एक ऐसा प्रान्त है जिसने बहुत तरक्की की है। अध्यक्ष महोदय, इस तरक्की के तीन चार कारण थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व मे हर गांव को बिजली दी गयी, हर गाव को सडक से जोड़ा गया, हर गांव को पीने का पानी दिया गया। इसके अलावा लिफ्ट इरीगेशन का प्रबन्ध करना और पर्यटन मे जबरदस्त विकास करना भी तरक्की करने के कारण थे। स्पीकर सर, इन सब बातों का नतीजा भी हमारे सामने आया है। मैं अब एक बात और पर्यटन के बारे मे कहना चाहूगा। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण मे पढा है कि शॉर्ट टर्म बेसिज पर और लौंग टर्म बेसिज पर पर्यटन केन्द्र लीज पर दिये जाएंगे ताकि उससे हमारे प्रान्त की तरक्की हो सके और रैवेन्यू भी आ सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां पहले पर्यटन मे हरियाणा बहुत आगे बढ़ा था। वही अब कहीं

न कहीं कोई ऐसी बात है जहां सुधार की जरूरत है। मैं यह बात आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि पिछले 40 सालो से जो चीजें बनी हुई हैं उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए इस बारे मे मैं कहता हूं कि इसको निजी क्षेत्र को देने की बजाय सरकार को स्वयं इस ओर ध्यान देना चाहिए और उसमे इमूवमैंट करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट मे एक बहुत बड़ी बात हुई है। 7 जनवरी, 2008 को गुड़गांव में रोड सेफ्टी वीक मनाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उदघाटन किया था, उसमे जो स्टैप्स उठाये गये थे ये कारगर साबित हो रहे हैं। अभी श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने बोलते हुए स्पोर्टस के बारे में कहा कि क्रिकेट ने दूसरे स्पोर्टस को निगल लिया है। इस बारे मे एक जो पुरानी कहावत है कि जलो मत रीस करो। यह कहावत इस बारे में चरितार्थ होती हे। 1977 मे भी एक स्पोर्टस मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि मै इस क्रिकेट को खत्म करना चाहूंगा। तब मैंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब क्रिकेट आपके घरो मे घुस जाएगा। वही बात सत्य हुई है। अब भी स्पोर्टस डिपार्टमैंट से मे यह बात कहता हूं कि इस क्रिकेट से सीख लेकर दूसरे स्पोर्टस को आगे बढाये। स्पीकर साहब, क्रिकेट दूसरे स्पोर्टस को निगल गया है, ऐसी बात कहना क्या अनुचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए दस मिनट का समय दिया था मैं औरों की तरह नहीं हूं इसलिए सिर्फ दस मिनट में ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा लेकिन एक प्वायंट अवश्य कहना चाहूंगा कि जैसे

मैंने रोड सेफ्टी वीक का जिक्र किया था। हरियाणा में ऐक्सीडैंट्स से साल मे 4100 डैथ्स होती हैं और रोजाना 11 आदमी मरते हैं जिनमे से 63.5 प्रतिशत पुरुष होते हैं इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस डैथ टोल की रोकथाम के लिये कदम उठाएं। सरकार ने जो हरियाणा हैवी रोड सेफ्टी पैट्रोल इस्टैब्लिश किया है। उसमें उस ट्रैफिक पुलिस स्टाफ को भी लगाया जाए। क्योकि उनको पर्याप्त इक्विपमैंट्स भी इस बारे में दिये गये हैं उनके पास ऐम्बूलैंस हैं, सेफ्टी राडार है इसलिए उनको भी इस काम मे लगाया जाए तो यह देश मे एक अग्रणी कदम होगा। इसके लिए जो 19 ट्रैफिक सैन्टर नेशनल हाइवे नम्बर 1, 2, 8, 10,22 पर स्थापित किए गए है और अभिभाषण मे कहा गया है कि 16 ट्रैफिक सैंटर और खोले जाएगे। 22 ट्रैफिक सैंटर वर्तमान में हैं और 16 और उनमे ऐड किए गए हैं। हरियाणा प्रान्त मे जो ऐक्सीडैंट्स होते हैं उनमे से ज्यादातर ऐक्सीडैंट्स ड्राइविंग ठीक न होने की वजह से होते हैं उस समस्या के हल के लिए ड्राइविंग सैंटर बहादुरगढ, कैथल और रोहतक मे खोले जा रहे हैं जो आगे जाकर इस दिशा मे मील का पत्थर साबित होगे। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 17th March, 2008.

***13.43 Hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 17th March, 2008).